हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार 15 मार्च, 1995

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एव उत्तर	(8)1
वाक आउट	(8)15
तारांकित प्रश्न एव गनर (पुनरारम्भ)	(8)16
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए ताराकिंत प्रश्नो के लिखित उत्तर	(8)19
राज्यपाल से सन्देश	(8)21
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा खाद्य एव आपूर्ति मन्त्री द्वारा लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा जाना	(8)21
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों नियम 84 के अधीन प्रस्तावो की	(8)22

सुचनाए	
मीडिया व्यक्तियो द्वारा प्रार्थना की गई सभी प्रार्टियों के एम ० एल ० एज ० की एक समिति के गठन सम्बन्धी मानना	(8) 24
(1) चौधरी बसी लाल द्वारा	(8)30
(2) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(8) 31
(3) चौधरी वीरेन्द्र सिंह द्वारा	(8)31
श्री कर्ण सिंह दलाल, एम ० एल० ए ० द्वारा श्री राम रतन, एम ० एल ० ए ० को धमकी देने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी मामला	(8) 32
वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)33
वाक आउट	(8)34
वर्ष 1995– 96 के वजट पर सामान्य चची (पुनरारम्भ)	(8)35
बैठक का समय बढ़ाना	(8)71
वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)72

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Pass Percentage of Results

***1024. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the percentage of the result of Middle Standard, Matric and 10+2 System Examinations of Government Schools, Government aided Private Schools and Non-Government aided Private Schools during the year 1993-94 in the State ;

(b) whether it is a fact that the result of the Government aided Private Schools and Non-Government aided Private Schools is higher than that of Government Schools in the State ; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps taken or proposed to be taken to streamline teaching system in order to improve the results of the Government Schools in the State ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) :

(a) (b) and(c) : The Information is laid on the Table of the House.

Information

(a) Percentage of the result is as follows :—

Examination Result (1993-94)

Level	Govt. Schools	Govt. aided Private Schools	Non-Govt. aided Private Schools
Middle	30.64	63.56	58.99
Matric	24.91	66.76	45.51
10+2	8.43	23.76	17.32

(b) Yes

(c) Reason for lower results in case of Govt. Schools are shortage of staff and curbing the menance of copying. The following steps have been taken to improve the results of Govt. Schools.

(i) Inspection of Schools has been made more intensive and extensive and a special campaign has been launched for inspecting maximum number of schools, especially those which have given less than 50% results.

(ii) System of monthly tests and quarterly examination has been introduced and the progress of the students would be communicated to the parents regularly.

(iii) Extensive in-service training programmes are being organised for the professional growth of teachers.

(iv) Class-wise syllabus has been distributed month-wise.

(v) The pattern of internal examinations of the Schools has been made uniform in order to prepare the child for the Board Examination. In order to introduce continuous and comprehensive evaluation, marks of half yearly Exam, held in Dec.—Jan., will be added in the Annual Examination

results.

प्रो० छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने मिडल, मैट्रिक और टैन प्लस टू की परीक्षाओं के रिजल्ट का जो विवरण दिया है, वह बहुत ही हृदय विदारक है। मंत्री महोदय ने गवर्नमैंट स्कूलों का रिजल्ट अच्छा न होने के कारण दर्शाए हैं कि गवर्नमैंट स्कूलों में स्टाफ की कमी है। यह तथ्यो से दूर की बात है। गवर्नमैंट ने नकल रोकने का मानसिक प्रयास किया है। गवर्नमैंट के पास तीन डी० पी ० आईज० हैं जोकि आई० ए ० एस० केडर के हैं, डी ० ई० ओज०, एस० डी ० ई० ओज० और इंस्पैक्टिंग स्टाफ है लेकिन इस्पैक्शन बिल्कुल न के बराबर है।

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, आप सवाल पूछें।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। इस प्रकार से हरियाणा वासियों के बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गवर्नमैंट स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिये कोई कारगर कदम उठाएगी ? इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन गवर्नमैंट स्कूलों मे रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, क्या उन स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई उपाय करेगी? जो अच्छा काम करने वाले टीचर्ज हैं, उनको कोई इनसैंटिव दिया जाएगा तथा जिन टीचर्ज का रिजल्ट खराब है, क्या उनको कोई पनिशमैट दी जाएगी ? जो रिजल्ट खराब आ रहा है, उसका कारण स्टाफ की कमी नहीं है बल्कि एजुकेशन डिपार्टमैंट में टीचर्ज की ट्रांसफर

पालिसी का नतीजा है। किसी टीचर का दिसम्बर के महीने में ट्रांसफर कर देते हैं और किसी का जनवरी में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या सरकार टीचर्ज की ट्रांसफर– की कोई ऐसी पालिसी बनाएगा ताकि टीचर्ज पूरे साल पढ़ाई की तरफ लग सकें?

श्री फूल चन्द मुलाना स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने तीन चार सप्लीमैंटरी पूछी हैं। इनकी पहली सप्लीमैंटरी का उत्तर यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं, वे मासिज को डील करते हैं। सरकारी स्कूलों में सभी दाखिला लेते हैं। प्राईवेट स्कूलों में स्टाफ भी अच्छा है और वे शहरी क्षेत्र में हैं। हमारे सरकारी स्कूल ढाणी, बस्ती और गांवों में है। जो हमारा समाज गांव में रहता है, वह ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं है और न ही वह खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। छतर सिह जी खुद शहर में रहते हैं और इसी वजह से इनके बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है। दूसरा कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे दाखिला लेते हैं, हम उन सभी की परीक्षा दिलाते हैं जबकि प्राईवेट स्कूल वाले जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, उनकी परीक्षा तो अपने स्कूल की तरफ से दिला देते हैं लेकिन कमजोर बच्चों की परीक्षा वे प्रईवेट कैंडीडेट के तोर पर दिलाते है, इसीलिए उनका रिजल्ट अच्छा आता है। कुछ कमियां हमारे स्कूलों में है, इनको मैंने माना है। एक तो हमारे पास स्टाफ की कमी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने जो नकल रोकी है, मुख्यमन्त्री जी के आशीर्वाद से इस में हम सफल भी हुए हैं, का भी रिजल्ट पर असर पड़ा है। मैं आप के माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि अभी 10+2 की परीक्षा समाप्त हुई है। हमारे

यहां पर आधा परसेंट के करीब ही नकल के केसिज पाये गए हैं। यानि 99.5 प्रतिशत पेपर फेयर हुए हैं। इन्होंने पूछा कि कदम क्या उठाये जा रहे हैं। सबसे बड़ा कदम तो नकल रोकने का है, जिससे बच्चों में भी और अध्यापकों में भी चेतना आई है। जहां पर हमारा रिजल्ट पहले 10 परसैंट था, बाद में सप्लीमैंटरी के दौरान वह) रिजल्ट 46 परसैन्ट तक बढ़ गया था और अब उसमे और अधिक इम्प्रूवमैंट होने जा रही है। एक बात इन्होंने यह पूछी कि जो अच्छे टीचर हैं, उनको ईनाम दिया जाये। मैं बताना चाहता हूं कि जो अच्छे टीचर है, उनको ईनाम भी दिया जा रहा है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिन स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत या कम रहा है, वहां पर इन्सपैक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो अच्छे टीचर हैं, उनको रिगार्ड दिया जा रहा है और जो ठीक तरह से नही पढ़ाते, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। एक सवाल इन्होंने ट्रांसफर पालिसी के बारे में पूछा। उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने कोई जनरल ट्रांसफर नहीं की और जनरल ट्रांसफर्ज अब भी नही होंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इन्होने नकल रोकने का मानसिक प्रयास किया है और जिसकी वजह से रिजल्ट पर असर पड़ा है। है पूछना चाहूंगा कि क्या नकल सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही रोकी गई? क्या प्राईवेट स्कूलों में खुली नकल हुई है? प्राईवेट स्कूलों में टीचर भी कम होते हैं, पे भी कम होती है और दूसरी सुविधाए भी कम होती है। इस सब के बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा रहता है और हमारे अध्यापकों का

अच्छा वेतनमान और उनकी अपेक्षा बहुत सी सुविधाएं लेते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे स्कूलों की प्राईमरी और मिडिल शिक्षा तो एक प्रकार से खत्म हो चुकी है। जब उनका बेसिक आधार ही खत्म हो गया, तो फिर हायर एजुकेशन में कैसे वे आगे आ सकेगे? मैं जानना चाहता हूं कि जिन स्कूलों मे 8 5 परसैन्ट रिजल्ट रहा है, उन स्कूलों का डायरैक्टोरेट में बैठे डी ० पी ० आई० और फील्ड में बैठे डी ० ई० ओ० व एस० डी ० ई० ओ० ने कितनी कितनी इन्सपैक्शन की है? ये इन्सपैक्शन की बजाये यहीं पर ए ० सी ० कमरों में ही बैठे रहते है। कृप्या बताए, जिनका रिजल्ट निम्न स्तर का रहा है, वहा पर कितनी कितनी इन्सपैक्शन की गई है? कितने हाई स्कूलो का डायरैक्टर आफ स्कूल एजुकेशन ने निरीक्षण किया है? कितने स्कूलों का डी ० ई० ओज० तथा बी ० ई० ओज० ने निरीक्षण किया है? अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में स्टुडैटस टीचर्ज की क्या रेशो है? प्राईवेट स्कूलों में स्टुडैंट्स टीचर्ज की क्या रेशों है? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि नकल रोक दी है, इसलिए रिजल्टस पर असर पड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो अभी दूर की बात है। माननीय मन्त्री जी क्या इन्सपैक्शन और रेशों के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी छत्तर सिंह जी को बताना चाहूंगा कि इस्तिहान प्राईवेट स्कूलों मे भी और सरकारी स्कूलों में भी होते हैं और

नकल भी दोनों जगहो पर होती है। ऐसा नही है कि सरकारी स्कूलों में ही नकल होती थी। नकल तो सारी जगहो पर होती थी। नकल के नाम पर सारे हरियाणा को बदनाम किया जा रहा था। स्कूलों मे नकल होती नहीं थी, बल्कि नकल करवाई जाती थी। इसमें सरकारी और प्राईवेट स्कूल दोनों शामिल रहे हैं। अब नकल में कमी आई है। अब तो केवल नाममात्र ही शायद रह गई है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल उन्होंने यह पूछा कि टीचर्ज और स्टुडैट्स की रेशो क्या है? प्राईवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलो मे टीचर और स्टुडैट की रेशो एक समान है। 40 स्टुडैंट्स पर एक टीचर की रेशो है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि स्कूलो में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए पिछले साल हुमने करीब साढ़े–पांच हजार टीचर्ज की भर्ती की थी और अब भी 3200 के करीब रिक्विजीशन हमने एस० एस०एस० बोर्ड या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी हुई है और स्टाफ की कमी को शीघ्र पूरा किया जाएगा। एक इन्होंने प्राईमरी स्कूल के स्ट्रक्चर को मजबूत कैसे किया जाएगा, यह सवाल पूछा है। इन्होंने कहा है कि अगर प्राईमरी स्कूल का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तो आगे कैसे इम्प्रूवमैंट लाएंगे? इनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूगा कि हर गांव में प्राईमरी स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन आगे भी हर साल हम 100 नये प्राईमरी स्कूल्ज गांवों में खोल रहे हैं। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयत्न से वर्ल्ड बैक के तहत 160 करोड़ रुपये मन्जूर हुए हैं, 4 जिले सिलैक्ट कर लिये गए हैं। अभी काम शुरू किया

गया है और 4 ऐसे जिलों को सिलैक्ट किया गया है, जहां पर महिला एजुकेशन की कमी है। प्राईमरी एजुकेशन का ढांचा वहां पर भी मजबूत किया जाना है। हमीर अधिकारी स्कूलों में इन्सपैक्शन के लिए जाते हैं। डायरैक्टर लैवल पर कई अधिकारियों को इन्सपैक्शन के लिए भेजा गया है उसके बाद डी० ई० ओज० तथा बी ० ई० ओज० के लैवल पर भी इन्सपैक्शन स्कूलो की की जा रही है। डायरैक्टर लैवल पर अभी 90 स्कूलो का इन्सपैक्शन किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्सनली भी कई स्कूलों को विजिट किया है। डायरैक्टर ने खुद कई स्क्लो को इन्सपैक्ट किया है। इस तरह से इन्सपैक्शन को पूरी तरह से स्ट्रैथन किया जा रहा है। दूसरे रिजल्टस को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्ज बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें, इस बात को देखा जा रहा है तथा मंथली टैस्ट भी होते है, क्वार्टरली टैस्ट भी होते हैं और फाईनल एग्जामिनेशन के अलावा दिसम्बर टैस्ट्स भी स्कूलों में लिए जा रहे हैं जिससे शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्त्री जी से जानना चाहूगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए क्या टीचर्ज के स्टैडर्ड को स्ट्रैथन करने की कोई कार्यवाही की गई है? मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते है कि टीचर्ज स्कूलो में कई गलत बातें भी करते हैं, हुक्का पीते है या ड्रिंक्स भी लेते हैं। क्या उनकी जानकारी में यह बात है कि कोई टीचर हुक्का पीते हुए स्कूल मे पकड़ा गया था? स्कूल में हुक्का पीने वाले या ड्रिंक करने वाले टीचर्ज को पकड कर सजा देनें या

स्कूल की नौकरी से हटाने बारे क्या कोई कार्यवाही की जाती है? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या शीशर खरबला हाई स्कूल में हैड मास्टर ने चार्ज लेते ही 2 लाख रुपये का गबन किया था? मैं यह बात इसलिए इनसे पूछ रहा हू कि इस बारे में लोग इनमे मिले थे और मामला इनके नोटिस में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह पूछना चाहूगा कि उस हैड मास्टर के खिलाफ महकमें ने क्या सोचा है और इस प्रकार की जो कुप्रथा है, इसको बन्द करने बारे मे महकमा क्या कर रहा है ?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय मक्कड़ जी ने पहला जो सवाल पूछा है, उसके बारे। में मै उन्हें बताना चाहूंगा कि टीचर्ज को एक्सट्रा ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर्ज की ट्रेनिंग इस प्रकार से दो तरह की हो जाती है। एक तो मास्टर लगने से पहले जे० बी ० टी ० या बी ० एड० की ट्रेनिंग तो होती ही है। उसके बाद सर्विस में आने के बाद टीचर्ज को इन–सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है तथा डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी उन को इन–सर्विस ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि उनके पड़ाने का स्तर ऊंचा हो सके और इस बारे मे भी हम दो सैन्टर खोलने जा रहे हैं। दूसरे, इन्होने कहा कि कोई मास्टर हुक्का पीते हुत पकड़ा गया था, तो उस बारे में हम ऐक्शन लेंगे। इन्हें सिफारिश करने की जरुरत नही है। (विध्न) तीसरा जो इन्होने सवाल पूछा है वह आगे भी आ रहा है। उस समय ही मैं इसका जवाब दे दूंगा।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसी भी स्कूल का अच्छा परीक्षा फल निकालने के लिए हैंड का होना आवश्यक है। जहां हाई स्कूल, 10 + 2 स्तर के स्कूल और प्राईमरी स्कूल्ज में प्रिसपिल्ज/हैड नहीं हैं, क्या सरकार इनको भरने की कोशिश करेगी, यदि हां तो यह पद कब तक भरे जाएंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी स्कूल प्रिंसीपल के बिना न रहे। इनको लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरैक्ट लगते हैं और दूसरे बाई परमोशन लगते हैं। परमोशन के लिए तो हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है और डायरैक्ट के लिए एस० एस० एस० बोर्ड को और पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजशिन भेज रखी है। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिकोमैंडेशन नही आई है। हमे आशा है कि हम इसे अगले सत्र तक पूरा भर पाएंगे।

श्री सूरज मल: अध्यक्ष महोदय, मैं बहादुरगढ़ की बात करता हूं कि वहां पर दो सौ के करीब प्राईवेट दुकानें स्कूल के नाम से खोल रखी है। वहां पर पढ़ाई नाम की कोई चीज नही है। वे बच्चों को मैट्रिक तक ऐसे ही धकेल देते हैं। यह सिर्फ बहादुरगढ़ में ही नहीं, बल्कि सारी स्टेट में हो सकता है। तो क्या सरकार के पास ऐसे कोई समाधान हैं जिससे यह सारी धांधली बन्द हो सके?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, हमने स्कूलो को रिकोग्नाईज करने का काम ऐजुकेशन डिपार्टमैंट को सौंप दिया है। इन्होंने जो बात बताई थी, उस बारे में मुख्यमन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम एक ऐसा ला बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रकार के स्कूली पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा।

Anganwari

***1030. Shri Krishan Lal :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether it is a fact that the functions of Anganwari in Madlauda Block, District Panipat has been entrusted to a private institution; if so, the reasons there of together with the name of said institution ?

Minister of State for Social Welfare (Capt. Ajay Singh) : Yes Sir. The Government of India has directed that one ICDS Project in the State should be implemented by a Voluntary agency. In accordance with these directions, Janta Kalyan Samiti, Rewari, a registered voluntary agency, has been entrusted with the Project.

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मती जी से पूछना चांहूगा कि मडलौडा ब्लाक में आगनवाड़ा स्कीम कब चालू की गई, जनता कल्याण समिति को कब सौंपी गई और कितने समय के लिए सौपी गई है? क्या इस ब्लाक के अलावा प्रदेश में यह स्कीम किसी और नए ब्लाक में भी सौंपी गई है? इस बारे में भी मंत्री जी पूरा ब्यौरा दें।

कैप्टन अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है, उसमें इन्टरव्यू हो चुके हैं और आगन बाड़ी के वर्कर्ज की सिलैक्शन हो चुकी है। उनकी ट्रेनिंग भी फरवरी में शुरू हो चुकी

है। यह ट्रेनिंग 2 मई, 1995 को खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, तीन ब्लाकस हैं उकलाना, भट्टूकलां और मडलौडा। इन तीनों में आगनवाड़ी स्कीम देने का विचार था। लेकिन एक ब्लाक को हमें यह देनी चाहिए थी, भटटू– कलां में पहले से ही आगनवाड़ी स्कीम चल रही थी और भारत सरकार के भी यह निर्देश थे कि अगर कोई स्वयं सेवा संस्था हो, तो उसको ही यह काम दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे राज्य में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। चूकि यह एक सामाजिक कार्य है, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए ही यह कार्य जनता कल्याण समिति को दे दिया गया है। मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके ब्लाक में भी यह योजना मई में सुचारू रूप से चालू हो जाएगी।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मती जी से पूछना चाहूंगा कि जनता कल्याण समिति रिवाड़ी को यह परियोजना कितने समय के लिए दी गयी है और इम पर खर्च कितना होगा तथा क्या इस परियोजना पर इन्वैस्टमैन्ट करने के लिए कल्याण समिति को पूरा पैसा खर्च करना होगा या फिर स्टेट गवर्नमैंट को भी इसमें पैसा खर्च करने के लिए देना होगा?

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई अवधि नहीं दी गयी है। अगर यह समिति इस कार्य को ठीक करती रहेगी तो समिति इस कार्य को चलाती रहेगी। इसके अलावा, इन्होंने यह भी सवाल किया कि इस पर कितना खर्चा होगा? अध्यक्ष महोदय, इस पर एक साल में 12.08

लाख रुपए खर्चा आएगा। कर्मचारियों को वेतन भत्ता डी ०ए० वगैरह भी इसी पैसे में आ जाएगा। लेकिन इस स्कीम में खाने का जो सामान देना होगा, उसको हमारी सरकार देगी यानि वे खुद सामान परचेज नहीं करेंगे। जो भी सामान और ब्लाकों मे दिया गया है, वही सामान इनको भी दिया जाएगा।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री बनी से जानना चाहूंगा कि जनता कल्याण समिति रिवाड़ी ने और कितने ब्लाकों मे यह स्कीम ली है तथा इस समिति ने जो कर्मचारी भर्ती किए हैं क्या वे टैम्पोरेरी तौर पर भर्ती किए हैं या परमानैन्ट तौर पर किए हैं? क्या सरकार इन कर्मचारियों को तनख्वाह देगी या फिर प्राईवेट समिति ही तनख्वाह देगी तथा सरकार ने किस बेसिज पर इस समिति को यह ब्लाक दिया है?

कैप्टन अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया है कि केवल एक ही ब्राक में यह हकीम इस समिति को दी गयी थी। इन संस्था में काफी स्कीम्ज हैं, जो भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं, जैसे प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि और भी बहुत सी 20–25 स्कीम्ज हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट हैं। इसके अलावा, मोशल ऐडवाइजरी बोर्ड की भी स्कीम्ज दी हुई हैं, जिनकी मेरे पास लिस्ट हैं। अगर आप कहे तो मैं इनको पढ कर बता सकता हूं लेकिन पढ्ने में काफी समय लगेगा।

चौधरी जिले सिंह जाखड: पढ्ने की जरूरत नहों है, यह बात ठीक है कि ये स्कीम तो भारत सरकार की ही है, लेकिन

मैं यह जानना चाहूंगा कि इन स्कीमों को लागू करने के लिए प्राईवेट समिति को देने का क्या क्राईटेरिया है?

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसका क्राईटेरिया कुछ नहीं होता। चार संस्थाएं इसके अंदर आयी थीं। ये संस्थाए हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, अखिल भारतीय महिला परिषद, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मैमोरियल ट्रस्ट और जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी। जो भी संस्था मैरिट में ऊपर आयी, उसको ही यह काम दिया गया।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः स्पीकर साहब, जो सरकारी कर्मचारी सोशल बैलफेयर विभाग के हैं, क्या वे यह स्कीम को लागू करने में सक्षम नही थे, प्राईवेट एजैसी को ही यह काम चलाने की इजाजत क्यों देनी पड़ा?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ठीक ही जबाव दिया है। भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को बार–बार कहा कि आपको किसी वालन्ट्री एजैंसी को मन यह काम देना चाहिए, तब हमने 1992 मे यह काम इस वालन्ट्री एजैसी को एक ब्लाक में दिया है। अगर आपके पास भी कोई और वालन्ट्री एजैंसी हो, और आप जिस ब्लाक का उसको काम दिलाना चाहें, तो बतायें। सरकार सबसे पहले उसको यह काम दे देगी क्योंकि यह तो एक सामाजिक सेवा का काम है। जो संस्था सम की सेवा करना चाह ती है और अपने पास से पैसा लगा कर बच्चों का जीवन सुधार करना चाहती है। तो बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास कोई इस तरह की संस्था है, तो

उसको हमारे पास भेजें। हम उसको और कोई ब्लाक इस काम के लिए दे देंगे।

Institution of Maharishi Balmiki Chair

***1029. Dr. Ram Parkash :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to institute the Maharishi Balmiki's Chair in any University of Haryana;

(b) if so, the name of the University together with the time by which it is likely to be instituted ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) :

(a & b) Yes, here is a proposal under consideration of the Government to institute Maharishi Balmikis Chair in Kurukshetra University of Haryana.

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, यह जो शुभ कार्य कर्नें का आश्वासन माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, उस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आदि कवि महर्षि बाल्मीकि के नाम पर जिस चेयर की स्थापना की जाएगी, वह टीचिंग–कम– रिसर्च के लिए होगी या केवल रिसर्च के लिए होगी और इसका क्षेत्र क्या होगा? दूसरे क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो नया एकैडैमिक सैशन जूलाई से प्रारभ होगा, उससे पहले सारी फौर्मलिटीज पूरी कर ली जाएं ताकि इस चेयर की स्थापना हो सके?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि माननीय मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने करनाल में 19– 10–94 को बाल्मीकि सभा में घोषणा की कि बाल्मीकि चेयर की स्थापना की जाएगी। उसी समय विभाग

ऐक्शन में आया और यूनिवर्सिटीज से ओप्शन मांग ली कि कौन इस चेयर की स्थापना करने के लिए तैयार है? डाक्टर साहब की इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र में शुरु हो। सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑफर दी। आदरणीय मुख्य मंत्री जी की ओर से केस अप्रूव करके तुरन्त फाइनैंस डिपार्टमैंट को भेज दिया गया है और मुझे आशा है कि बहुत जल्द इस पर कार्य शुरु हो जाएगा। जहां तक डाक्टर साहब ने पूछा है कि इस पर क्या कार्य होगा? अध्यक्ष महोदय, सारे समाज का जो दबा हुआ तबका शिडयूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास का है, उस पर शोध कार्य होगा और आदि कवि महर्षि बाल्मीकि, जो संस्कृत के बड़े भारी कवि थे, उनकी पोइट्रिक इन्टर–प्रैटेशन है, उस विषय पर भी पूरा शोध कार्य होगा।

Construction of Roads

***1046. Chaudhri Bharath Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from village Sajuma to Dubal and Guhna and from Singwal to Shimla of Distt. Kaithal; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed ?

Public Works Minister (Chaudhri Amar Singh) :

(a) No Sir.

(b) In view of (a) above question does not arise.

चौधरी भरथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सजूमा से गुना तक और सजूमा से

अल तक सड़क बनाने से सरकार को फायदा होगा क्योंकि इन सड़कों पर बसें चलने लगेगी, इसलिए ये सड़के बननी चाहिएं। इसके अलावा शिमला से सिंगवाल तक भी सड़क बनाने का सरकार का कब तक विचार है?

चौधरी अमर सिंहः स्पीकर सर, सजूमा से दुबल तक 7 किलोमीटर की सड़क है और निर्माण लागत 28 लाख रुपये है लेकिन गांव सजूमा पहले ही दोनो तरफ से मिला हुआ है और दुबल भी एक तरफ से मिला हुआ है। इसलिए यह सड़क बनाने का प्रावधान नही है। सजूमा से गुना तक यह 4.5 किलोमीटर की सड़क है और 43 लाख रुपये इस पर लागत आएगी क्योंकि बीच में एक ड्रेन पड़ती है, यह सड़क निर्माणाधीन है। इसके बनने से गांव गुना से किलायतपुर बिना लम्बे रास्ते के तय किए जा सकेंगे। इसी तरह सिंगवाल से शिमला, इस सड़क की लम्बाई 39 किलोमीटर है। गांव शिमला पहले ही नरवाना कैथल सडक से जुड़ा हुआ है और सिंगवाल–मंडी सड़क पर स्थित है। इस प्रकार यह सडक एक दोहरी सड़क है। इसको भी बनाने का कोई प्रावधान नही है। स्पीकर सर कलायत में कुल 153.65 किलोमीटर की लम्बाई की सड़क पड़ती है। इनका पैच–वर्क किया गया है और ये सड़कें बिल्कुल ठीक हैं। एक सड़क चौसाला से मटोर तक की 6.60 किलोमीटर लम्बी है। उस पर लगभग 24 लाख 13 हजार रुपये खर्च आने वाला है जिसमें से 5. 34 किलोमीटर सड़क पर काम चल रहा है और 1 किलो– मीटर सड़क पर अर्थ वर्क हो

गया है। इसलिये 15/8 तक यह सड़क बनाकर जनता के सुपुर्द कर दी जाएगी।

10.00 बजे

Case of Embezzlement

***1052. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any case of embezzlement in the School of village Sisar-Kharbala, Tehsil Hansi, District Hissar has come into the notice of Government during the year 1993-94 ; and

(b) if so, the total amount involved therein togetherwith the names of the officers/officials held responsible for the aforesaid embezzlement and the action taken against them ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना):

(क) जी हां।

(ख) श्री हरि सिंह, मुख्याध्यापक के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी हिसार द्वारा दर्ज करवाई गई एफ० आई० आर० के अनुसार स्कूल के फण्डों से 2,01,246. 21 पैसे की राशि अनियमित तौर पर निकलवाई गई तथा इस मुख्याध्यापक को राशि अनियमित तौर पर निकलवाने के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस स्टेशन नारनौंद में एफ० आई० आर ० दर्ज करवाई गई तथा इस मुख्याध्यापक को निलम्बित किया गया।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, एक हैडमास्टर को 3–11–93 को सस्पैन्ड किया गया और 18– 10–94 को उसको बहाल कर दिया। इस मास्टर ने केवल 15– 16 दिनो में

13–9–93 से 28–9– 93 तक 2 लाख रुपये का गबन किया था। क्या यही एजुकेशन का स्तर है? इस तरह से सरकारी कर्मचारी पैसे का गबन करके, उसका दुरुपयोग करते है और स्कूलों के कमरों के अन्दर बैठे शराब पीते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के कितने केसिज सरकार के नोटिस मे हैं? अगर इस प्रकार बच्चों के पैसो का गबन का मामला चलता हो रहेगा तो शिक्षा का क्या स्टैण्डर्ड होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? अगर इसी तरह मे फण्ड्ज का दुरुपयोग होता रहा ता शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा आएगा, शिक्षा का स्तर कैसे मर उठेगा? मैं सरकार मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के टीचर्ज जोकि पैसे ले ले कर रखे गये हों, क्या उनको इस तरह से खुला छोड़े रखेगी ताकि वे अपनी कमाई करते रहे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का हो सकता है। सरकार का यह फर्ज बनता है कि जब भी कभी कोई ऐसी बात उसके नोटिस में आये तो उस पर फौरन कार्यवाही की जाए। जब यह मामला हमारे नोटिस में आया हमने उसी वक्त उस अध्यापक को सस्पैन्ड किया और उसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करवायी 1 वह हैड मास्टर 3– 11–93 को सस्पैन्ड हुआ और 19–9–94 को बहाल हुआ लेकिन बहाल करने के बाद हमने उसको उस हक से वचिंत कर दिया और उससे डी ० डी ० ओ० की पावर्ज भी छीन लीं ताकि वह आगे से ऐसा काम न कर सके। श्री राम भजन जी शिक्षा के गिरते हुए स्तर सै बहुत चिंतित हैं। लेकिन ऐसी कोई बात

नहीं है। अगर हमें बच्चों की शिक्षा के बारे में चिन्ता है, तो हमें अध्यापकों से काम लेना ही होगा। कोर्ट के फैसले के अनुसार हम सस्पैंडिड व्यक्ति से काम नहीं ले सकते। केवल उसे तनख्वाह ही दे सकतै हैं। अगर कोई सस्पैन्ड होगा तो वह सरकारी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिये हमने उसको बहाल कर दिया और उसे बहुत दूर के स्कूल में लगा दिया ताकि वह पड़ाने का काम तो करता रहे। जब ऐसा कहीं केस नोटिस में आएगा तो उस पर अवश्य कार्यवाही भी होगी। केवल पढ़ाने के लिये उस अध्यापक को दूर के स्कूल में लगा दिया गया है लेकिन उसको यह हक नहीं होगा कि वह कोई पैसा ड्रा/खर्च कर सके। फिर इन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास इस तरह के कितने केसिज हैं। जो भी इस तरह के केसिज आते हैं, उन पर पूरी तरह से कार्य– वाही होती रहती है। विभाग में ऐसे केसिज पर अवश्य कार्यवाही की जाती है। ऐसे केसिज पर पूरी तरह से चौक हो, स्कूलो में हर प्रकार से कार्य ठीक से चले, तभी हमने इस तरह की इस्पैक्शन के कार्य को सुदृढ़ बनाया है और आगे से रैगुलर इंस्पैक्शन भी होगी। जो इररैगुलैरिटी होगी, उस के ऊपर कार्यवाही होगी।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी बारे में पहले भी पूछा था कि इस हैडमास्टर ने इस स्कूल से पहले भी क्या कहीं पर इतना ही गबन किया था? इसको सस्पैन्ड किया गया और एफ० आई० आर ० भी. उसके खिलाफ दर्ज है। इसके बाद आया उसको परमोट भी किया गया या नही या उसको हैडमास्टर ही रहने दिया गया या कि प्रिंसिपल बना दिया गया है? जो जांच

इस केस में चल रही है, क्या आगे उस पर कार्यवाही हो रही है या नही? लोगों ने वहां पर इसी रोष में उस स्कुल को ताला लगा रखा था। क्या ऐसे आदमी को परमोट तो नही कर दिया गया?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी सूचना नही है। हमारे यहां कुछ केसिज में भर्ती बाई परमोशन होती है और कुछ मे बाई डायरैक्ट रिक्रूटमैंट होती है। यह अध्यापक डायरैक्टली प्रिंसिपल सिलैक्ट हो गया था, पब्लिक सर्विस कमिशन से। लेकिन हनुने इसको प्रिंसिपल लगने नहीं दिया। वह केवल हैड मास्टर का कार्य कर रहा है। वह प्रिसिपल के तौर पर कार्य नहीं कर रहा है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1055

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी सूरज भाग काजल सदन मे उपस्थित नही थे।

Aucation of Land of Municipal Committee/Council, Palwal

***1073. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any land of Municipal Committee/Council of Palwal was auctioned in the year 1993-94; if so, the amount received therefrom ?

Minister of State for Local Government (Chaudhari Dharambir Gauba) : Municipal Committee/Municipal Council Palwal, had not auctioned any land during the financial year 1993-94 i.e. from 1-4-93 to 31-3-1994). Therefore, the question regarding amount received does not arise.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल पलवल की म्युनिसिपल कमेटी के बारे मे दिया था। मैंने सवाल में

लिखा था कि 1993 से ले कर 1994 तक क्या पलवल म्युनिसिपल कमेटी. की कोई जमीन बेची गई। माननीय मन्त्री महोदय ने सवाल को वर्ष 1993–94 का बना दिया। इसका मतलब तो यह निकलता है 1–4–93 से 31–3–94 तक। अध्यक्ष महोदय, वहां पर डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन बेची गई है। सरकार ने अपने ही बनाए हुए नियमों को ताक पर रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनके घरो के आगे प्लाट बना– बना कर जमीन बेची गई है। मैं आपके द्वारा सारे सदन को बताना चाहता हू कि पिछले साल भी मैंने यह सवाल किया था तो मन्त्री महोदय ने खड़े हो कर कहा था कि इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते, हमें समय दिया जाए। आज जब यह सवाल आया है तो इन्होंने साफ मना कर दिया है कि कोई जमीन नही बेची गई। मैं बताना चाहता हूं कि पलवल मे डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन बेची गई है। चौधरी देवी लाल के समय मे गुड़गांव मे एक करोड़ रुपए की कब जमीन बेची गई थी तो यहां हो–हल्ला मचा था। यह सरकार जान–बूझ कर इसको दबाना चाहती है। तो मैं जानना चाहता हू कि क्या मन्त्री. जी के नोटिस में यह बात है कि पलवल मे डेढ़ करोड़ रुपए की जमीन 1993 से दिसम्वर, 1994 तक बिकी. है या नही?

श्री अध्यक्षः क्या आप श्योर हैं कि आपका क्या क्वैश्चन था?

चौधरी धर्मबीर गाबाः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, वह यह हैः–

"Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any land of Municipal Committe./Council of Palwal was auctioned in the year 1993-94 ; if so, the amount received therefrom ?"

इसका जवाब मैंने क्लीयर कट दिया है। अब इन्होंने जो सप्लीमैंटरी पूछा है, उसका जवाब यह है कि वर्ष 1994–95 मे वहां पर 1 करोड़ 33 लाख 29 हजार तीन सौ निन्यानबे रुपए की जमीन नीलाम की गई है। वहां पर जो 79 प्लाट नीलाम किए गए हैं, उनमें चार प्लाट दलाल साहब के भी हैं। स्पीकर साहब, यह वही जमीन है जिस पर 30–40 साल से लोगों ने इन्क्रोचमैंट कर रखी थी। हमने उस इन्क्रोचमैंट को हटाया है। यदि वह जमीन वैसे ही पड़ा रहती तो फिर लोग उस पर दोबारा इन्कोचमैंट करते क्योंकि वह जमीन मकानों के बीच में है। उस जमीन के बारे मे यह फैसला हुआ कि उसको डी० सी० से परमिशन ले कर नीलाम किया जाए और डी ० सी ० से परमिशन ले कर एस० डी ० एम० ने वह जमींन नीलाम की है ताकि उस पर दोबारा इन्क्रोचमैंट न हो। वह जमीन म्युनिसिपल कमेटी के काम नही आ सकती। उस जमीन को डी ० सी ० से परमिशन ले कर 1 करोड़ 33 लाख 29 हजार 399/– रुपये में नीलाम किया गया है। वह सारा पैसा पलवल म्युनिसिपल परिषद के अन्दर डिवैल्पमैंट पर खर्च किया गया है। वहां पर इतनी जबरदस्त डिवैल्पमैंट हुई है, अगर आप कहें, तो मैं उसकी डिटेल बता सकता हू। वहां पर डिवैल्पमैंट पर 1 करोड़ 46 लाख 53 हजार 891/– रुपए खर्च किए गए हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने यह कहा है कि वहां पर मैंने चार प्लाट लिए हैं तो क्या मंत्री जी यह बंताएगे कि मेरे नाम से वहां पर कौन– कौन से प्लाट्स हैं? क्या मैंने वह प्लाट बोली लगा कर लिए है या किस तरीकें से लिए है? एस० डी ० एम० ने अपने घर मे बैठ त्हर उन प्लाटों को नीलाम किया है। मली महोदय ने कहा है कि वह जमीन डी ० सी ० से परमिशन ले कर नीलाम की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा राज्य के जो कानून है, वे इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई भी एस० डी० एम ० इस तरह से जमीन कौ नीलाम कर सकता है? इस हरियाणा प्रदेश में पता नही कितने लोगो ने म्युनिसिपल कमेटीज की जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हुए है। मैं यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार सभी. म्युनिसिपल कमेटीज मे जिन–जिन लोगों ने जमी नो पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनको पलवल म्युनिसिपल कमेटी की तरह हटा कर नीलाम किया जाएगा ?

चौधरी धर्मवीर गाबाः स्पीकर साहब, केवल पलवल म्युनिसिपल कमेटी की ही बात नहीं है, जहां जहां पर भी नाजायज कब्जे हैं और जो जमीन म्युनिसिपल कमेटी के काम नही आ सकती उन जमीनों को कब्जे में ले कर नीलाम करने का हमारा प्रयास जारी है। वह थोड़ी–थोड़ी जमीन है, जिस पर न कोई सरकारी बिल्डिग बन सकती है और न ही कोई कम्पलैक्स बन सकता है।

श्री कर्ण सिंह दलालः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जमीन डायरैक्टर की परमिशन ले कर नीलाम की गई है?

श्री अध्यक्षः आपका मेन लिखा हुआ क्वैश्चन यह है –

"Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—has any land of Municipal Committee/ Council, Palwal been auctioned in the year 1993-94 if so"

तो मंत्री जी ने 1–4– 93 से 3 1–3. 94 तक का आपको जवाब दै दिया।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैंने मूल रूप में जो सवाल लिख कर आपके यहां दिया था, वह अपने हाथ से लिख कर दिया था। आप वह मंगवा कर देख

श्री अध्यक्षः उसमें आपने यही तो लिखा था।

Chaudhri Dharambir Gauba : Under the Haryana Municipalities Management of Municipal Properties and State Properties Rules, 1976, the permission of the D.C. was obtained by S.D.M.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, डी ० सी ० और एस० डी ० एम० ने पैसा खाया है। उस जमीन कौ नीलाम करने के लिए राज्य सरकार से कोई परमिशन नही ली गई।

चौधरी धर्मबीर गाबाः स्पीकर साहब, जिसके बारे में डी ० सी ० परमिशन देने के लिए कम्पीटैट हैं, उसकी डायरैक्टर से क्यों परमिशन लेंगे? Under the Haryana Municipalities Management of Municipal Properties and State Properties rules, 1976 the permission of the D.C. is to be obtained and not of the Director.

श्री राम रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हू कि कर्ण सिंह दलाल ने मार्किट कमेटी पलवल की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह कब तक खाली करवा ली जाएगी? इसी प्रकार से कर्ण सिंह दलाल ने गांधी समुदाय की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह कब तक खाली करवा ली जायेगी? इसके अलावा कर्ण सिंह दलाल ने जितने कब्जे कर रखे है व जिन पर दुकानें बना रखी है, कब तक खाली करवा ली जायेगी? (शोर)

Mr. Speaker : Next question please

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, ये बे–बुनियाद बात कह रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब मंत्री जी की तरफ से नही आ रहा। यदि सरकार मेरे सवाल का जवाब नहीं देती और आप हमे और सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत नही देते तो हम विरोध स्वरूप वाक–काउट करते हैं।

(इस समय विपक्ष के सदस्य सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल, छतर सिंह चौहान तथा राम भजन अग्रवाल सदन से वाक–आउट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Dowry case in Rohtak

***1090. Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of dowry cases registered in Civil Lines Police Station, Rohtak, during the month of June, 1994 togetherwith the action taken thereon ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): दो मुकदमें दर्ज हुए। धारा 304–बी /498– ए भा ० द० स० और 406/498–ए भा ० द० स ० के अन्तर्गत एक–एक मुकदमा दर्ज किया गया। इन दोनों मुकदमों का चालान न्यायालय में दिया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुकदमा नं ० 237 दिंनाक 12–6– 94 अडर सैक्शन 304–बी/ 498–ए आई०पी ०सी ० में, क्या मुख्य मन्त्री के आदेश पर क्राईम ब्राच के इन्सपैक्टर चमन लाल री–इन्वैस्टीगेशन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसकीं प्रोग्रेस क्या है? क्या यह भी सही है कि इस केस में इर्म्पोटैट ऐवीडैंस श्री धर्मचन्द के बयान की ओडियो कैसेट तथा मृतका के पिता करतार सिह का जो पूरक बयान है, उसको इग्नोर कर दिया है? क्या यह सही नही कि मरने वाली पूनम डाउरी के केस के कारण तो नहीं मरी? दूसरे मैं बताना चाहूंगा कि इस केस में धारा 406 लगनी चाहिए थी, वह नही लगायी गई। जरा मुख्य मन्त्री महोदय क्या इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस मरने वाली लड़की ने छत से छलांग लगा कर खुदकशी की है। उसने एक चिट्ठी. लिखकर छोड़ा थी। उस चिट्ठी के मुताबिक उसके पति, देवर, ससुर का कोई जिक्र नही था। सिर्फ यह लिखा था कि उसकी सास उसे तंग करती थी, इसलिए वह खुदकशी कर रही. है। इसीलिए उसकी सास के खिलाफ केस दर्ज किया गया और

चालान किया गया। बाद में लड़की के पिता ने एक एप्लीकेशन दी कि इसमें इसके पति को, ससुर को और ननद व देवर को भी गिरफ्तार किया जाये। इसकी जांच की गई लेकिन जांच में डी०एस०पी० और एडीशनल एस०पी० की रिपोर्ट से यही निष्कर्ष निकला कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी इस केस की इन्कवायरी चल रही है। यह इन्कवायरी हमारा जो क्राईम ब्रांच का स्पैशल स्टाफ है, उस द्वारा की जा रही है। अभी इस केस में वारसान (लड़की के पिता) की तसल्ली नही हुई है, इसलिए इस केस की कोर्ट से इजाजत लेकर दुबारा इन्क्वायरी करने की परमिशन 11/94 मे ले ली गई है। जांच अभी चल रही है। इतना ही नहीं, हमने इस केस में धारा 406 भी लगा दी है और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सप्लीमैंटरी चालान पेश किया जाएगा।

Sale of Lottery Tickets

***1092. Prof. Sampat Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount received from the Sale of State run Lottery tickets during the year 1994-95 togetherwith the profit earned therefrom during the said period ?

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) :

Total sale proceeds of lottery tickets during
1993-95 upto 28-2-1995 Rs. 2789.91 Crores

Estimated profit upto 28-2-1995 Rs. 73.89 Crores

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री श्री गुप्ता जी ने जो फिगर्ज दी हैं, वे काफी अलार्मिंग फिगर्ज हैं। इन्होंने बताया है कि 2789.91 करोड़ रुपये के टिकट बिके और आमदनी केवल 73.89 करोड़ रुपये हुई। अध्यक्ष महोदय, लाटरी आम आदमी खरीदता है। इस साल का अभी एक महीना और रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से जानना चाहूगा कि 2789.91 करोड़ रुपये में कुल बैनिफिट 73.89 करोड़ रुपये हुआ है। बाकी के जो बैनिफिशरीज हैं, वे कौन लोग हैं और इतनी एमाउट किसको किस काम के लिए दी गई है? स्पीकर सर, इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि लाटरी की जो टिकटें छपती हैं, क्या उनको छपवाने के लिए सरकार ने कोई टैडर इन्वाईट किया था और अगर टैडर इन्वाईट किया था तो क्या जिसने कम से कम रेट दिया या उगे को ही छपाई का काम दिया गया था किसी अन्य व्यक्ति से ये टिकटें छपवाई गई हैं? स्पीकर सर, इसके साथ ही एक और सवाल मैं माननीय मांगें राम गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी अपनी प्रिंटिंग प्रैस है, तो प्राईवेट लोगों से ये छपाई क्यों करवाई जा रही है और आप इन टिकटों की छपाई अपनी प्रैस में क्यों नही करवाते?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी बहुत ही समझदार आदमी है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोगों की दिक्कत को समझते हुए या इसको एक सामाजिक बुराई समझो हुए सरकार ने पहले ही लाटरी को बन्द करने का फैसला ले लिया है। दूसरे स्पीकर सर, मैं इनको यह बताना चाहता है कि लाटरी

की स्कीम आज की वर्तमान सरकार ओं नहीं चलाई थी, 1968 मे हरियाणा में लाटरी स्कीम चल रही है और सभी सरकारों के वक्त में रही। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार रही हो, चाहे चौधरी भजन लान जे। के। सरकार रही, या दूसरी सरकारे रखी लाटरी की स्कीम चलती रही। यह स्कीम जिस तरी के से पहले से चल रही थी और जैसे टिकटें छाती और बिकती थीं, हमने उसमें कोई चेंज नहीं की। अध्यक्ष महोदय, यहां पर हन्डेने यह कहा कि इतनी टिकटें छपी और फायदा कम हुया। अध्यक्ष महोदय, ये समझदार आदमी हुँ और इनको पता भी है कि 20 रुपये की टिकटों के ब्लाक में से 18 रुपये तो टिकट खरीदने वाले को ही मिलते हैं सिर्फ 2 या अढ़ाई परसैटं, प्रैस का खर्च, हमारे सारे खर्च वेजिज वगैरा निकाल कर जो बचता है, वह प्रोफिट है। यह दो या अढ़ाई परसैट को रायल्टी मान ले या कमीशन कह लें (विध्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही में चौधरी सम्पत सिह जी को यह भी बताना चाहूंगा कि इनके समय में जो टिकटों की छपाई होती थी, उस रेट से कम रेट पर हम टिकटें छपवा रहे है हलांकि उसके बाद कागज के रेट्स भी बढे हैं और वेजिज भी ज्यादा देने पड़ रही हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे यह जानना चाहा था कि क्या छपाई के लिए इन्होंने टैंडर काल किये थे या कि नही? अब अगली छपाई के लिए कोई और टैंडर काल किया गया है या कि नही?

श्री मांगे राम गुप्ता: जब हमने लाटरी बन्द करने का फैसला ले लिया है, तो फिर टैंडर काल करने की क्या आवश्यकता है? बाकी जो पहले टैडर की बात है, उसके बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि इन्होंने खुद क्या रेट्स दिए थे (विघ्न) स्पीकर सर, यह रिकार्ड की बात है। मैं इनकी जानकारी के लिए इन्हे बताना चाहूंगा कि जिन रेट्स पर इन्होंने टैंडर एक्सैप्ट किया था, उसके बाद हालांकि कागज की कीमतें बढ़ी हैं, और वेजिज भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन रेट्स से हमने कम रेट्स पर छपवाई करवाई है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इनके राज में 1987– 88 मे टोटल इन्कम 38. 71 करोड़ रुपये हुई थी और खर्च जो हुआ था वह 35. 43 करोड़ रुपये हुआ था। सिर्फ 3 करोड़ रुपये बचत सरकार को हुई। 1988– 89 में 69.73 करोड़ रुपये की सेल हुई और खर्चा हुआ 62.56 करोड़ रुपये और इसमें इन्कम हुई 7.17 करोड़ रुपये की। 1 989–90 में सेल हुई 103 करोड़ रुपए की और खर्चा आया 93 करोड़ रुपये का, इसमें इन्कम 10 करोड़ रुपये की हुई। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बहुत बड़ी डिटेल दी है। अब मैं इनकी बात पर ही सवाल पूछ रहा हूं। इन्होने जो फिगर्ज दी हैं, वह ठीक ही दी होंगी। अध्यक्ष महोदय, 38 करोड़ में से 35 करोड़ का खर्चा आया और उसमें से 3 करोड़ बच गए। इसका मतलब यह हुआ कि 9 प्रतिशत प्रोफिट

हुआ। अगर हम 2789 करोड़ रुपए का 9 प्रतिशत लगाएं तो तकरीबन यह 260 करोड़ बनता है। उस रेशो के हिसाब से टोटल एम्बैजलमैट पौने दो सौ करोड़ रुपए की बनती है। अब ये बताए कि वह पैसा किसको दिया? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बताए कि यह पैसा कहां गया?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहता है कि इनके टाईम में 10 टिकटों का ब्लाक 20 रुपए का था और ये वापिस 16 रुपए देते थे। हमने इसको इम्प्रूव किया है कि जो भी ब्लाक खरीदेगा, उसको 18 रुपए दिए जाएंगे और जो ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहां गया है तो यह जो हम 18 रुपए देते हैं, वहां पर गया है।

Prof. Sampat Singh : I am saying nearly 9%. It will be 8%. It means that the amount has been paid to the commission agents..

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह कमीशन एजेंट नही हैं। जो भी टिकटों का ब्लाक खरीदता है, हम उसको 18 रुपए देते है। ये तो अपने टाईम में 16 रुपए ही देते थे। हमने तो इनसे 2 रुपए ज्यादा दिए हैं और इस वजह से हमारी सेल भी बढी है।

प्रो ० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप भी इस मामले को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। गुप्ता जी ने फरमाया कि बेचने वाले को प्रोफिट देते हैं लेकिन जो गरीब आदमी दिन भर टिकट खरीदने में लगा रहता है, उसको क्या प्रोफिट दिया है? उसको

सुसाईड जैसा प्रोफिट दिया है। ये 75 करोड़ रुपए कमाने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता: हमने किसी भी एजेन्ट को कमीशन नही दिया है। जिसने भी 20 रुपए की टिकटों का ब्लाक खरीदा है, उसका 18 रुपए वापिस दिए हे। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए ताराँकित प्रश्नों के लिखत उत्तर

Rejected Coal

***1105. Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the yearwise total quantity of Coal purchased by the Thermal Power Plant, Panipat during the year 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1993-94 and 1994-95 ; and

(b) the total quantity of Coal, if any rejected out of the Coal as referred to above togetherwith the criteria adopted for the rejection of Coal ?

Power Minister (Shri Veiender Singh) : A statement is laid on the table of the House.

"STATEMENT"

(a) The yearwise quantity of coal purchased for Panipat Thermal Power Station was as follows

Year	Quantity purchased (Lac Tonnes)
1987-88	11.52
1988-89	11.64
1989-90	15.15

1993-94	16.78
1994-95 (Upto 12/94)	12.88

(b) No rejection of received coal is made except for visible stones and boulders which are removed. However, the coal grinding mills reject some quantity of poor grage coal and stones etc. The yearwise details of coal rejected by mills is as follows :—

Year	Quantity rejected
1987-88	21,126
1988-89	24,216
1989-90	40,625
1993-94	85,166
1994-95 (Upto 12/94)	62,093

Construction of Road

***1168. Sardar Jaswinder Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from village Adhoya to Kraha Saheb of district Kurukshetra: if so, the number of culverts proposed to be constructed on the said road ?

Public Works Minister (Chaudhri Amar Singh) : Yes Sir, 16 Nos. culverts are under construction.

Damaged Road

***1174. Shri Daryao Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the time by which the damaged road from village Ahari to Kulana is likely to be repaired ?

Public Works Minister (Chaudhri Amar Singh) : Patch work (repair) on the road from Ahari to Kulana has been done.

राज्यपाल से सन्देश

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a letter from the Governor, which reads as under :—

"Thank you so much for your communication No. HVS-LA-36/95/4659, dated 10th March, 1995, sending therewith a copy of the 'Motion of Thanks' on my address passed by Haryana Vidhan Sabha on 10th March, 1995."

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री द्वारा लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा जाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 25, given notice by Shri Ram Bilas Sharma, regarding the non-availability of kerosene oil and wheat on ration shops and black-marketing of these items. I admit it. Shri Ram Bilas Sharma may read his notice.

(As Shri Ram Bilas Sharma was not present in the House, the notice of motion was not read)

खाद्य एवं आपूर्ति मंन्त्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिह): अध्यक्ष महोदय, माननी व सदस्य राम बिलास जी तो इस समय कसी कारणवश हाउस में उपस्थित न ही हैं लेकिन आपने उनकी मोशन ऐडमिट कर ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाउस की जानकारी के लए इस मोशन का जवाब दे सकता हूं। मेरे पास यह लिखित में स्टेटमैंट है।

श्री अध्यक्षः आप इस स्टेटमैंट को हाउस की टेबल पर रख दें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः ठीक है जी मैं रख देता हूं।

Sir, With your permission, I beg to lay on the Table —

A copy of statement* in respect of Calling Attention Notice No. 25, given notice of by Shri Ram Bilas Sharma, regarding non- availability of kerosene oil and wheat on ration card-shops and black marketing in the State.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैंने और मेरी पार्टी के सभी एम०एल०एज० ने एक कालिंग अटैन्शन मोशन दी है जिसमें हमने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की जमीनो के आक्शन के आर्डर हो चुके हैं। नारनौल और रिवाड़ी के दी ०सीज० की कोठी, दफ्तर, ऐक्सियन के दफ्तर और रैर्जाडैस तथा नारनौल कैनाल रैस्ट हाऊस के आक्शन के आर्डर हो चुके हैं। किसानो को जो दो करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया है, उसके बदले में यह आर्डर हुए हैं। इसका मतलब फाईनैशियल काईसिज है।

श्री अध्यक्षः आपका यह मोशन अभी अंडर कसीड्रेशन है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः सर मेरा भी एक कालिंग अटैशन मोशन था जो कि मैंने 9 तारीख को दिया था। यह मोशन पानीपत थर्मल पावर प्लांट के आस– पास के गांव जैसे खुखराड़ा,

आसनकला, सकलाना खुर्द और जाटल आदि, मैं बड़ा भारी जो प्रदूषण फैल रहा है, के बारे में है।

श्री अध्यक्षः आपका यह मोशन अभी गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा चौधरी ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कल 3. 55 मिनट पर आपको अपना एक मोशन दिया है। यह मेरा मोशन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मोशन शराव के आन्दोलन के बारे में था।

श्री अध्यक्षः अभी आपका यह मोशन अंडर कंसीड्रेशन है। अब आप बैठिए।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः सर, मेरा एक मोशन और भी था जो मैंने आपकी सेवा में सुबह ही दिया है। यह मोशन किसानों को कम्पनसेशन न देने के बारे में है। इसके अलावा एस०वाई०एल० के बारे में और यमुना ऐग्रीमैंट के बारे में भी मैंने आपको अपने मोशन दिए हुए हैं जोकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उन मोशन का क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः आपके ये मोशन रूल 84 के अंडर हैं और ये अभी अंडर कसीड्रेशन हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाऊस के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हु कि हमारा एक भाई छत्तरपाल सिंह हाऊस के बाहर बैठा हुआ है..

श्री अध्यक्षः आप केवल अपने मोशन के बारे में ही पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यह मामला तौ कालिंग अटैंशन मोशन से भी ज्यादा गम्भीर है। इसी हाउस का

वह सदस्य बेचारा सड़क पर बाहर बैठा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस सदस्य को हाउस के अन्दर बुलाने की इजाजत दी जाए।

श्री अमर सिंह ढांडे: स्पीकर सर, 10 तारीख को मैंने एक काल अटैशन मोशन दिया था। जिला कैथल के गांव क्योड़क में अनेक जगहों पर हरिजनों के साथ जो अत्याचार हुआ, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिजनों के पीड़ित परिवार गांव छोड्कर चले गए हैं।

Mr. Speaker : It is under consideration. यह गवर्नमैंट को कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

श्री रमेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आपुने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जैसे अभी अमर सिंह ढांडे जी ने बताया कि क्योड़क गांव में हरिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी प्रकार से सिवानी कस्बे में भी हरिजनों के ऊपर जुल्म किये गए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह आलरैडी डिस–अलाउड है। इस पर बोलने की जरुरत नहीं

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, हाउस में कई बातों का जिक्र आ चुका है। विपक्ष की बात तो आ गई लेकिन सरकारी प्रापर्टी की अटैच मैट की जो बात आई है, उसके बारे में सरकार का पक्ष नही आया है। यह जो इन्होंने काल अटैंशन मोशन दी है कि सरकार की प्रापर्टी अटैच हो रही है, यह ठीक नही है।

श्री अध्यक्षः अभी तो कोई बात नहीं की है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं आई। यह बात ठीक नही है। या तो ये कहते कि हमारे काल अटैंशन मोशन का फलां नम्बर है, फलां तारीख को दिया है लेकिन इन्होंने तो डिटेल में बात कह दी है, हालांकि यह अंडर कंसीड्रेशन है।

मीडिया व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना की गई सभी पार्टियों के एम०एल०एज० की एक समिति के गठन सम्बन्धी मामला

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं स्पीकर सर, एक बात अखबार में आई शै, जिसके बारे में प्रैस के मैम्बर यहां आकर डिफैंड नही कर सकते, वह हैः–

"Newsmen seek all-party probe."

यह बड़ा अहम मसला है। इस हाउस के माननीय सदस्य चौधरी बंसी लाल जी ने अखबार वालों पर इस तरह के रिमार्कस पास किए, जो ठीक नही है। फैक्चुअल पोजीशन को छिपाकर राजबीर सिंह को पार्टी में एडमिट कर लिया। उसने बनारसी दास गुप्ता पर गोली चलाई थी और उसे सजा हो चुकी है। पेपर वालो के सामने उसे एडमिट कर लिया और अखबार वालों ने इस बारे मैं रैजोल्यूशन पास किया है और लिखकर भी दिया है। यहां आकर प्रैस वाले अपने आपको डिफैड नही कर सकतै कि यह बात सही है या गलत। जो आदमी यहां डिफैड नही कर सकते, उनके खिलाफ चौधरी बंसी लाल जी ने ऐसी बातें

कही। स्पीकर सर, वह राजबीर सिंह, जो एक क्रिमिनल है, उसको पार्टी में एडमिट किया और सबके सामने ऐडमिट किया। वे यहां आकर हाउस में कह रहे हैं कि नहीं ऐडमिट किया, यह गलत बात है। आज के दैनिक ''दी ट्रिव्यून'' इंगलिश में पूरी डिटेल है। इसकी कगनीजैस आप लें। प्रैस वाले अपने आपको डिफैड नहीं कर सकते। उन्होंने आपको लिखकर भी दिया है। इसके बारे में आप भी कार्यवाही करे।

श्रम तया रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा): स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजबीर सिंह मेरे हल्के हिमाउपुर का रहने वाला है और चौधरी बंसीलाल जी ने खुद पत्रकारों के सामने उस आदमी को पेश किया था। पत्रकारों ने खुद इस बात को माना है कि चौधरी बंसी लाल जी ने राजबीर सिंह को उनके सम्मुख पेश करके उनको इन्ट्रोड्यस किया और बाद में चौधरी बंसी लाल जी इस बात से भी मुकर रहे हैं। (व्यवधान व शोर) बंसी लाल जी ने हाउस में और बाहर भी इस तरह की गल्तबयानी की है, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह बात बिल्कुल गल व निराधार है कि मैंने राजबीर सिंह को ऐडमिट किया है। न तो मैंने इसको ऐडमिट किया और न ही कोई ऐसी बात है। (शोर) अब ये भाई यूंही कहानी मढ़कर प्रैस पब्लिसिटी के लिये जो कहना है, वह कह लें। जो चाहे कहानी घड़ लें, लेकिन मेरी पार्टी में ऐसे आदमियों के लिये न तो

कोई स्थान है, न ही कोई ऐसी बात है और न ही इस तरह का कोई सवाल ही पैदा होता है। (शोर)

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डाः स्पीकर साहब, इस के लिये हाउस की कमेटी बना दीजियेगा। राजबीर सिंह के रिलेशज इस घटना से पहले चौधरी बंसी लाल जी के साथ रहे हें। (शोर) वह भिवानी में जब रहता था, तब भी इनके घर आता– जाता था। इनके बेटे सुरेन्द्र सिंह से और इनसे उसके पूरे रिलेशज रहे हैं और इनके घर उनका आना–जाना रहता था। उस का बाप और वह मेरे पास आए और उन्होने यह सारी बात मुझे बतायी। इसलिये मेरा सुझाव है– कि इसकी जांच के लिये हाउस की एक कमेटी बना दी जाए ताकि सारे फैक्ट्स सामने आ जाएं। (शोर)

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मेरा फिर प्वायंट आफ आर्डर है क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर यह इलजाम लगाया है कि उस राजबीर सिह का मेरे घर आना जाना रहा है। मैं यह कहता हू कि मैंने उसको शक्ल से पहली बार प्रैस काफैस मे देखा था, वह भी चलते–चलते। मेरा तो उसके साथ न कोई ताल्लुक है और न ही कोई ऐसी बात है। न ही उसको पार्टी में एडमिट करने का सवाल ही पैदा होता है। (शोर) जब बनारसी दास गुप्ता पर गोली चली तो सब से पहला आदमी मैं था, जिसने इस बात को कंडैम किया था और कहा था कि इसको अवश्य सजा मिलनी चाहिये और इस के रोष स्वरूप मंडी में हमने हड़ताल भी करवाई थी। (शोर)

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डाः स्पीकर साहब, इन्होंने इतना तो माना कि मैंने उसको पहली बार देखा था। (शोर)

श्री राम रत्नः स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने का समय चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्षः राम रत्न जी, आप बार–बार बोलने के लिये खड़े क्यों होते हें? आप बैठें। आपको भी इसके बाद बोलने के लिये समय दिया जाएगा। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी बंसी लाल जी ने कहा और माना कि मैंने एक बार ही राजबीर सिह को प्रेस काफ्रैंस में चलते–चलते शक्ल से देखा था। जैसाकि हुड्डा साहब ने भी बताया है और पत्रकारों ने बतलाया है कि इन्होंने उसको स्वयं पत्रकारों के सम्मुख प्रस्तुत किया था और उसके बाद जब यह समाचार पलों में आया कि यह एक क्रिमीनल टाईप का आदमी है, जिसको सजा हो चुकी है तो ये मुकर गए। उसको यदि ये पार्टी मे एडमिट करते तो इनकी पार्टी की बदनामी थी। इस वजह से ये उसको पहचानने में आना–कानी कर रहे हें। इन्होंने पत्रकारों के सामने ही उस को पेश किया था और फिर ये कह रहे हैं कि वे पत्रकार गल्त कह रहे हैं। इस बारे मे बड़े–बड़े 15 पत्रकारों ने स्पीकर साहब, आपको लिख कर भी दिया हुआ है। हिन्दुस्तान अखबार, राष्ट्रीय सहारा दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रैस, नवभारत टाईमज, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, संध्या हिन्द टाईम वगैरह–वगैरह जो मेन अखबार है, इन के पत्रकारो ने आपको लिखकर दिया हुआ है कि जो चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है, वह हमारे सम्मुख कहा है। इस तरह के बड़े–बड़े पत्रकार जो अपने आप को हाउस में डिफैन्ड नहीं कर

सकते, उनको बंसी लाल जी झूठा कह रहे हैं। यह बड़ा ही गम्भीर मसला है। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था। (शोर) इसका एक ही हल है कि जो पैटीशन उन्होंने आपको दी है, उस पर यहां के रूल्ज एण्ड रैगूलेशन के तहत निर्णय लें। इस तरह के पार्लियामैंट में भी कई प्रैसीडैन्ट्स मौजूद हैं। उनके अनुसार आप निर्णय लेकर आगे कार्यवाही करें ताकि जो आऊट साईडर्ज हैं, उनके राईट्स को सेफ किया जा सके। अगर इन जैसे सीजन्ड पार्लियामैटेरियन इस तरह की गल्तबयानी यहां पर करेगे, खुद किसी बात कने कहकर मुकरेंगे तो आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इस मामले पर यहां पर आप द्वारा कोई कार्यवाही न की गई तो बाहर जो प्रैस है, आफिसर्ज हैं और दूसरे जो साधारण व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति क्या रहेगी? इन जैसे आदमी, जोकि 10– 10 साल लगातार राज्य के मुख्य मन्त्री रह चुके हों और पार्लियामैंट में भी उच्च पदों पर विराजमान रहे हों, भी अगर इस तरह की बातें करें, तो यह उचित नही है। इस लिये स्पीकर साहब, आप स्वय इस का निर्णय करें।

श्री अध्यक्षः यह अंडर कसिड़ेशन है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत और बे–बुनियाद बात करते हैं। मैंने उसको कभी एडमिट नहीं किया। अगर ये अखबार की बात पढ़ते हैं तो मैं भी एक अखबार की बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूं। मेरे पास यह नव भारत टाइम्ज अखबार है।

श्री अध्यक्षः आप इसी कनैक्शन मे बात करें।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा राईट है। ये क्रैक्टर असैसीनेशन कर रहे हैं। मैं इसी कनैक्शन में बता रहा हूं। मैं सच्ची कहानी बताऊंगा। इसमें कांग्रेस सांसद चिरन्जी लाल शर्मा की भजन लाल को खुली चुनौती के नाम से खबर छपी है। (शोर) पंडित चिरन्जी लाल ने कहा है कि हरियाणा में सरकारी अधिकारी ही कांग्रेस पार्टी की जगह लिए हुए हैं।

श्री अध्यक्षः इस बात का उससे कोई कनैक्शन नहीं है। (शोर)

चौधरी बंसी लालः नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का पूरा किया है। यदि ये बार–बार मेरा क्रैक्टर असैसीनेशन करते हैं तो मुझे सच्ची बात बताने दो ताकि सही बात तो सामने आए। पंडित चिरन्जी लाल ने कहा है कि अधिकारी ही काग्रेस पार्टी की जगह लिए हुए हैं। उपायुक्त जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक महा सचिव, तहसीलदार कोषाध्यक्ष, बी ०डी ०ओ० संगठन सचिव और कानूनगो व पटवारी कार्यकर्ता का स्थान लिए हुए हैं।

श्री अध्यक्षः यह बात उससे संबंधित नही है। आपकी बात का सब्जैक्ट उससे संबंधित नही है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं और अखबार में भी मेरी बात आ चुकी है कि यह गलत है। फिर ये वार–बार ऐसी बात क्यों करते हैं?

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में बात करना चाहता हूं। कई दिन से इस सदन में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं।

श्री अध्यक्षः आप इससे अलग बात न करना।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः मैं इससे अलग नहीं जाऊंगा। आपको मेरे खड़े होते ही पता नही क्या बहम हो जाता है, आप मुझ पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, ऐसी कोई बात नही है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः मैं चेयर का पूरा सम्मान करता हूं। कई बार आपकी मजबूरी होती है। आप कोई बात कह नही सकते इसलिए वह बात मुझे कहनी पड़ती है।

श्री अध्यक्षः हमारी कोई मजबूरी नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः तो मैं कह रहा था कि इस विषय पर कई बार चर्चाएं चली हैं और इन चर्चाओं के दृ ष्टिगत लोगों को यह सोचने–समझने पर मजबूर होना पड़ता लूँ कि राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी व्यक्ति के बारे में मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। जब बनारसी दास गुप्ता पर गोली चलाई गई थी, तो सब से पहले भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और मौजूदा मुख्य मन्त्री की तरफ से व्यान छपा था कि ओम प्रकाश ने बनारसी दास को गोली मरवाई है। अच्छा हुआ बिल्ली छिक्के से बाहर आ गई और अब उस मुद्दे को ले कर दोनों में नोंक झोंक हो रही है। श्रम मन्त्री जी अभी

कह रहे थे कि वह व्यक्ति मेरे पास भी आया था। तो अपराधी किस्म के लोगों के एक प्रकार से पनाहगार ट्रेजरी बैंचिज के लोग बने हुए हैं। उन्हें प्रोत्साहन मिल जा है और उसका नाजायज लाभ उठा करके इस प्रकार के जो लोग हैं, वे राजनीतिज्ञों को गुमराह करने के प्रयास में लगे है। इसी हाउस में अध्यक्ष महोदय, कभी लेखू अपहरण कांड को ले कर तो कभी पहाड़ी पर चर्चा चली थी। कभी जितेन्द्र का भी जिक्र आया।

श्री अध्यक्षः इसका इससे कोई ताल्लुक यही है। आप बैठे। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं आ रहा हू। आप जरा मुझे भूमिका बांध लेने दें। मै आपके दारा यह कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले के लिए विधान सभा के जो सम्मानित सदस्य है, उनका अपना आचरण ठीक हो। आपकी तरफ सै आचार संहिता मुकर्रर की जानी चाहिए वरना यह प्रथा बढ़ती चली जाएगी और राजनीतिज्ञों की' विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगर हम पब्लिकली कोई बात कहते है तो उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर प्रैस के लोगों को इस प्रकार की बातें कही जाएं तो उनको वह बात डिफैड करने का अवसर नहीं मिल सकता। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का तो जनतन्त्र में विश्वास रहा ही नही हे। प्रैस पर अंकुश लगाने के लिए विदेशी मीडिया को बुलाया का रहा है। इस प्रदेश मे तो पत्रकारो पर जानलेवा हमले भी हुए है और उनको डराने धमकाने की कोशिशे भी की गई हैं। आज इसी बात को लेकर अगर हम लोग कोई बात कहें और

उसके बाद हम अपनी. बात मे मुनकर हो जाएं तो प्रदेश के लोगो के सामने सही बात कैसे आ पाएगी? मैं यह बात को तो मान सकता हूं कि चौधरी बसी लाल जी किन्ही कारणों से अपने दिमागी सन्तुलन को खो बैठे है, इसलिए वे कमी मानव को 'चिचड' की सजा देते हैं और कभी एमरजैसी को डिफैडं करते हैं। पत्रकारों को कही हुई बात से भी मुकर होने का प्रयास करते है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूगा कि किसी कमेटी का गठन करने की –बजाय आप आचार संहिता मुकर्रर करें। प्रैस की जो भूमिका है, वह कायम रहनी चाहिए। फ्रीडम औफ प्रैस पर कोई अंकुश नही लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार का आपको कोई निर्णय देना चाहिए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप पिछले 28 साल से इस हाउस के सम्मानित सदस्य रहे हैं। आपने बार–बार चुनाव जीता है और इस चुनाव के बाद आप इस हाउस के अध्यक्ष चुने गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप राजनीति में आए, उस समय मैं कालेज में एक स्टुडैट था। उस समय हमने एक सैमीनार किया था। उस सेमीनार मे कुछ बातें ऐसी आई थीं जैसे शिक्षा का प्रसार और प्रचार सभी जगह होना चाहिए। लेकिन वह इसलिए नही होता क्योंकि साधनों की कमी है। आपने उस समय यह कहा था कि साधनों को कमी होते हुए भी शिक्षा का प्रसार और प्रचार होना चाहिए। शिक्षा तो एक अमृत है। उसको अगर औक से भी पिलाया जाए तो भी वह पिलाना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सदन में जो चची हुई है,

उसका कोई औचित्य नही है। वह बात रूल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट औफ बिजनैस के किसी भी रूल में शामिल नही है। लेकिन कुछ वरिष्ठतम साथी, जो पूर्व मुख्य मन्त्री भी रहै हैं या वे सीनियर मैम्बर होने का दावा करते हैं, अपनी सीनियीरटी की वजह से खड़े हो कर अपनी सारी बात कह देते है। उन पर कोई रूल लागू नही होता है। मौका लगते ही वे खड़े हो कर अपनी बात कह जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया। मैं कहता हू कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 1987 से पहले कोई राजनैतिक हत्याए नही होती थी और न ही राजनीति का कोई अपराधीकरण हुआ था। मैं यह बात इसलिए कह रहा हू क्योंकि मुझे भी आपने अपनी बात कहने का मौका दे दिया, वरना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वह बात कहने का कोई औचित्य नही था। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत कहां से हुई, इस बारें में हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छा तरह से जानती है। मेहम मे जौ काण्ड हुआ, वह उसकी चरम सीमा थी। उस समय राजनीति में अपराधियों को शह किसने दी? दुकानों पर कब्जे करवाना, गरीब आदमियों को उनके घरो से बाहर निकालना, जमीनो पर नाजायज कब्जे करना अनेको-अनेक ऐसी बातें है, जिनका विवरण इतिहास के अन्दर कही पर भी नही है। चौधरी बंसी लाल जी. के चुनाव मे और मेरे चुनाव में जिस तरीके से वहां का वातावरण आतंकित था और किसी तरीके से वहां पर लोगों को गोलियो से भुना गया, वह सारी की सारी कहानी किस के नाम से जानी जाती है यह बात मैं

नही कहता, हरियाणा प्रदेश की जनता कहती है कि किसने राजनीति का अपराधीकरण किया। स्पीकर साहब, आपको हाउस की कुछ मर्यादायें तो रखनी पड़ेगी। मैं आपकी शान में कोई गलत बात नही कहता। आप बहुत शिक्षाविद है। आप इस सदन के पिछले चार साल से अध्यक्ष है। मैं यह कहता हू कि जो नए एम०एल०ए० है औंर मैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नया एम ०एल०ए ० मानता हू क्योकि ये कभी भी' चुनाव जीत कर नही आए। ये तो उप–चुनाव जीत कर आते है लेकिन अब तक ये जनरल चुनाव जीत कर नहीं आए। इस बारे में मेरा आपमें अनुरोध है कि जो मैम्बर चुनकर आए उनको 5– 6 महीने के बाद 5– 10 दिन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस बारे में तो मैं भजन लाल जी का भी कइर मानता हूं कि जो नए मैम्बर चुनकर आए है, उनको ट्रेनिंग देने की बजाये सीधे मिनिस्टर बना दिया, उनको ट्रेनिंग का मौका नही मिला। (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): आज कल आप खाली हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए लगा देते है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अगर आप मेरे को इस काम पर लगाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेनिंग दूगा। स्पीकर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूगा कि प्रो० छत्रपाल जी को हाउस से बाहर निकाला हुआ है और वे बाहर बैठे हुए हैं। वे प्ले–कार्ड लिए हुए बैठे हैं। अब हाउस की मर्यादा यही. है कि आप उनको बूलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको मौका दीजिए ताकि वह भी अपने हल्के की बातें कह सकें। बाहर जनता में जो प्रदर्श्न वे कर रहे है, वह

हाउस की मर्यादा के बाहर की बात है। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि किन मुद्दों पर कौन आदमी खड़ा होकर कब क्या बात कह सकता है? कैसे आदमी को हाउस से बाहर निकालने के आदेश देते हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात पर पुनर्विचार करें। यह बात सही है कि कोई भी कोड आफ कण्डक्ट हाउस के अन्दर नही है। अब आप देखिए कि नेहरा साहब ने कह दिया कि बंसी लाल जी ने कुछ कह दिया है या संपत सिंह जी ने कुछ कह दिया है, इसलिए मुझे भी मौका मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आपने उनको मौका किस रूल के तहत दिया? जब आप यह कहते हैं कि बैठ जाइए तो फिर सदस्य क्यो खड़े रहते हैं? बैठते क्यो नही और अपनी बात पर वाजिद रहते है, चाहे कितने भी सीनियर सदस्य हो, जब आप खड़े हो, तो उनको बैठ जाना चाहिए। इसलिए मेरा आप सै अनुरोध है कि यह विचारणीय विषय है, इस पर आप सोचिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

(1) चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल आन ए प्वायट आफ पर्सनल एक्यप्लेनेशन सर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बात श्री जगदीश नेहरा नें उठाई कि बंसी लाल ने पहले तो उसको एडमिट कर लिया औंर फिर पता लगा कि वह तो क्रिमिनल है, अगले दिन इन्कार कर दिया। एक मन्त्री कहते है कि उसका हमारे घर आना–जाना था। पहते ये दोनों फैसला कर लें कि सरकार में सच कौन सी बात है? ये कौन से वर्शन पर टिकते हैं? दूसरी बात यह

है अध्यक्ष महोदय, जैसा अखबार ने लिखा है, मैंने उसको एडमिट किया। उसी अखबार ने यह भी लिखा है कि बंसी लाल ने उसको प्रैस कांफ्रैंस में धमकाया। धमकाने के बाद क्या मैं उसको एडमिट करूंगा? कोई सोच सकता है क्या? मैं उसी को धमका रहा हूं और उसी को एडमिट कर रहा हूं, यह कैसे हो सकता है? मैं कम्पलीटली डिनाई करता हू कि न तो मैंने उसको अपनी पार्टी में लिया, न उसका कोई वेल्कम किया और न ही ऐसे आदमियों के लिए हमारी पार्टी मे कोई जगह है। मेरे बारे में चौटाला साहब ने कहा कि बंसी लाल तो दिमाग का संतुलन खो बैठा है। शायद मै इनके हिसाब से सतुंलन खो बैठा हूंगा। यह तो हरियाणा की जनता जानती बै कि दिमाग का संतुलन मैं खो बैठा हूं या चौटाला साहब खो बैठे हैं। यह तो हरियाणा की जनता पर छोड़ दें।

(2) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर, अध्यक्ष महोदय, हाउस के सम्मानित सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा। मैंने कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है। विशेष रूप से ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोगों पर अपराधीकरण के मुकदमे चल रहै हैं। शायद चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को छगन नही कि 307 का केस इनके खिलाफ अरब भी है। केस चल भी रहा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूं। कि इस प्रकार का राजनीति अपराधीकरण न हो, और दोगली बातें न अपनाई जाए। चौधरी बंसी लाल जी में

हिम्मत होनी चाहिए कि कोई बात कही जाये तो उसे धड़ल्ले से एक्सैप्ट कर लें। प्रैस के लोगों को अब परेशान किया जा रहा शै। उस पत्रकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर सम्पर्क स्थापित करके उसे पत्रकारिता से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे चुनाव जीत कर आए हैं तथा वे जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए उनकी बात जनता जनार्दन तक जानी चाहिऐ। चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी दोगली नीति पर चल रहे हैं। हाउस के बाहर तो कहते हैं कि चौधरी भजन लाल करप्ट हैं लेकिन यहां पर हाउस में उनका गुणगान गाने में लगे हुए हैं। शायद अब भी बचे–खुचे अर्से में मन्त्री पद की उनकी लालसा रही होगी। चुनाव आएगा तब बंसी लाल जी को भी आटे दाल का भा व पता लग जाएगा। और यह जो विभूतियां सामने बैठी हुई हैं, इनमें से कोई भी जीत कर आने वाला नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर यह निर्णय करना है तो आज ही निर्णय क्यों न कर लिया जाए (विघ्न)

11.00 बजे

(3) चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। एक तो मैं यह कहना चाहता हू कि मेरे खिलाफ 307 का कोई केस नही है ये बिल्कुल गलत और निराधार बात कह रहे है। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुकद्दमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है या नहीं? आप हाउस को गुमराह मत करिये (किन)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि वह केस चल रहा है। मेरे खिलाफ 307 का कोई केस नही चल रहा है, वह बिल्कुल गलत व्यानी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ 307 का केस हिसार में दर्ज हुआ था। मेरे ही साथियों को गोलियां लगी थी, मेरे ही वर्कर की हत्या की गई थी क्योंकि चौटाला साहब और चौधरी देवी लाल की हुकुमत थी इसलिये केस भी मेरे खिलाफ दर्ज हुआ। स्पीकर सर, इससे ज्यादा राजनीति का अपराधीकरण और तया होगा? पुलिस की देखरेख में इनके शासन में गुण्डों को जेलों से पैरोल पर छुड़वा कर भिवानी और हिसार में लोगों को आतंकित करा रहे थे। इस से बड़ा राजनीति का अपराधीकरण और क्या होगा? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल के बारे में जो मामला पत्रकारों ने दिया है वह अण्डर कैसी ड्रेशन है। अब इस पर और डिस्कशन नही होनी चाहिये। अब श्री राम रतन अपनी बात कहे।

श्री कर्ण सिंह दलाल, एम ० एल ० घर ० द्धारा श्री रामरतन, एम ० एल० ए ० को धमकी देने तया उनके विरुद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी मामला

श्री राम रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। रोजाना हरिजनों के बारे मे बात होती है और हरिजनों पर अत्याचार भी होते हैं। इसी सदन के साथी जो विधायक हैं, उनसे बढ़कर हरिजनों पर अत्याचार करने वाला शायद पूरे हरियाणा में और कोड नही है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक दरख्वास्त दी है जो कि निम्न प्रकार से है:—

''श्री मान अध्यक्ष महोदय,

हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ।

करना खिलाफ कार्यवाही कर्ण सिंह दलाल, विधायक।

श्रीमान जी,

मैं राम रतन, विधायक, हल्का हसनपुर जिला फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं निम्नलिखित रूप से आप से प्रार्थना करता हूं:—

कल रात जब मैं एम० एल० ए० होस्टल में था तो श्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक ने बिना वजह से कहा कि तू हरियाणा विधान सभा में हमेशा मेरा विरोध करता है। इसके बावजूद मैने उनको कुछ नही कहा। इसके बावजूद मेरे को मां बहन की गालिया दी और कहा तू मेरे से दूर हट, तू चमार है और तेरे से बदबू मार रही है। फिर जाने हुए मेरे को जान से मार देने की धमकी दी और देख लेने की धमकी दी। अध्यक्ष महोदय, मुझे उनकी धमकी (जान से मारने की और देख लेने की) से बड़ी मानसिक पीड़ा पहुंची है और उनसे मुझे जान का खतरा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी जान की रक्षा की जातु और श्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। '' (विघ्न)

मेरी इस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही हुई है?

Mr. Speaker : Ram Rattan Ji, it is under consideration. (Interruptions) It is under consideration, that's all.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए है। न मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और न ही गाली–गलोच की। अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्य वहां पर सदन में बैठे हुए है। यह कल शाम की बात है। मैं कमरा नं० 1 मे बैठे हुए डाक्टर से दवाई लेने जा रहा था। तो वहां से' माननीय कटवाल साहब जा रहे थे। मैं इधर डाक्टर के कमरे की तरफ जा रहा था। श्री राम रतन जी अपने कमरे से निकल कर शायद ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब इन्होंने पहली सीडी पर पैर रखा तो कटवाल साहब ने इनका हाथ पकड़ा और मेरी तरफ इनको खींच कर लाने की कोशिश कर रहे थे। कटवाल साहब इनसे क्या कह रहे थे या इन्होंने कटवाल साहब से क्या कहा, यह मैंने नही सुना। कुछ कहते हुए कटवाल साहब मेरी तरफ इनको ला रहे थे। मैंने उनसे कहा कि इन्हे मेरे से दूर रखें। मेरी इनसे बनती नही है। यह कह कर मैं डाक्टर के कमरे की तरफ चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं औन औथ यह बात कह सकता हूं। उस वक्त वहां पर 20–25 आदमी खड़े हुए होगे और अगर उनमें से कोई भी यह कह दे कि मैंने इन्हें गाली दी या और कुछ कहा हो, तो आप जो भी सजा मुझे देंगे, वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल के पास मेरी किसी भी बात का

जवाब नही है और ये मेरे सवालों के जवाव में राम रतन को खड़ा कर देते है। मैं इनको कहता हु कि ये फरीदाबाद मे आमने सामने जन–सभा कर लें तो मैं इनको जवाब दूंगा और इनको इनकी हैसियत का भी पता चल जाएगा।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बात तो कुछ और थी और ये किमी दूसरी साईड पर ले गए। ये दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं और इनके कारनामे राम रतन जानता है और राम रतन के बारे मे ये जानते है। (शोर) अब इन्होंने मेरे बारे में कह दिया कि फरीदाबाद मे जन सभा करके देख लो। अध्यक्ष महोदय, ये पहले मेरे साथ थे और मैंने इनको तीन तीन गाड़िया दे रखी थी और ये गाड़ियां लेकर वैसी लाल जी के पास चले गए। मैंने कहा कि भाई गाड़िया तो दे दो। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो इनके हल्के पलवल से ही चुनाव लड लेंगे और इनको भी पता चल जाएगा। (शोर एव व्यवधान)

वर्ष 199 5– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: राम रतन जी, जो आपने मुझे लिखकर दिया है, वह अभी अन्डर कंसीड्रेशन है। आनरेबल मैम्बर्ज, अब बजट पर जनरल डिस्कशन रिज्यूम की जाएगी। श्री सतबीर सिंह कादयान अपनी स्पीच शुरू करे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो

(इस समय चौधरी ओम प्रकाश बेरी बोलने के लिये खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्षः बेरी साहब, आप कल आधा घन्टा बोल चुके हैं। (शोर)

वाक आउट

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आपके चौम्बर में फैसला हुआ था कि दो पार्टी के लीडर आधा–आधा घन्टा बोलेंगे और बाकी मैम्बर्ज 5–7 मिनट अपनी कांस्टीचुएंसी के बारे में बोल लेंगे। अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब आधा घन्टा बोल चुके है और अब ये जितना समय भी बोलेंगे, आप वह समय मेरे आधा घन्टा मे से काट लेना। बाकी जितना समय बचेगा, मैं उतने समय में ही बोल लुंगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर ये दोनों के समय मे बोल लेगे तो मैं अपने समय पर नहीं बोलूंगा। इसीलिए आप बेरी साहब को बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्षः बंसी लाल जी, ये कल आधा घन्टा बोल चुके हैं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मुझे कल 10 मिनट तक इन्ट्रप्ट किया गया था। आप मुझे वह समय तो दे दें।

श्री अध्यक्षः बंसी लाल जी, क्या आप बोलेंगे?

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आप मेरे टाईम में से बेरी साहब को टाईम दे दें। ये जितना समय बोलेंगे, उतना ही समय मेरे टाईम में से काट लेना।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग 1– 1 घंटा बोलेंगे तो बाकी मैम्बर कहां पर जाएंगे? 60

मैम्बर्ज तो हमारे भी बैठे हुए हैं। आपको इनको भी मौका देना चाहिये।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हर पार्टी से दो मेन स्पीकर्ज के आधा आधा घंटा बोलने के लिये जो फैसला हुआ था, हम उनसे बाहर तो नही जा रहे है।

श्री अध्यक्षः बंसी लाल जी, आपके ग्रुप को भी उसी तरह से टाईम दिया जाएगा जिस तरह मे डिसाईड हुआ था। इसलिये अब कादयान साहब बोलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यदि आप बेरी साहब को बोलने का समय नहीं देते हैं तो हम इसके विरोध में एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। ....

श्री अध्यक्षः यह जो मेरी परमिशन के बिना बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सभी उपस्थित माननीय सदस्य एवं असम्बद्ध सदस्य श्री ओम प्रकाश बेरी सदन से वाक आउट कर गए) वर्ष 1995–96 के वजट पर सामांन्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। 13 तारीख को जो माननीय वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने 1995–96 का बजट पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हू। अध्यक्ष महोदय, जो नीरस बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, इस बारे मेरा कहना यह है कि ऐसा नीरस

बजट, ऐसी निगाहों से, ऐसे इरादों से हरियाणा में कभी भी पेश नही किया गया जैसा कि गुप्ता जी के रहते हुए पेश किया गया है। स्पीकर सर, गुप्ता जी इतनी बड़ी उम्र में भी सिन्दूर पर और मंगल सूत्र पर टैक्स माफ करते हैं जबकि गुप्ता जी को कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हैल्थ में, बिजली में, सिंचाई मे और बाढ़ पर राहत देनी चाहिए थी। जब हमारी पार्टी की सरकार यानी चौधरी देवी लाल जी. की सरकार और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होने जो–जो ध्यान इन क्षेत्रो मे दिया था, उसको मैं आपको पैरावाइज बनाऊंगा। मैं मक्की और ज्वार के बारे में बताना चाहता हूं। इनके डिपार्टमैंट के जो स्टेटिक्स या आकड़े हैं, मैं उनके हिसाब से ही वित्त मंत्री जी को बताऊगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी तो व्यापारी हैं और इनकी आढ़त की दुकान भी हैं अगर किसी भी मंडी में ज्वार की सेल एक क्विटल से ज्यादा हुई हो, तो ये हमें बता दें। इसके अलावा बाजरे की और मक्की की सेल तो बहुत ही कम हुई है। हमारी सरकार ने 1990–91 में जो बजट पेश किया था, उसमें कृषि के ऊपर बहुत खर्च किया गया था। इन्होंने अपने बजट में कृषि के ऊपर 7. 2 परसेंट ही कुल प्लान का पैसा खर्च करने के लिये रखने का निश्चय किया है जबकि 1990–91 में यह 12.20 परसैंट था और 1991–92 में यह 15. 12 प्रतिशत था जब हमारी पार्टी की सरकार थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार इस तरह का बजट पेश करके गयी थी, पास करके गयी थी। लेकिन आपने तो

इसको घटाया ही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो किसान ट्रैक्टर लेते है, तो चाहे कौमर्शियल बैक हो या कोई दूसरा बैक हो, ऐसे बैकों में किसानों को इसके लिए बैक गारंटी के रूप में 1.5 परसैट रैन्ट देना पडता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कही किसान बैक को अपना कर्जा अदा न करे। उपाध्यक्ष महोदय, एक डी ०आई०सी० जी ०सी ० यानी डिपोजिट इंशयोरैन्स क्रैडिट गारन्टी कोरपोरेशन, बम्बई नाम की सस्था शै। इसने किसानों को 1.5 परसैंट रैन्ट पर इसलिये कजी दिया है कि कही किसान उसका पैसा न दे सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसानो का क्या कसूर है? वे क्यों गारन्टी दें ? इस तरह की गारन्टी का हरियाणा सरकार क्यो नही अपने बजट मे प्रावधान करती कि अगर किसान इस तरह के इम्पलीमैन्ट्स खरीदने चाहे या और दूसरी ऐसी चीजे खरीदना चाहें तो हरियाणा सरकार को इस बात की गारन्टी अपने बजट में से उनको देनी चाहिये और कहना चाहिये कि बहुत समय तक उनसे कोई गारन्टी या फीस नही ली जाएगी। जहां तक कृषि की बात है तो खाद की क्या दुर्दशा थी? आपकी ही पार्टी की केन्द्र मे सरकार है और वहां आपके ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हैं। आप उनसे समय पर खाद देने के लिये क्यों नही कहते ? मैं खाद पर सबसिडी देने के बारे में हरियाणा सरकार से पूछना चाहूंगा कि कौन सी खाद पर कब सबसिडी दी गई है? पैस्टीसाईड्ज और इनसैक्टीसाईड्ज की पिछले सालों के मुकाबले में सेल भी घटी है लेकिन उन पर इन्होंने सबसिडी भी खत्म कर दी है। इस सब के बावजूद सारे प्रदेश में खाद के लिये हाहाकार

मची.। आपके चहेते लोगों ने खाद को ब्लैक कर दिया। जो यूरिया का कट्टा 166 रुपये का हुआ करता था, वह कट्टा 200 से 250 रुपये तक में बिका। साथ ही नकली डी ०ए०पी ० बिकी। समय पर न खाद दिया, न दवाई दी। यह तो भगवान की. दया हो गई कि बारिश हो गई वरना तो नहरों में भी पानी नही होना था और रजवाड़ों मे भी पानी. नही होना था। कौमर्शियल सेल टैक्स की जो वुद्धि है वह ज्यादा है क्योकि किसान का उत्पादन बिकने कें बाद उस राशि का चार परसैंट आपके खजाने मे जाता है। अनाज ज्यादा पैदा हुआ इसलिये टैक्स की राशि मे भी बढ़ोतरी हुई है। गन्ने का भा व आया तो चीनी घोटाले जैसे काम आपने कर दिए। कृषि की पालिसी पूरी तरह से गलत है। किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये पूरे धन की व्यवस्था नही करवाई जाती है। पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में यह बात आई थी कि 100 ग्राम टमाटर का बीज विदेश से खरीदकर लाए। वह 22 हजार रुपये का आया। एक किलो बीज दो लाख 20 हजार का लेकर आए। यह टमाटर के बीज का भाव नही है। इसमे विदेश जाने का खर्चा भी इन्कलूडिड है। मैं भी विदेश गया था। मैं तो 20 हजार रुपये में एक किलो बीज लेकर आया। जो बीज लेकर आए, उस बीज को किस किसान ने ट्रायल किया? कैसी. उसकी आउटपुट रही? इस बात का जनता को इलम नही है और प्रदेश में जिस तरह मे मिलावटी बीज बिक रहे हैं, उसमें लगता है कि आपकी जो सर्टीफाइंग एजैन्सी है, वह अपना काम सुचारू रूप से करने में नाकाम रही है। नकली बीजों को सर्टी– फाई करके

किसानों को दिया जाता है, जिससे उसकी उपज घटती है। उसके साथ–साथ अच्छे भाव नही मिलते क्योकि मिलावटी बीज है, उन्नत किस्म नही है। चौधरी देवी लाल जी के समय मैं स्कीम चलाई थी कि यदि किसान मंडी में अनाज लाता है तो 3 रुपये मार्किट फीस कमेटी को मिलती. है। उस पैसे से उसका रास्ता बनाया जाए। सड़क का काम शुरू किया गया था। गांव से मंडी को जोड़ने के लिये सड़क बनाई जति। थी। रास्ते पक्के किए जाते थे। आज वे सड़कें गांव में नहीं बनती। कही दूसरों की फैक्ट्रियों में सडक बनती हैं। चौधरी देवी लाल जो ने जो स्कीम मंजूर की थी, उन पर काम नहीं हो रहा है। मार्किटिंग बोर्ड ने शराब ढोने का काम भी खुद ले लिया है। 8 तारीख को पानीपत मे एस०डी ०ओ०, जे ०ई० और क्लर्क दारू की चार पेटी ले जा रहे थे। चार पेटी शराब हुड्डा कालोनी पानीपत में चांदनी बाग के एस०एच०औ ० ने बरामद की। चौधरी देवी लाल के समय में जौ सड़कें मन्जूर हुई थी, वे सारी बनानी बंद कर दी। एक सड़क अहर से अलूपुर की इन्होंने बनवाई थी, उस पर साइकिल भी नहीं चल सकती। किनारे से सड़क टूट जाए तो मंत्री जी कह देंगे कि फ्लड से टूट गई लेकिन अगर सड़क बीच से बैठ जाए तो गुप्ता जी और कृषि भली जी क्या बहाना करेगे? मैंने कहा कि इस सड़क की इंकवायरी कराई जाए और मुझे भी इस इंकवायरी में शामिल कर तिया जाए। कृषि मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नही की। डिवाणा ऐ प्रोच रोड से सिवाह वैटनिरो होंस्पिटल तक तुक किलोमीटर की सड़क बननी है, और एक उरलाना खुर्द से गुरुद्वारा की सड़क है। यह सड़क भी

नही बनाई। यह मेरे हल्के के गांव है और मैं विपक्ष का एम ०एल०ए ० हू इसलिये मेरी मांग की ओर ध्यान नही दिया जाता है।

अब मैं पी ०डब्ल्यू ० डी ० विभाग से सम्बन्धित कुछ बाते कहना चाहूंगा कि आपकी जो इकनामिक सवे आफ हरियाणा की रिपोर्ट है, उसमें पेज 21 पर सड्कों के बारे में लिखा गया है कि 1990– 91 में हरियाणा के अन्दर 23168 किलोमीटर्ज सड़के थी जोकि अब घटकर 22787 रह गई है यानि 181 किलोमीटर सड़के कम हो गई, पता नही कहां गइ। ये तारकोल व रोड़ी जा गये पता नहीं इनको कितना कुछ हजम हो गया। मैं आपको बताता हूं कि एक सड़क परहाना से शाहपुर तक मन्जूर हुई थी और उसके ऊपर चार लाख रुपये की मिट्टी पड़ चुकी थी परन्तु वह सड़क न बनाकर इन्होंने पड़ाना से जवारा तक की सड़क का काम शुरू कर दिया जोकि सोनीपत के हल्के में पड़ती है और यह हल्का इनके कांग्रेस अध्यक्ष .... का पड़ता है। इस सडक के ऊपर सरकार का काफी लगाव है (शोर) और वे इनके लिये एक पार्टी मीटिंग मे पिट भी गये थे। इस लिये अपने किसी चाहने वाले की खातिर हमारे हल्के के साथ इस तरह के भेदभाव की नीति नही बरतनी चाहिये थी। (शोर एवं विघ्न)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो स्पीच दे रहे हैं, आया यह बजट पर है या कि काग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ है? कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लेकर जो इन्होंने कहा बै, वह ऐक्सपन्ज हे चाहिये। जो आदमी इस हाउस का मैम्बर

न हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिये। जो आदमी अपने आप को डिफैन्ड न कर सकता हो, उसका नाम यहां नही आना चाहिये। जो नाम लिया गया है, उसको कार्यवाही में से निकाल देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है। किसी का नाम कार्यवाही में नही आना चाहिये, वह रिकार्ड न करे।

श्री सतबीर सिंह कादयानः मैं जो कह रहा हू यह फैक्ट्स है। हम तो कहते हैं कि जहां चाहो सड़कें बनाओं लेकिन हमारे पानीपत के जिला की जिन सड्कों का जिकर आया है, उनको भी प्राथमिकता दी जाए। जैसे पानीपत से काबड़ी, पानीपत से कुतानी तक की सड़कें बलबीर पाल शाह की कांस्टीच्यूएंसी की हद पर लगती हैं, वहां तनि–तीन फुट के गड्ढे हैं, इसलिये इन सड्कों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि लोगों को आने–जाने में असुविधा न हो। इसी तरह से आसन कलां से आसन खुर्द की सड़क है, जिसके बारे में मैंने कई बार ग्रिवेसिज कमेटी में भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस इलाके की सड़कें ऐसी. बुरी हालत में हैं कि वहां व्हीकल्ज तो क्या, आदमी पैदल भी नही चल सकता। मैं यह भी कहूंगा कि असन्ध और नौलथा विधान सभा क्षेत्रों को हर लिहाज से बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। इसी तरह से एक और सड़क मडलौडा से कुराना की है। उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। अब मैं रूट परमिट्स के बारे में कहूंगा कि सरकार ने लोगों को परमिट तो दे रखे है लेकिन सड़के खराब होने की वजह से बसे खड़ा है। ब्राह्मण माजरा गांव से वाहपुर तक की

सडक दो सात्र मे बन्द पड़ी है। उस पर सरकार की ओर से कोई कार्य– वाही नही की गई है। इसी सड़क के ऊपर एक बस रूट परमिट सहकारी संस्था को मिला हुआ है। उस बस को सीख सै नौलथा तक चलना है लेकिन बस पिछले 6 महीने से खड़ी है। न ही उसका रूट परमिट बदला गया है और न ही उस सड़क की मुरम्मत हो रही है जिस कारण सै लोग बेरोजगार हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसी तरह से पी ० डब्ल्यू ० डी ० विभाग के बारे में एक बात और कहूंगा कि वहां पर पैसे की बड़ी वेस्टेज हो रही णै। गोदामों में खाली ड्रम हर जगहों पर पड़े हुए हे और सरकार उनकी नीलामी नही कर रही है। उनकी बोली कम से कम क्वार्टरली होनी चाहिये। वहां पर इसीलिये चोरी होती है। ड्रमो के ड्रम वहां से गायब हो जाते हैं और बिकते हैं। इसीलिये नी लामी नही होती। अगर सड़कों पर तारकोल यूज हो और वह भी सही तरीके से यूज हो तो सारे के सारे खाली ड्रम बिक सकते है जिससे सरकार को काफी पैसा मिल सकता शै और जिसका असर हमारे बजट पर भी पड़ सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस चोरी को रोके और कोई ऐसा तरीका अपनाए जिससे कम से कम क्वार्टरली खा ली ड्रमों की नीलामी हो जाया करे। इसी तरह से हुड्डा की बात भी करना चाहूंगा कि इन्होंने डिस्क्रिशनरी कॉटे में से लगभग 3600 प्लाट्स अपने खास लोगों को या अपने चहेतो को दिये है। कईयों को पैट्रोल पम्प के लिये प्लाट दिये है। जैसे चौधरी लहरी सिंह जी है, उनको पंचकुला में

और श्री जगदीश नेहरा को पैट्रोल पम्प केलिये सिरसा में प्लाट दिया गया है। (विध्न) डिप्टी स्पीकर महोदय, मन्त्री जी खुद कबूल कर चुके हैं और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नही है। (विध्न) तो मैं कह रहा था कि हुड्डा जो जमीन एक्वायर करता है उस पर दस–दस साल तक कोई काम नहीं होता। इनको चाहिए तो यह कि एक साल में एक्वायर कर लें और उस पर उसी साल काम शुरू कर दें। इनको यह भी चाहिए कि एक्वायर की गई जमीन का किसान को पूरा मूल्य दें और जिसकी जमीन एक्वायर होती शै, उसके लड़के को नौकरी भी दे। चौधरी देवी लाल ने अपने समय में यह फैसला किया था कि जिसकी जमीन एक्वायर की जाएगी, उसको वहां पर एक प्लाट दिया जाएगा। वह बहुत अच्छी स्कीम थी लेकिन आज कुछ भी नही किया जाता। जिन लोगों ने प्लाट ले रखे है, उन पर मकान नही बनाए, उनको बार–बार एक्सटैन्शन दी जाती है। यह सारा काम मुनाफाखोरी के लिए किया जाता है। चाहिए तो यह कि यदि कोई मकान नहीं बनाता तो उससे प्लाट सरैडर करवाया जाए और किसी दूसरे को दिया जाए।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने शिक्षा का जनाजा निकाल रखा है क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी का शिक्षा के प्रति लगाव नही है। वर्ष 1994–96 में एक भी स्कूल अपग्रेड नही हुआ। कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं बना। यह मैं आपकी रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। आप इकनौमिक सर्वे में पढ़े। वर्ष 1990 में उस समय की गतिशील सरकार ने शिक्षा के

लिए 2389 परसैटं बजट रखा था लेकिन वह 1994–95 मैं घट कर 16.71 परसैंट रह गया। ये गुप्ता जी के आकड़े मैं आपको बता रहा हू। फिर 1995–96 में तो ताज्जुब की बात है कि वह शिक्षा पर खर्च 846 परसैंट रह गया। यानी जहां 1990 में वह बजट का 24 परसैटं था, आज वह साढ़े आठ परसैंट से भी कम रह गया है। हमारी सरकार ने 27–3– 1991 को 350 स्कूल अपग्रेड किए थे, लेकिन अब तक इनके राज के लगभग चार सालों में उतने स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। हमने जो स्कूल अपग्रेड किए थे, उनकी लिस्ट भी आ गई थी, लेकिन उसके बाद इतफाक से हमारी सरकार नही रहो। उस समय गवर्नर साहब ने कहा था कि इन स्कूलों का जुलाई से चाल कर देंगे लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वे स्कूल नही खुलेगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारे तो चलती रहती हैं लेकिन मुख्य मन्त्री बदलते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल को हम भी यहां बैठेंगे और आपकी तरह हम नहीं करे गे। इसी तरह से बिल्डिग फंड के लिए एक–एक लाख रुपया, एक स्कूल के हिसाब मे, बीस करोड़ रुपया साल का दिया जाता था लेकिन अब कोई पैसा नहीं दिया जाता। पी० डब्ल्यू ० डी ० वाले उनकी रिपेयर नही करते क्योंकि गुप्ता जी उनको धन नही देते। हमारी सरकार के समय नौलथा में एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग सैंटर मंजूर हुआ था लेकिन चार साल हो चुके हैं, उसका कोई जिक्र नही है। सुनने मैं आया है कि इनके चहेते विधायक उसको दूसरी जगह बदलवाना चाहते हैं। इसी तरह से सिवाह गांव में नवोदय स्कूल के लिए 25 एकड़

जमीन दे रखी है, उसका भी कुछ पता नहीं। ये लोग यहां पर नकल विरोधी प्रचार करते है। सुशीला बहिन इस सरकार के धिनौने कामों की वजह से इस नकल विरोधी बात की शिकार हुई। उसने मुख्य मन्डी के चहेते डी ० एस० पी ० के लड़के को नकल मारने से रोका था। उसको नकल नहीं मारने दी। अभी गोहाना के अन्दर इनकी पार्टी के प्रधान हैं। मैं उनका नाम नही लूंगा। अगर नाम लूगा तो इनको तकलीफ हो जाएगी, वह दुर्भाग्य से एम० पी ० भी है। उनकी लड़की नकल मार रही थी। पहले जो फलाईग स्कवैड आई, उसको कहा गया कि यह धर्मपाल जी की लडकी है, वह चले गए। उनको ऐसा लगा कि हम कुछ करेंगे तो कही सुशीला जैसा काण्ड न हो जाए। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री सदस्य से मेरा अनुरोध है कि इनको ऐसे एलीगेशन नही लगाने चाहिएं कि चौधरी धर्मपाल जी की लड़की नकल करते हुए पकड़ी गई और फिर कहते है कि कही सुशीला जैसा काण्ड न हो जाए। इनको पता होना चाहिए कि सुशीला काण्ड मे जिनको पकड़ा था, उनके बारे में कह दिया गया है कि उनका कोई दोष नही है। कल उनकी जमानत भी हो गई।

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि उनकी लड़की नकल मारते हुए पकड़ी गई और एस० डी ० एम० ने पर्चा दिया। अगर कोई नकल मारता हो, कोई दिक्कत नही उसका केस बन जाए लेकिन उसको बचाने की कोशिश की गई और जो बचाने की कोशिश की गई, उसका हम

इजहार कर रहे हैं। इस सरकार की स्कूलों में कलर टी ० वी ० देने की योजना है और यह सरकार उन स्कूलों को टी ० वी ० देगी जिनमें बिजली नही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैचिंग ग्रांट के लिए बजट में जो पैसा रखा गया हे, वह बहुत कम है। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने 1979–80 में एक स्कीम बनाई थी कि मैचिंग ग्रांट दी जाए ताकि गांवों की स्वैच्छिक सस्थाएं पैसा इकट्ठा करे और वह गांवों और शहरों का विकास कर सके। वर्ष 1989–90 में हमारी सरकार ने इस काम के लिए 10 करोड़ 90 लाख रुपए दिए और 1990–91 में 7 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए। वर्ष 1991–92 में 3.62 करोड़ रुपए दिए गए, वर्ष 1992–93 में 21 करोड़ ओर 1993–94 में 1.46 करोड़ दिए गए। फिर 1994–95 में इस सरकार ने रिकार्ड तोड़ दिया, केवल 1.52 करोड़ रुपए दिए है। कहते है बजट की वुद्धि 21 परसैट है और मैचिंग ग्रांट उसी स्पीड से उल्टे क्रम से घट रही है। इस सरकार का ध्यान विकास के कार्यो पर नही है। 27–3– 1991 को ग्रामीण शिक्षा प्रसार समिति, इसराना ने कालेज बनाने के लिए 5 लाख 40 हजार रुपए सरकार के पास जमा करवा रखे हैं। आज तक वहां पर कालेज नही बनाया गया है। अगर वे उस पैसे को किसी बैक में डाल देते तो वह पैसा डबल हो जाता। यह सरकार वह पैसा लिए बैठी हैं, उसको डबल नहीं करती। लड़कियों के स्कुलों के लिए तीन गुणा पैसा नहीं दिया जाता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से आज यह सरकार उद्योगपतियों को बहुत तंग कर रही है। उसकी कोई मिसाल नही

है। जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने निर्णय लिया था कि जो उद्योगपति बिजली न मिलने के कारण या बिजली की कमी आ रही हो, तौ अपना जनरेटर लगाएगा, उसको सबसिडी दी जाएगी। उस समय हमारी सरकार ने 50 हजार रुपए से बढ़ा कर 15 लाख रुपए सबसिडी की थी। वह सबसिडी कटीन्यू तो है लेकिन उसको ये मंद करने वाले हैं। पिछले तीन साल से किसी भी उद्योगपति को सबसिडी नहीं दी जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, 1200 रुपए पर के० वी ० ए० के हिसाब से सबसिडी दी जाती थी। तीन जिलो मे एक उद्योग कुंज खोलने वाले है और उसमें 10 कमरे होते है। उस तीन जिलों के उद्योग कुंज मे 10 आदमी रौजगार पाएंगे। इस तरह से आप कितने लोगों को रोजगार दे पाएगे। आप जनता को क्यों बहका रहे हैं? आप कहते हैं कि एक परिवार के एक आदमी को नौकरी देगे। गुप्ता जी थोड़े दिनों में आपका जनाजा निकलने वाला है। आप देखे नौकरी किसको मिलेगी और किसकी नौकरी मिली एं। पता नही कैसे ये लुभावने–सुभाबने नारे दे देते हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने सरकार तो बना ली। जब जनता इनकी चिमटों से खाल उतारेगी, तब इनको पता लगेगा। एक ऐसी स्कीम चलाई है कि 25 लाख रुपए की सबसिडी एग्रो बेस्ड इडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज को दी जाती है, लेकिन तीन साल से वह सबसिडी किसी को नही दी गई है। यह सरकार उद्योग. पतियों को कहती है कि आप एच० एस० आई० डी ० सी ० मे लोन ले लें। लोन तो उनको दे देंगे लेकिन सबसिडी रिलीज नही करेंगे। अगर लोन देने

की सरकार की क्षमता है, तो सबसिडी क्यों नही दी जाती ? गुप्ता जी, आप खुद व्यापारी हैं। आप व्यापारियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे है? आप कहीं चूक रहे हो या मारा पैसा आप अपने घर ले जाते हो। बड़ी फैक्टरी लगाने के बारे मे इन्होंने एक स्कीम चलाई है कि हुड्डा से 10–10 किल्ले आधी कीमत पर जमीन खरीदे और जो कम्पनी 100 करोड़ रुपए की इनवैस्टमैंट करेगी उसको आधे भाव की रियायत पर जमीन दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, एक छोटा बेरोजगार यदि 500 गज का प्लाट लेगा तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा और पूरा पैसा भी रु महीने के अन्दर देना पड़ेगा। एक रणबीर सिह एडवोकेट है। उसको एक प्लाट मिला था। वह बेचारा प्लाट के पैसे नही भर पाया क्योंकि लैड की जो कीमत है, उसको हरियाणा फाइनैंस कारपोरेशन ने नहीं माना। उस वकील को चार हजार रुपए का नुक्सान हो गया क्योकि उसको लोन देने के लिए टाल कर दी। बेचारे ने प्लाट लेने से मना कर दिया और 5–6 महीने जो पैसा उसका पडा रहा, उसका उसे दण्ड भुगतना पड़ा। मिनरल्ज की माईन्ज भी यह सरकार अपने चहेतों को, रिश्तेदारो को, एम० पीज० को और उनके साले आदि को दे रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मौजूदा सरकार प्रदेश की सम्पत्ति को चारों तरफ से लूट रही है। चाहे हुड्डा के प्लाट्स हैं या पहाड की जमीन पै, या किसी नदी की जमीन है। ये सब पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं।

जहां तक बिजली का संबंध है, सारे प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब है। हमारे यहां पर 88 हजार ट्रांसफार्मर्ज

वर्किंग कंडीशन में चलते है लेकिन आज के दिन इनमें से 21 हजार 500 ट्रांसफार्मजं ऐसे हैं, जो वर्कशाप में हैं और 10 हजार ऐसे हैं जिन पर पशु बंधते हैं, यानि वे खूंटे का काम करते हैं। इस बारे में मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि इनको उठा कर इनकी रिपेयर आदि करवाई जाये। जहां तक रिपेयर की बात है, बिजली बोर्ड खुद रिपेयर करने कीं बजाये प्राईवेट लोगों से ज्यादा पैसा देकर रिपेयर करवा रहा है। प्रदेश के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 1700 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। इतना बड़ा घाटा शायद ही किसी बिजली बोर्ड को हो। मौजूदा सरकार बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई कार्य नही कर रही। हमारी सरकार ने 5वीं यूनिट चालू की थी और छठी यूनिट के लिए काम शुरू हो गया था। इस बात के गवाह चौधरी वीरेन्द्र सिंह जो भी हैं क्योंकि उस समय ये उस मंत्रिमंडल में भागीदार थे। अब ये अपनी फर्मो से यानि अपने देश की कम्पनियो से बिजली का सयंत्र लगवाने की बजाय इसराईल की कम्पनी से काम करवा रहे हैं। इस बारे में होना तो यह चाहिए था कि यदि हमारे देश की कोई कम्पनी जैसे एन० टी ० पी ० सी ० या बी ० एच० ई० एल० बाहर की कम्पनी की बजाय 20 परसैंट अधिक पैसा लेती है तो भी यह काम अपनी ही कम्पनी को दिया जाना चाहिए ताकि देश का पैसा देश में रहे। लेकिन ऐसा करने की बजाये ये पानीपत थर्मल प्लांट का काम बाहर की कम्पनी से करवा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इस इजराईल

की कम्पनी को यह काम सारे रूल्ज की वायलेशन करके दिया जा रहा है।

अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी में टयूब– वैल्ज की 80 फुट की गहराई तक बिजली का रेट 43 रुपये प्रति हार्स पावर ले रहे हैं और दूसरे एरियाज जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाला, में 80 फुट की गहराई तक 60 रुपये प्रति हार्स पावर लिए जाते हैं। पानी तो इनका भी नीचे गया है। जो ऐसा भेदभाव है, यह नहीं होना चाहिए। जिस किसान के टयूब– बैल की मोटर 50 फुट से नीचे रखी हुई है, उसको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। बजट में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। गुप्ता जी उन किसानों की तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ 2 क्षेत्रों का जिंक्र किया गया है। जहां–जहां पानी नीचे है, उन सबको यह सुविधा मिलती चाहिए चाहे वह झज्जर है, चाहे रोहतक जिला हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं टैक्नीकल एजुकेशन पर कुछ कहना चाहूंगा। श्री छतर पाल जी मंत्री बनाए गए थे और चौधरी भजन लाल जी ने उनको ऐसा महकमा दे रखा था कि वे चलते–फिरते घोषणा करते थे। उन्होंने शौर्ट कोर्स डिप्लोमा घोषित कर दिया। शाहपुर गांव में एक कोर्स का ऐलान किया। 2 महीने तक स्टाफ वाले वहां पर रहे। पता नही, वहा पर क्या करते रहे? जो पैसा उन पर खर्च हुआ, वह सरकारी था या मुख्य मन्त्री जी का अपना पैसा था। वहां पर कोई भी आई० टी ० आई० या ट्रेनिंग इन्हटीच्यूट नहीं खुला। एक बार तेजेन्द्र सिंह मान जा कर

आए। डिप्टी स्पीकर सर, सीख गांव मेरे हल्के में पड़ता है वहां पर हमने एक आई० टी ० वोकेशनल एजुकेशन इन्स्टीच्यूट बनाया था। अपने हल्के में उसके लिए फण्ड एलोट करवाया था। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उस पर स्टे ले लिया। उसका पत्थर तेजेन्द्र सिंह मान जी ने 3 साल पहले रखा था। इस बारे में जब मैं सवाल पूछता हूं तो जवाब मिलता है कि धन की उपलब्धि नही है। जब सरकार के पास धन ही नहीं है, तो यह पत्थर क्यों लगाए जाते हैं। डस प्रकार के पत्थर लगाने की भी सरकार को मनाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः कादयान साहब, आपका टाईम खत्म हो गया है इसलिए अब अपि वाईड अप करिये।

श्री सतबीर सिंह कादयानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। चौधरी देवी लाल जी ने एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत किसानों की जमीन के साथ–साथ पी ० डब्ल्यू० डी ० या नहरों के महकमे ने दरखत लगाए हैं। वह 10 फुट की हद तक है। किसान के लिए कानून के मुताबिक उसका मुआवजा मुकर्रर किया था क्योंकि किसान को उससे फायदा नही बल्कि उल्टा नुकसान होता था लेकिन इस सरकार ने उस सुविधा से सारे किसानों को वंचित कर दिया है। पानीपत में मुख्य मन्त्री जी का दौरा था। पानीपत के उद्योगपतियों के गेट सड़क पर लगे हुए हैं जो कि 20–20 साल से लगे हुए हैं। उनको नोटिस दे दिये और व्यापारियों ने कोर्ट से जा कर जमानत करवाई। उनका कसूर यह था कि उन्होंने चन्दा नही दिया। जिसने चन्दा नही दिया,

उसको कह दिया तू जी ० टी ० रोड से नहीं जा सकता कहीं और से जाओ। मुख्य मन्त्री जी और रास्ता उनको कहां से देंगे? क्या उनको कोई जहाज देंगे? मुख्य मन्त्री जी, जिसका गेट ही सड़क पर है, उसको रास्ता तो देना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्षः कादयान साहब, प्लीज आप अपनी बात को समाप्त करके अपनी सीट पर बैठें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी कुछ बातें और कहनी है इसलिए मुझे थोड़ा समय और दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, दरख्तों का कटान हुआ है। इसके साथ ही आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने आई० ए० एस० में, एच० सी ० एस० और सर्बोडिनेट आफिसर्ज को परमोट किया था। उन 11 में से केवल दो को पोस्टिंग मिली है जिनमें से एक तो मुख्य मन्त्री जी के ओ० एस० डी ० है और दूसरे एक अन्य अधिकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, जगहे खाली पड़ी हैं लेकिन वे बेचारे बेइज्जती महसूस करते हुए अपने पुराने पदों पर बने हुए है। उनकी परमोशन हो गई और उनको केडर मिल गया लेकिन सरकार उनको पोस्टिंग नही दे रही है क्योंकि इनमे कुछ लोग ऐसी जाति के है, जिनसे मुख्य मन्त्री जी घृणा करते है। उनको मजबूरी मे प्रमोट तो करना पड़ा परन्तु उनको पोस्टिंग नही मिली। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री एक जाति से घृणा करते हैं लेकिन घृणा तो ये लोग करते थे। ये अपने जमाने को याद करे। भजन लाल तो 36

बिरादरी का नेता है और 36 बिरादरी को साथ ले कर चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पोस्टिंग देने का ताल्लुक है, सब को उनके पदो पर पोस्टिंग दे कर लगाएंगे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कादयान साहब, अब आप बैठे क्योंकि आपको काफी समय मिल गया है। अब आप और न बोलें और अपनी जगह पर बैठें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 10 मिनट का समय और दीजिए मुझे अभी काफी बाते कहकी हैं।

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी सीट पर बैठे। आप अपनी यात को एक मिनट में खत्म करे।

श्री सतबीर सिंह कादयानः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी गवर्नमैंट ने किसानो की तरक्की की। हरित और श्वेत क्रान्ति आई। लोगों को लोन दिए गए। इन लोगों ने लोन नहीं दिए। किसानों को पशुओं की बीमारी के लिए दवाईयां नही मिल रही हैं। मेरे हल्के मे एक वी ० एल० डी ० ए० की लापरवाही से पटवारी की छः भैसे मर गई। उसका नाम राम फल था। हमने इस मामले को ग्रिवैन्सिज कमेटी में उठाया (विघ्न) उसके खिलाफ इन्कवायरी हुई और उसको वहां से बदल कर 1–2 किलोमीटर दूसरी जगह पर लगा दिया (घण्टी) एक गांव से बदल कर 1–2 किलो मीटर दूर लगाने से उसको क्या फर्क पड़ा? (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः अब आप अपनी– सीट पर बैठे।

श्री सतबीर सिंह कादयानः ....

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए अब आप जो बोलेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं आएगा। कादयान साहब, जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। कादयान साहब, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठे।

श्री सतबीर सिंह कादयानः ....

श्री उपाध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठ जाए यह कुछ भी रिकार्ड नही किया जा रहा है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः ....।

श्री उपाध्यक्षः कादियान जी आप बैठ जाएं। मक्कड़ साहब आप बोलें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः ....

श्री उपाध्यक्षः यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। मक्कड़ जी, आप शुरू करे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वित्तमंत्री जी ने जो परसो बजट पेश किया है, मैं उसके बारे मे आपको बताना चाहता हूं कि यह बजट कर रहित है। बिक्री कर में छूट और विकास के बारे में कितना ही अच्छा बजट है। यह एक बहुत ही सराहनीय बजट है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में हर वर्ग के तथा हर क्षेत्र के विकास की बात की गई है। इसमें हर बात को लिया गया है। वित्त मंत्री जी ने बताया कि बजट में हर प्रकार से, चाहे वह सड़क है, चाहे वह स्वास्थ्य के बारे में है, एजुकेशन के बारे मे है, पीने के पानी की बात है,

महिलाओं के विकास की बात है, सबके लिए प्रावधान है। आज हम समझते हैं कि इससे लारी यह स्टेट दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। आप सभी समझते है कि क्य कभी इस प्रदेश की जनता ने झारे इन साथियों, जो अभी बोल रहे थे और टौंट कस रहे थे, का राज हरियाणा मे बनवाया तो इन्होंने क्या किया? यह बात हम सभी जानते है। आज यह बजट का विरोध करते है। यह बात ठीक है कि इस किस्म की बातें विधान सभा में नहीं होनी चाहिएं जैसा कि हमारे एक साथी भी कह रहे थे। लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि पिछले चार सालों के राज में इन्होंने कही भी हरियाणा में विकास के नाम की कोई बात नही की सिवाए लूट खसौट के और सिवाए नाजायज कथ्यों के और कोई इनका विचार ही नही रहा। लेकिन आज इस बजट में जितनी भी अच्छी बातें होनी चाहिए थी, वह सब दर्शायी गयी है और आगे आने वाले समय में जो काम होंगे, उनके बारे में भी बजट मे बताया गया है जो एक सराहनीय बात है। जैसा कि सड़कों के बारे मे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और लोक निर्माण मती जी ने हाउस को बताया कि 'कितनी सड़कें जिनको हमारे ये साथी पीछे बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ गए थे, को रिपेयर कराया है। काफी सड्कों के बारे में, यहां पर उन्होंने बताया था जिसमें मुरथल से लेकर करनाल तक और स्टेट हाई–वे नं० 1, 2 और 8 हैं, जिन पर आज काम हे चल रहा है और इनका रास्ता चौड़ा बनाने की स्कीम बनायी गयी है। ऐसा करने से एक्सीडैन्ट भी कम होंगे और सड्कों पर आने–जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही साथ

नयी' सड्कों का निर्माण भी आज की सरकार कर रही है। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें ऐसी हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती हैं, उनको भी बनाया जाए। इनकी यह बात ठीक है कि हरियाणा मे हर गांव सड़क से मिला हुआ है लेकिन कुछ और सड़कें भी बनाना जरूरी है ताकि किसानों को मंडियों में जाने के लिए समय कम लगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में खरकड़ा से अनाज मंडी की सड़क जो कि तीन किलोमीटर तो बनी हुई है लेकिन अभी 6 किलोमीटर और बनायी जानी है को पूरा किया जाना चाहिए इसके अलावा दूसरी सड़क ढानी जाटू से अनाज मंडी तक है और तीसरी सड़क सुल्तानपुर से अनाज मंडी तक की बननी है। इसी तरह से एक सड़क जी ० टी ० रोड से रामपुर स्कूल तक बननी है। उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसी सड़के है जिनसे किसानो को मंदी मे और शहर में जाने के लिए पाच या छः किलोमीटर व। कम रास्ता तय करना पड़ता हैं इसलिए ये सड़कें बनायी जानी बहुत जरूरी है। जैसा वित्त मंत्री जी ने बजट में बताया भी है कि इस मद में हम काफी पैसा खर्च कर रहे है। मैं समझता हू कि वे यह सड़कें भी जरूर बनाएंगे ताकि मेरे हल्के के किसानो को काफी सुविधा मिल सके। इसी तरह से इरीगेशन के बारे में है। मेरे अपोजीशन के भाईयो ने यमुना ऐग्रीमैंट के बारे में काफी कुछ कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ताजेवाला हैड पर हमारी कमेटी गयी थी। यह हैड सौ—साल से ज्यादा पुराना है और उसकी गारंटी की मियाद भी खत्म हो चुकी है। इसलिए चौधरी भजन लाल जी ने और इरीगेशन मिनिस्टर ने

अपने अथक प्रयासों से यह समझौता लागू कराकर हथनी–कुड बैराज के बनाने का रास्ता साफ किया है। यह बैराज बनना जरूरी है क्योकि इसके लिए करोड़ों रुपये की मशीनरी काफी सालों से ली हुई पड़ी है। उस मशीनरी को जंग लग रहा है और उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस बेकार पड़ी हुई मशीनरी पर जो पैसा हरियाणा सरकार का खर्च किया गया था, उसका इस्तेमाल करने व पानी को कमी को पूरा करने के लिए ही यह समझौता सरकार ने किया है। इन्होने तो अपने राज में इसके लिए कुछ भी नही किया। चाहे वे चौधरी बंसी लाल ही क्यों न हों जो चीफ मिनिस्टर रहे हों, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये भी इसका यूं ही ऐतराज कर रहे हैं। हमने ताजेवाला से लेकर सारी नहरों का सर्वे किया था। जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, कि हम बहुत कम पानी इस्तेमाल कर रहे थे। सर, हथिनी कुंड बैराज के बनने से हरियाणा के किसानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा और फिर ताजेवाला हैड कभी भी टूट सकता है, कभी भी बह सकता है। अब यह जो समझौता किया है, यह बहुत सराहनीय है, हम तब को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। विरोधी पक्ष के भाई इसका ऐतराज करते है जो कि गल बात है क्योंकि यह हरियाणा के हित की बात है। इससे हरियाणा के किसान को बहुत लाभ होगा। जब तक नहरों की सफाई नही हो जाती किसान की टेल तक पानी पहुचना मुश्किल है। 180 करोड़ रुपया नहरों और छोटी माइनरो की सफाई के लिए दिया है। यह काम अब शुरू हो रहा है। मैं इसकी भी सराहना करता हूं। हरियाणा

सरकार को किसान की चिंता है और किसान के टेल तक पानी पहुंचाने के लिए यह सरकार पूरा प्रयास कर रही है। एम० आई० टी ० सी ० खालें पक्की कर रही है। इससे कोई ढाई हजार क्यूसिक पानी की बचत हुई है। इससे कितने हैक्टेयर फसल ज्यादा हुई, यह एक उदाहरण है। आज हरियाणा का किसान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज हमारी उपज 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा होने जा रही है। उसका यही कारण है कि इरीगेशन सिस्टम ठिक होने की वजह से किसान के खेतों में ज्यादा पानी जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के में काफी खालें तो पक्की हो चुकी हैं। कुछ जो रह रही हैं, उनको भी पक्का कराया जाए। खालें पक्की होने से किसान के पानी की बचत होती एं। पानी की सी पेज नही होती। मेरे हल्के मे धमाणा 'माईनर के लैफ्ट और राईट 9 हजार टेल हैं। इसी तरह कुछ और माइनर्ज हैं जिन में पानी की बड़ी दिक्कत है। जैसे गढ़ी माईनर, पुट्ठी माईनर और मनूमरा माईनर व बीड़ माईनर शै जिनमें पानी टेल पर नहीं पहुंचता। मैं चाहूंगा कि इनका दोबारा सर्वे कराकर उनकी लाईनिंग अच्छे लैवल पर कराई जाए जिससे पानी सही ढंग से टेल पर पहुंचे। ग्रामीण विकास और शहरी विकास के बारे में भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। 20–20 लाख रुपये हर एम० एल० ए० के अपने क्षेत्र के विकास के लिए रखे हैं। पहले यह राशि मिनिस्टरों के लिए तो रखी जाती थी पर चौधरी भजन लाल जी ने इम तरह से विधायकों का आदर करके एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि नये साल की

राशि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी विधायक के हल्के में भिजवाए ताकि विधायक अपने हल्के में विकास के काम सही ढंग से करा मकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गांवों के अंदर अभी पंचायती राज लाए हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी का यह सपना था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक सपना देखा था कि देश में पंचायती राज होगा और ताकत का बंटवारा किया जाएगा। राजीव गांधी जी ने इसे पूरा करने के लिए स्कीम बनाई। यह ठीक णै कि आज वे हमारे बीच नहीं है। मगर आज हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपने को साकार बनाने के लिये, पंचायती राज को लागू करने के लिये इस बिल को पास करवाया और उसके बाद सबसे सराहणीय कार्य हरियाणा सरकार ने यह किया जो इस को सब से पहलें लागू किया। इससे महिलाओ को राजनीति में आने का पूरा मौका मिलेगा और 173 महिलाएं पचायत और नगर पालिकाओं की मैम्बर बन सकेंगी। उनको इस प्रकार की पूरी पावर्ज देने की कोशिश सरकार ने उग विल के द्वारा की है। (शोर)

12.00 बजे

श्री धीरपाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे माननीय साथी ने पंचायत के चुनावो की चर्चा की है कि बड़े अच्छे ढग से सम्पन्न हुए है लेकिन जब पंचायत, जिला परिषद वगैरह के लिये चुनाव प्रचार हो रहा था, तो उस वक्त ये नारे दिये जा रहे थे कि जो पिलाएगा देसी, उसको वोट

कैसी, जो पिलाएगा रम, उसको वोट कम और जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी। यह तो इनके चुनावों का हाल था (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हू कि जो आदमी शराब पीता है, उसका नाश हो जाता है, आत्मा का नाश हो जाता है। तो इस तरह की इन लोगों की धारणा हो तो फिर ये लोकतन्त्र मै इस प्रकार की चर्चा करे कि चुनाव बड़े ही निष्पक्ष और सही ढंग सै हुए हैं, यह कहना उचित नही है,। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, यह कोई प्यायंट आफ आर्डर नही है। यह जो इन्होंने यहां पर चुनाव प्रचार में शराब से सम्बन्धित। नारों का जिकर किया है, यह सब कुछ इन्ही के पार्टी वर्कर्ज करते होंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रकार का कभी प्रचार नही किया गया और यह सब कुछ इन्ही लोगों की सरकार का ही काम होता था। इस सब के लिये ये लोग ही जिम्मेवार हैं। हमेशा ही इन्होंने इस तरह के कारनामे किये हैं और अब भी करवा रहे हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्ही के नेता के पास शराब बनाने के लाईसैस हैं। तभी उन्होने अपनी शराब बिकवाने के लिये ऐसा करवाया है। (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी पार्टी ने यह निर्णय किया। हुआ है कि जो आदमी शराब पीयेगा उसको चुनाव के लिये पार्टी टिकट नही दी जाएगी। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, शराब पीने के लिये अहाते तो इन्हीं की सरकार के वक्त मे खोले गये थे। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः अहाते तो हमने रण। खुलवाये थे लेकिन बिना टैक्स के शराब तो आपके वक्त में बिक रही है। (शोर)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो इधर–उधर की बातो में इन लोगों ने मेरा समय बरबाद कर दिया है, यह टाईम मेरे टाईम में से निकाल दिया जाए और मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। नेहरा साहब ने कहा कि अहाते तो इन्हीं की सरकार के वक्त में खोले गये थे, जिससे शराब पीने वालों को बढ़ावा मिला था। तो फिर ये किस मुंह से यहां पर शराब के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके लिए यह अच्छी बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं शहरी विकास की बात करना चाहता था, इन्होंने बीच में टोक दिया। हमारे आदरणीय प्रधान मल्टी जी और हरियाणा सरकार भी यह बिल ला रही है। महिलाओं की भलाई के लिये सरकार बड़ा कुछ करने जा रही है। जहां पहले महिलाएं मैला ढोने का काम करती थीं, अब वह बिल्कुल बन्द हो जाएगा। पहले सीवरेज की व्यवस्था ठीक नही थी। शहरों में काफी ऐसी कालोनियां हैं जहां पर इस प्रकार की लोगों को दिक्कत आ रही है और वहां पर सीवरेज का कोई सिस्टम नही है। अब सरकार यह सिस्टम हर जगह पर करने जा रही है जिससे महिलाओं को मैला नही उठाना पड़ेगा। अभी पंचायती राज बना है। इस तरह की

पंचायतों को पावर्ज दी गई हैं। उसमें अब घर–घर में गांवों में लैट्रीन बनाने का प्रावधान किया गया है। काफी गांवों में अभी तक नही बनी हैं। उनमें भी बनाने की व्यवस्था की जाएगी। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा बहुत सारा समय तो इन लोगों ने बरबाद कर दिया है। मुझे कम से कम अपने हल्के की बात तो कह लेने दीजियेगा। तो मैं शहरी विकास के बारे में यही प्रार्थना कर रहा था कि शहरों को भी कुछ ग्रांट दी जाए। शहरों में ऐसी–ऐसी नगरपालिकाएं हैं, जिनकी ज्यादा आमदनी नही है और वे अपने स्टाफ को पूरी तनखाह भी नहीं दे सकतीं। उनके अन्दर हांसी भी शामिल है। उनको कुछ ग्रांट दी जाए ताकि वे विकास के कार्य कर सकें। आज मार्किट कमेटियों के पास पैसा है। जैसे पहले इन्होंने आदेश दिए थे कि शहर की सड़को का विकास मार्किट कमेटी करेगी। मैं उन सड्कों की बात कर रहा हूं, जो अनाज मडी या सब्जी मंडी को जाती हैं। ऐसी काफी सड़कें है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शहरी सड्कों का काम मार्किट कमेटियों को दिया जाए। जो सड़के पी ० डब्ल्यू० डी ० बनाता है, वहां पर उनके पानी के निकास का काम भी उन्ही को दिया जाए ताकि वे सड़कें बनने के बाद चलने के काबिल हो। पानी का निकास न होने के कारण नई सड़क भी दो महीने के बाद वैसी ही हो जाती है। इस काम के लिए चाहे पैसा मार्किट से ले लिया जाए लेकिन पी ० डब्लयू ० डी ० महकमा ही इस काम को करे। एजूकेशन के बारे में मन्त्री जी ने काफी विस्तार में बताया कि एक सौ नए स्कूल खोले गए तथा 40 स्कूल अपग्रेड किए गए। मैं

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा मे शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हो रहा है। मेरे हल्के में धनेरी सिंधवा और खरबला में हाई स्कूल है इनको दस–जमा–दों मे अपग्रेड किया जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भांडाहेड़ी गांव के अन्दर स्कुल के लिए लोगों ने 26 कमरे बना दिए थे। पिछले राज में दो चीफ मिनिस्टर उस गांव मे बार–बार गए और उन्होंने उस स्कूल को मन्जूर कर दिया लेकिन वह स्कूल नही खुला। वहां पर इन्हेने तीन बार लड्डू भी बंटवाए। उसके बाद मैं बहिन शान्ति राठी को उस गांव मैं ले कर गया। ये 26 कमरों को देख कर हैरान रह गईं। इन्होंने एक हफते मे वह स्कूल खुलवा दिया। तो आप ही अन्दाजा लगाएं कि पिछली सरकार शिक्षा मे कितनी दिलचस्पी रखती थी। तीन बार लड्डू बटवा दिए और एलान करने के बाद भी स्कूल नही खुला था। हमारी बहिन जी ने वहां पर प्राईमरी स्कूल खुलवाया, मैं इनका धन्यवाद करता हू। मेरा निवेदन है कि वांडोहेड़ी तथा ढाणा पुर के स्कूलो का दर्जा भी प्राईमरी से मिडल तक किया जाए क्योकि वहां पर काफी दूर–दूर गांव पड़ते हैं। कुछ स्कुल शहरों में भी हैं, जिनको अपग्रेड किया जाए। जैसे राम पुरा के स्कूल को भी प्राईमरी सै मिडल किया जाए। उसकी मिडल स्कूल के हिसाब से बिल्डिंग बना दी गई है। इसी तरह से कुछ स्कूल मिडल से हाई भी किए जाए। उनकी लिस्ट मैंने पहले ही दे रखी है। एक ढाणी राजू के स्कूल को मिडल से हाई कर दिया जाए। (घंटी) मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी सरकार बहुत बधाई की पात्र है कि इसने पिछले दो सालों से यहां पर कोई

उग्रवाद की घटना नही होने दी। हमारी पुलिस ने इस पर बहुत अच्छा कन्ट्रोल किया है। अब उनका यहां पर नामों– निशान नहीं छोड़ा है। जो ये गोली की बात करते हैं वह बिल्कुल फिजूल की बात है। डिप्टी सीकर साहब, चौधरी बंसी लाल और ओम प्रकाश चौटाला ने यह लांछन लगाया कि नारनौल में पुलिस की गोली से वह लड़का मर गया। मैं इस बारे में आपके सामने उसकी हकीकत बयान करता हूं। नारनौल मेरे हल्के के साथ लगता हुआ हल्का है। वहां पर बी ० के० यू ० के लोग पत्थरों से ट्रैक्टर ट्रालियां भर कर लाए थे। यह मेरी आखो देखी बात है। पुलिस ने उनको बड़ी शांति के साथ रोका लेकिन वे लोग पुलिस का घेरा तोड़ कर नारनौल में पहुंच गए और उन्होने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उस समय कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए और एक शमशेर नाम का पढ्ने वाला बच्चा सिर मे पत्थर लगने से मर गया। ये मेरे भाई बार–बार यह कहते है कि वह पुलिस की गोली लगने से मर गया, यह ठीक बात नही है। पुलिस के पास जो हथियार होते हैं, वह कोई देसी छरी या देसी कट्टा नही होता। उनके पास पिस्तौल या थ्री नाट थ्री की गन होती है। जिसके सिर में थ्री नाट थी की गोली लगेगी और वह भी नजदीक से, तो उसका सिर बिल्कुल नही बचता और उससे कई आदमी जख्मी हो जाते है। आपने एक बात यह भी कही कि उसके सिर के मांस का एक टुकड़ा दिवार पर लगा हुआ था। सिर तो पत्थर लगने से भी फट सकता है। गोली लगने से तो सिर का निशान ही मिट जाता है।

आप ऐसी बातें कह करके हाउस को गुमराह न करे। मैं समझता है कि ये अपनी लोक प्रियता बड़ाने के लित ऐसी बातें कहते हैं।

चौधरी बलवन्त सिंह मायनाः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर क्रश। सरकार कहतीं है कि वह लड़का छत से गिर कर मरा है और ये कह रहे हैं कि पत्थर लगने से मरा है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः मैं कहता हूं कि वह लडका छत पर खड़ा था और उसके सिर में पत्थर लगा और वह नीचे गिर गया।

श्री उपाध्यक्षः यह मामला बार–बार उठ चुका है। इसलिए इस पर अब कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मक्कड साहब, आप वाईंड–अप करें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्षः मक्कड़ साहब, आप अपनी स्पीच खत्म करें। अब श्री पीर चन्द बोलेगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः ठीक है। डिप्टी स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसकी ताईद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री पीर चन्द (रतिया–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने परसों जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलते हुए अपने हल्के की कुछ बाते कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, यह तरक्की की निशानी है क्योंकि

गरीब आदमियों का इसमें खास तौर से ध्यान रखा गया है। म्यूनिसिपल कमेटीज, ग्राम पंचायत, ब्लाक समिति और जिला परिषद् के चुनावो मे महिलाओं के लिए 30 परसैटं रिजर्वेशन रखी गई है। यह बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हरिजन कल्याण निगम के बारे मे कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हरिजन कल्याण निगम के माध्यम से मिन्नी ट्रक खरीदने के लिए बी ० ए ० और मैट्रिक पास लड़कों को जिन की संख्या 50 के करीब है, 2 लाख 75 हजार रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से लोन दिया है। इसी प्रकार से 30 बच्चों के करीब जो लड़के बेरोजगार थे, फोटो स्टेट मशीन के लिए 1 लाख 7 हजार रुपया प्रति व्यक्ति का लोन दिया है, ताकि वे अपना काम चला कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी प्रकार हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी और कढ़ाई की ट्रेनिंग दी है। सरकार ने यानि हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि जो महिला सिलाई–कढ़ाई का काम सीखने के बाद अपना काम करना चाहती है, उसे 50 हजार रुपये तक का लोन दे दिया जाये और ऐसा लोन हम देते भी हैं। सरकार एक महिला को ट्रेनिंग देने पर 150 रुपया महीना देती है और 500 रपये माहवार खर्च आता है। सरकार ये सारे काम इसलिए कर रही है ताकि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वे ऊपर उठ सकें और गरीब आदमियो को लाभ हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतान चाहूंगा कि हमारी

सरकार आधे सै ज्यादा ध्यान गरीब व्यक्तियो और महिलाओ के उत्थान की तरफ दे रही है।

अब मैं अपने हल्के की बाबत बताते हुए कहना चाहता हूं कि 1977 से पहले रतिया में सिर्फ एक थाना और एक बी० डी ० ओ० का आफिस था। उस समय मैं भी चौधरी भजन लाल जी के साथ था। जब चौधरी भजन लाल जी 1979 में मुख्य मंत्री. बने तो मैंने उनसे रतिया की समस्याओ के बारे में निवेदन किया तो उन्होने वहां पर जो पहले 33 के० वी० का पावर हाउस था, उसको बढ़ाकर 132 के० वी ० का बनाया। इसी प्रकार से रतिया को तहसील का दर्जा दिया और वहा पर वाटर– वर्क्स बनाए गए जिससे वहां पर पीने के पानी की समस्या खत्म हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, इसमे कोई दो राय नही हैं कि रतिया और जाखल हल्के में वाटर वर्क्स लग जाने से और बिजली घर बन जाने सै बिजली और पानी की कोई कमी नही रही है। इस इलाके का नीचे का पानी बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से 1977 के बाद से अब तक वहां पर 500 से ज्यादा टय़्बवैल्ज लग गए है। यह खुशी की बात है कि आज सारे हरियाणा मे रतिया हल्के के अन्दर सब से ज्यादा अनाज पैदा होता है। वहां पर बहुत अच्छा और बढ़िया सीड इस्तेमाल होता है। (विघ्न) वहां पर घी की क्वालिटी भी सबसे बढ़िया है क्योंकि वहां बढ़िया नसल के दुधारू पशु हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा को वहा से अन्न और घी की सप्लाई हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहा पर जमीदार और मजदूर बहुत मेहनत करते हैं और वे अपनी मेहनत

से सारे इलाके को खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं और वहां की प्रगति में उनका पूरा हाथ है, इसीलिए वे लोग कामयाब हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बहबल पुर गांव जाखल और रतिया में पीने के पानी की कोई तकलीफ नही णै। चौधरी भजन लाल जी ने मेरी बात को मान कर वहां पर विकास कार्य करवाए हैं जिसकी वजह से वहां पर आज बिजली और पानी की कोई कमी नही है। बहबलपुर मे 33 के० वी ० का पावर हाउस लगाया है और नीमली में भी 33 के० वी० का पावर हाउस लगाया गया है जिससे इस इलाके के लोगों को बिजली में राहत मिली शै। ये सारे कार्य इस सर–कार के द्वारा किये गए है जो कि मेरे विचार से बहुत ही अच्छे काम हुए हैं।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कुछ कमियां भी हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हू। आज रतिया की आबादी 30–35 हजार के लगभग है। 1977 से पहले यहां पर 5 हजार के लगभग आबादी थी अब और आबादी बढ़ी है। म्युनिसिपल कमेटी भी बने। है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक बहुत बडी कमी है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। टोहाना और फतेहाबाद से होते हुए पंजाब का रास्ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहां पर रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा फाईनैस मिनिस्टर महोदय से निवेदन करता हू कि रतिया शहर की इस सड़क को फोर लेन

बनवाने के लिए विचार करे ताकि इस इलाके के अन्दर लोगों को सुविधा हो सके और ट्रैफिक कण्ट्रोल हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क की फोर–लेनिग बहुत जरूरी है। इसके साथ ही वहां पर रतिया में सीवरेज की बहुत अधिक आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, रतिया शहर 3–3 या 4–4 किलोमीटर तक बढ़ गया है। अब इतनी आबादी हो गई शै लेकिन आज भी औरतों और आदमियो को लैट्रीन बाहर जाना पड़ता है तो मेरा आपसे निवेदन शै कि वहा पर भी लैट्रीन का प्रबन्ध किया जाए। आज आबादी इतनी हो गई है कि गन्दगी भी फैलती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर यह दिक्कत न हो, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनको वहां पर सीवरेज का भी प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे 1977 के बाद रतिया में हैफेड का कम्पलैक्स बनवाया गया और उस पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए है। उस वक्त मैं उसका चेयरमैन था। उपाध्यक्ष महोदय, यह फैक्टरी दूर से ही चमकती है और इसको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि रतिया आ गया है। वहा पर तेल भी रिफाईन किया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी किस्म का होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक और भी कमी है कि वहां पर जो 30 बैड का अस्पताल है वह बहुत ही छोटा है। पिछले दिनों उसका शिलान्यास मुख्य मत्री जी ने किया था। इसके बाद तहसील की बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के समय में, उन्होने एक बस स्टैन्ड का पत्थर रखा था। इनकी सरकार दो साल तक रही और वह बस

स्टैन्ड नही बना सकी और वह पत्थर भी न जाने कहां पर गया है। मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए भी विश्वास दिलाया है कि ये वह भी बनवाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज इन तीनों का काम शुरू हो चुका है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको दिसम्बर 1995 तक पूरा करवा दे ताकि यह सब बनने के बाद गरीब आदमियो का भला हो जाए। (घण्टी)

श्री उपाध्यक्षः पीर चन्द जी, आर वाईन्ड–अप कीजिए।

श्री पीर चन्दः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने वायदा किया था और वह काम शुरू हो चुका है। लेकिन फोर–लेनिंग के बारे मे भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और कहा था कि 61 लाख रुपए उसके लिए मन्जूर हो चुके है। मैंने उस बारे में पता किया और वह बात ठीक भी है और मुझे विश्वास भी है कि वह सड़क जल्दी ही बन जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह बहुत ही तरक्की का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, जाखल से लेकर रतिया तक जो बीस गांव है, वहां पर जब बारिश आती है तो पलड उन गांवों को तबाह कर जाता है। 1993–94 मे भी जाखल गांव के अन्दर मेरे ख्याल से पांच–पांच या छः–छः फुट पानी मण्डी मे चला गया था जिसकी वजह से वहां के लोगों को उस गाव से बाहर बैठना पड़ा था। 1981–82 में चौधरी भजन लाल जी ने वहां सवा करोड़ रुपये खर्च करके रंगोई नाते की खुदाई करने में लगाया था लेकिन अब वह सिर्फ चार किलोमीटर ही बीच में बनने से रह गया है। इस बजह से वहां का पानी आगे नही जाता और टक्कर

मारकर पीछे लौट आता है। मैं मती जी से और मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जमींदारों को और गरीब आदमियों को बचाने के लिए इसका कोई स्थाई प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि वहां के लोग आराम से रह सके। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आप चौहान साहब से कहें कि ये मुझे बार–बार इटरप्ट न करें।

प्रो० छतर सिंह चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी आदमी की नाक कट गयी और वह कहने लगा कि नाक कटने से भगवान दिखाई देते हैं। इस आदमी को देखकर और दो चार आदमियो ने नाक कटवा दी लेकिन उनको भगवान नही दिखाई दिया। फिर एक किसान कहने लगा कि ये तो अपना पंथ बढ़ाते है कैसा भगवान दिखाई देता णै। तो सर, ये भी इसी तरह से अपना पंथ बढ़वाने में लगे हुए है।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्यायट ऑफ आर्डर नही है।

श्री पीर चन्दः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फ्लड से वहां पर जो नुक्सान होता है, तो उसका कोई परमानैन्ट इलाज होना चाहिए (विघ्न) जब फ्लड आता है तो मेरे हल्के में बहुत नुक्सान होता है। मत। जी यहा पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं उन–से निवेदन करना चाहूगा कि मेरे हल्के मे सड़को की. तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे हल्के में एक सड़क तो जाखल बस–स्टैण्ड से लेकर थाने तक की है। उसको ऊंचा

उठाया जाना चाहिए और ऊंचा उठाकर उसको बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से रेलवे स्टेशन से लेकर जाखल गांव तक की सडक को भी बनाया जाना चाहिए। यह सड़क बहुत ही खराब है और रेलवे स्टेशन को जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ होती है (विघ्न) आप लोगों को तो थानों में जाना ही है इसलिए आराम से चरने जाओ तो क्या दिक्कत है? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं (घंटी) सर, घंटी तो कई बार बज चुकी है लेकि न अभी मेरी बात पूरी नही हुई। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा समय और बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके दारा स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के के स्कूलों में मास्टरों की काफी कमी है उस कमी का, मैं समझता हूं, कोई कारण नहीं हो सकता। हमारे उस एरिया के तो मास्टर होते नहीं है। वे हांसी, हिसार के आस–पास के हैं। वे उधर नहीं रहना चाहते। जैसे भी हो सके, सरकार मास्टरों को ट्रांसफर करके भेजे। उनको पूरी सख्ती से वहां भेजना चाहिए। दस जमा दो के जो दो स्कूल बनाए हैं, उनकी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई हैं, उसको परसों चालू किया है। उनमें जो अध्यापकों और कर्मचारियों व प्रोफैसरों की जरूरत है, उन्हें जल्दी वहां भेजा जाए क्योंकि लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। उन्हें फतेहाबाद या टोहाना जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, जाखल पंजाव के बोर्डर से लगता है। उसके कारण जाखल जंक्शन भी बहुत बडा है। चारों तरफ से गाड़ियां चलती हैं। मंडी बहुत बड़ी हैं। गांव बहुत बड़ा है। जाखल के

साथ मेरे हल्के के 20 गांव लगते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर ब्लाक बनाए जाएं। ब्लाक् बनने से इस इलाके के लोगों की कई प्रकार की तकलीफ दूर होगी। गांव–गांव में बी ० डी ० ओ० जाएंगे तो सडको और गलियों पर ध्यान देंगे। मेरा हल्का टोहाना के साथ पड़ता है। टोहाना के मैली जी भी हैं। वे हमारी तरफ पैसा नही देते हैं। अपनी तरफ लगा लेते है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, आप बार–बार घण्टी मार रहे है इसलिए मैं अपनी बात यही पर खत्म करता हू। अन्त में मांगे राम गुप्ता जी ने, जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए आपका करता हूं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ (साल्हावास): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जैसा पीर चन्द जी ने कहा कि यह मांगे राम जी का बजट है। यह बात उनके मुंह से ठीक निकल गई। यह बजट चूल्हे, चक्की, मंगल सूत्र, संदूर यानी घर से बाहर निकला ही नहीं है। बजट से लोगों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को, विद्यार्थियों को उम्मीदें होती है कि बजट से कोई राहत महसूस होगी कुछ कर मुक्त होगा, कुछ मिलेगा लेकिन माने राम जी ने बड़ा डल और ड्राई बजट पेश किया है। पता नही, इन्होंने यह घर बैठकर बनाया है या कटवाल जी की बुआ के साथ बैठकर बनाया है। यह घर से बाहर नहीं निकला हए। सरकार खोखले दावे करती है कि हम किसानों को बिजली देते हैं। पानी

देते है। ये देते है। वो देते हैं। लेकिन देने लेने का कोई प्रावधान नही है। जो डैफिसिट है, उसको हम कुछ कम कर सकते हैं, जो खर्चा है उसको बचा सकते है। डिपार्टमैंट वाईज जो वेस्टेज है, ट्रक, टैक्टर या कारे हैं, उनको समय पर ऑक्शन करके डिस्पोज औफ कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा ? जो कम कीमत पर चीजें जा रही है, अगर वेस्टेज की सही समय पर डिस्पोजल कर दी जाए तो उन से ज्यादा कीमत सरकार को मिल सकती है। ऐसा प्रोवीजन यह हाउस कर सकता है। इस हाउस का यही काम है कि इस तरह की व्यवस्था करना। इस तरह के कानून बनाने का इस हाउस को पूरा हक है ताकि जिससे सरकार की आमदनी बढ़े न कि ट्रांसफर्ज चेंज करवाना, नौकरियो में भर्ती करना, थानों में किसी की पिटाई करवाना। यह काम इस हाउस का नहीं है जोकि यह सरकार करती जा रही है। इस तरह का प्रोवीजन इस हाउस को, सरकार को करना चाहिये ताकि डिपार्टमैंटवाईज जो–जो वेस्टेज है, उसका सही समय पर सदुपयौग किया जा सके और जो डिसपोजल के लिये पुरानी मशीनरी हो, उसका सही समय पर आक्शन करवाकर सरकारी खजाने मे पैसा आ सके। सपोज कीजिये कि एक बस, या ट्रैक्टर खराब हो जाता है। अगर वह गाड़ी दो–चार, पांच लाख किलोमीटर चल गई उसके 200 किलोमीटर और चलने बाकी थे और उसका पम्प खराब हो गया तो उसमे नया पम्प लगवा दिया जाए साथ ही दो टायर लगवा दिये जाएं ताकि उस गाड़ी की कीमत बढ़ जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि गाड़ियाँ फिजूल मे खड़ी रहने से भी खराब हो

जाती है जिसके कारण सरकार को नुक्सान होता है। मेरा मतलब यह है कि जो गाड़ियां खड़ी हैं और वह चालू हालत में थी जिनको समय पर डिस्पोज आफ करने से कुछ मशीनरी बच सकती थी उन्हें डिस्पोज आफ जल्दी करना चाहिए। कुछ आईटम्ज उन की ऐसी भी हो सकती थी, जिनकी सेल में या आक्शन में कीमत बढ़ सकती थी अगर उनकी आक्शन समय पर कर दी जाती। इससे बजट में घाटे को काफी हद तक पूरा किया जा सकता था।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ऐग्रीकल्चर के बारे मे भी कहती गै कि हमने इस क्षेत्र में किसानों को बड़ी सुविधा दी है, राहत दी है। स्प्रिंक्लर सैट्स के बारे में कल ही हाउस में एक क्वैश्चन आया था जिसका जवाब कैटेगरीक्ला देने की बजाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर टाल गये लेकिन सच्चाई यह थी कि इन्होंने स्प्रिंक्लर सैट्स पर सब–सिडी नही दी है। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है क्योंकि मेरे इलाके मे बहुत सारे स्प्रिंक्लर सैट्स लगे हुए है। न ही इन्होंने किसानों को सब–सिडी दी थी और वह पैसा सरण्डर कर दिया। न ही जिस कम्पनी से वह सैट्स खरीदे गये, उन से रेट वगैरह ही तय किया। जो सबसिडी इन्होंने 1993– 94 में दी वह 30.50 लाख रुपये की राशि थी और उसमें केवल 6.9 लाख रुपये ही खर्च हुए और जो मनी सरण्डर हुई, वह थी 24.2 लाख रुपये जोकि सब से ज्यादा है हालांकि उस वक्त बजट में इसके लिये बहुत थोड़ा पैसा रखा गया था। सब–सिडी सरण्डर करने का कारण यह था कि सरकार ने उस कम्पनी से रेट वगैरह फिक्स नहीं किया था और न ही सब–सिडी देने पर ध्यान दिया

और न ही किसानों की मुश्किल की ओर ही ध्यान दिया गया जिस के कारण से किसान स्प्रिंक्लर सैट्स नही ले सके। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूगा कि खाद के रेट्स कितने बढ़ गये है। बजि के रेट्स कितने बढ़ गये है। इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर समय पर किसानों को खाद व बीज मिल जाते, तो उनको काफी फायदा हो सकता था। यह बात तो ठीक है कि पिछले साल की निस्बत खाद ज्यादा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक समय पर नही हुआ। अगर समय पर डी० ए० पी ० तथा यूरिया किसानों को मिल जाती तो जो ब्लैक में यह चीज आई, वह कभी न आती जो अब स्थिति हुई, वह न आती। ब्लैक मार्किटिये बीच में न आते।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से पैस्टीसाईडज का मामला है। दवाईया भी असली नहीं रही हैं। जहर भी अगर किसान को असली न मिले तो उससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अगर किसान कौ अपने खेतो के लिये, अपनी बागवानी के लिये दवाईयां भी असली न मिले और उन नकली दवाईयों का कोई असर भी न हो, तो उस बेचारे किसान के ऊपर क्या गुजरेगी? इसको आप सब भली भाति समझते है। नकली दवाईयों का कोई असर हो ही नही सकता। मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह के जो बलैक–मार्किटिये है, जो नकली दवाईयां बेचते है, उन पर निगाह रख और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे ताकि वे भविष्य मे नकली दवाईयों न बेचें जिससे किसानों के खेतों को फायदा होने की बजाये नुक्सान हो। जहा तक बिजली पानी का

सवाल है, इस बात को सरकार खुद मानती है कि पानी और बिजली में कमी आई है। इस बारे मे सरकार के अपने आकड़े बताते है कि इरीगेटिड एरिया के अन्दर जो बिजाई की गयी, उसके आधार पर यह बात इकनामिक सर्वे आफ हरियाणा में साफ लिखा है:–

"The percentage of net area irrigated to net area sown and gross area irrigated to total area cropped decreased from 76.0 and 77.9 in 1991-92 to 75.3 and 76.4, respectively, in 1992-93."

इसका मतलब यह हुआ कि........।

चौधरी जगदीश नेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, जिले सिंह जी जो फिग्गर्ज तथा तथ्य दे रहे हैं, वह सदन को गुमराह करने वाली बात है। जो बारानी जमीन हैं, वह बारिश पर निर्भर करती है। सिंचाई मैं कोई कमी नही है। जो सिचाई से बिजाई हुई, अगर उसमें बिजाई कम हुई, तो वह सिचाई का कसूर है और यदि बारानी में बिजाई कम हुई, तो वह बारिश का कसूर है। यानि बारिश कम हुई है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: इसमें लिखा है ''नेट इरीगेडिट एरिया''। इसमे बिजाई कम हुई क्योंकि नइरो में पानी नही था और टय़्बवैल्ज के लिए बिजली नहीं थी। दूसरी बात ये कहते है कि एस० वाई० एल० का निर्माण कार्य तथा डब्ल्यू० जे ० सी ० की डी–सिल्टिंग करेंगे और वी ० एम ० एल० मे पानी ज्यादा लाएंगे। लेकिन बजट के अन्दर एस० वाई० एल० के लिए एक पैसा भी नही रखा।

चौधरी जगदीश नेहराः एस० वाई० एल० के लिए 16 करोड़ 60 लाख रुपए बजट में रखें हुए है (शोर)।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः आप यह बात बताएं कि 16 करोड़ रुपए से क्या– क्या करोगे? यह तो हाथी के मुंह मे जीरा देने वाली बात है। मैं बताना चाहता हूं कि इस नहर का निर्माण कार्य बन्द हो गया है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इस वनाए से हरियाणा की लाईफ लाईन का नुक्सान हुआ। इस नहर के निर्माण वाली 34 कम्पनियां ऐसी क्रैश, जिन्होने 2535.23 लाख रुपए का दावा आपके महकमे के ऊपर किया और यह पैसा आपसे लिया। इसके बावजूद आप कहते हैं कि बजट में इसके लिए 16 करोड़ रुपए रखे हैं। इम तरह से हमें 2635 लाख रुपए का नुक्सान हो गया। तो 16 करोड़ रुपए से क्या होगा?

श्री उपाध्यक्षः यह जो पैसा दिया गया है इसका ताल्लुक क्या एस० बाई० एल० से है?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः जी हां, मैं उन कम्पनियों के अलग–अलग नाम बता सकता हूं कि किस–किस कम्पनी ने कितने–कितने पैसे लिए।

चौधरी जगदीश नेहराः ये जो कम्पनियों की बात कर रहे हैं, उनके फैक्ट्स एण्ड फिग्गर्ज इस समय मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि किसी कम्पनी ने काम बन्द कर दिया हो, किसी का कोई डिसप्यूट हो या कुछ केस कोर्ट में पडे हो। यह बात तो उसके बारे में है, जो पंजाब में काम हुआ है। यह मामला

सब–जुडिस है इसलिए इसकी फैक्ट्स एण्ड फिग्गर्ज मैं नहीं दे सकता।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय, 2535 23 लाख रुपए उन कम्पनियो ने ले लिए। इसमें आपकी कोताही रही है। अगर आप ऐमे एग्रीमैंट न करते तो इतना पैसा फिजूल में हमारे एक्सचौकर से न जाता। अगा पैसा पंजाब गवर्नमैंट में भी जमा करवाया तो भी हमारा शेयर गया। इन तथ्यो के आधार पर आप इन–फ्यूचर ऐसै अनुबन्ध किसी कम्पनी से न करें। अगर किसी वजह से कोई काम बन्द हो जाए, तो वह कम्पनी सरकार पर दावे ठोक ठीक कर फिजूल खाते मे काम बन्द कर देगी। वह इस तरह से करोड़ों रुपए बना रहे पै। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहते है कि कुछ नही हुआ। इतना पैसा गया, आपको उसका पता क्यो नहीं? आपको उसका पता होना चाहिए। दो–तीन कम्पनीज हों, तो ठीक है लेकिन ये तो 34 कम्पनीज हैं।

चौधरी जगदीश नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर एक्वाडक्ट बन रहे थे, साईफन बन रहे थे। रेलवे के ब्रिज बन रहे थे। जो नाले नीचे से जा रहे है और ऊपर से जा रहे हैं, उनके एक्वाडक्ट बने है। बहुत से काम बन्द हो गए है। किसी का लिटिगेशन हो गया। किसी को पैसा दे दिया। किसी को देना है। यह मामला सब–जुडिस है। अगर आप कोई स्पैसिफिक बात कहे, तौ हम उसकी इन्क्रवायरी करवा सकते हैं। लेकिन किसी को गलत पैमें की पेमेंट करेंगे, उसकी सम्भावना नही

श्री उपाध्यक्ष: नेहरा साहब, जो वहां पर एग्जीक्यूटिंग एजेंसिज हैं, क्या वे आपके डिपार्टमैंट की हैं?

चौधरी जगदीश नेहरा: नहीं जी।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहना है कि ये किसी कम्पनी के साथ ऐसा कोई अनुबन्ध न करे जिससे स्टेट के एक्सचौकर को नुक्सान हो। इसके अलावा, मेरा सुझाव है कि डब्ल्यू० जे ० सी ० से हमारे रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ नारनौल, रोहतक और सोनीपत जिलों को पानी मिलता है। उस नहर को डी–सिल्ट नहीं किया गया है जो ताजेवाला हैड वर्क्स है, वह कमजोर है। उस नहर की हालत ऐसी है कि जैसे पानी के टब होते है। हमने कमेटी की तरफ से वहां विजिट किया था 1 ताजेवाला हैडवर्क्स पर क्रैकस हुँ। उस नहर का ताजे वाला हैड वर्क्स से ले कर ऐण्ड तक सर्वे किया था। वह नहर सारी ऐसी है, जैसे टापू बने हों। उसमें भैंसे बैठी थीं। झुण्ड उगे हुए थे। मैं कहता हूं कि सरकार उसकी डि–सिल्टिंग करवा करके उसकी कैपेसटी दे बढ़ाए ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाईज किया जा सके। एक दिन में 70 लाख क्यूसिक पानी वेस्ट चला जाता है। बरसात के दिनों में उस पानी को स्टोर करके रोहतक, रिवाडी, महेन्द्रगढ़, नारनौल जिलो की नहरों में छोड़ दिया जाए क्योंकि उन ईलाको के लोगों को पीने का पानी नही मिल रहा है। वहां वाटर टेबल लगभग 100 फुट नीचे चला गया है। कम से कम उनको पीने का पानी तो मिल जाए।

चौधरी जगदीश नेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आफ आर्बर है। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने जो सवाल उठाए, उनका हमने जवाब दिया है। इन्होने कहा कि ताजेवाला हैड वर्क्स टूटा हुआ शै। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हथनी कुण्ड बैराज बनाने के लिए समझौता हुआ है। उस पर डैम बनेंगे। डब्ल्यू० जे ० सी ० जो 16,000 क्यूसिक्स की कैपेसिटी की है, उसको हम 28 हजार क्यूसिक्स की कैपेसिटी की बनाएगे ताकि उस पानी को बैरानी ईलाकों में ले जा सकें और री– चार्जिग कर सकें। लेकिन जो समझौता है, उसी समझौते का ये विरोध कर रहे हैं। उसी के बारे में सुझाव दे रहे है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप सुझाव दे रज्य हैं और आपकी पार्टी उसका विरोध कर रही है, ऐसा क्यों?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः मेरा सुझाव है कि डब्ल्यू० जे ० सी ० की डी सिल्टिग की जाए।

चौधरी जगदीश नेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात हम कह रहे हैं, वही बात ये कह रहे है।

प्रो० सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। अभी नेहरा जी ने प्यायंट आफ आर्डर के बहाने से जमुना एकार्ड का जिक्र कर दिया। जो डी–सिल्टिग की बात है, यह बिल्कुल सैपरेट है। इसकी डी–सिल्टिग पांच स्टेट्स मिल कर करवाएगी। ऐसी बात बिल्कुल नही है। यह स्टेट का अपना सबजेक्ट है और स्टेट की अपनी टैरिटरी है। जमना मे जो गाद है, मिट्टी भरी हुई है उससे वहां आइलैड बने हुए है। उसको आप

रिमूव करे ताकि पानी का फलों ठीक हो। ये जिक्र कर रहे थे कि जमुना का पानी बढ़ जाएगा, हम इस बात को नही मानते। आपने 30 परसैन्ट पानी कम कर दिया और कम करके तीन स्टेट्स को दे दिया। आपने हमारे इंट्रैस्ट को सैकरीफाईस कर दिया। वह ईशू अलग है। यह केवल जमना नहर से गाद निकालनें की बात थी। आप उस बात को टाल कर उसकी आड मैं उस समझौते की बात कर रहे हैं। यदि उसके बारे में डिस्कशन करनी है तो आप दों–चार घण्टे उस बारे मे डिस्कशन कर ले, हम तैयार हैं।

चौधरी जगदीश नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्हों ने ताजेवाला हैड वर्क्स का जिक्र किया कि उसमें करैक्स आए हुए है और कहा कि डब्ल्यू० जे० सी ० की कैपेसिटी बढ़ाए और पानी लगातार मिलना चाहिए। इस बात का जमना अकोर्ड के साथ संबंध है। जो ये उसमें गाद की बात कह रहे हैं, और जो सुझाव दे रहे हैं, उसी सन्दर्भ में मैंने अर्ज किया है।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी जिले सिंह जी, आप अपने हल्के की ही बातें कहे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: मैं अपने हल्के के बारे में ही बात कर रहा हू क्योंकि डब्ल्यू० जे० सी ० मेरे हल्के मे जाती है। इस बारे मे मेरा सरकार से अनु– रोध है कि इन नहरों की सफाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाये ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके और लोगो को पानी पहुंच सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। इन्हों ने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए लेकिन बिजली की

फिर भी हालत खराब है। इन्होंने दिखाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता कि बजट के सप्लीमैंटरी नोट में 205 में कुछ तहसीलो के नाम दिए हैं जैसा कि तहसील दादरी, नारनौल, महेन्द्रगढ़, सब तहसील मातनहेल अण्डर रिवाड़ी, सब तहसील साल्हावास, कोसली अण्डर झझर। यह तो रिवाड़ी मे है। मैं बताना चाहता हू कि यह गलत सूचना दी है। मेरा इलाका रिवाडी के साथ लगता है। वहां पर तो डीप टयूबवैल का अलग रेट है मौर हमारे यहां पर अलग है। इस बारे में मैं बिजली मती जी से कहना चाहता हू कि द्वीप टयुबवैल के हिसाब से जो टैरिफ रखा गया णै वही हर जगह एक जैसा होना चाहिए।

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हू कि साल्हावास के किसानों की संघर्ष समिति पिछले 14 महीने से एजीटेशन चला रही थी। वे कल शाम मुझे मिले थे। अब फैसला हो गया है और बिजली का बिल भी जो लोग दे नही रहे थे, वे भी देना मान गए है। मैं साल्हावास भी गया था। उस समय मैं उनको आश्वासन देकर आया था। उसी दिन मैंने आर्डर कर दिए थे कि इसको ठीक ढंग से एग्जामिन करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय, चलो सिंचाई मती जी ने बता दिया कि इस पर ठीक ढंग से विचार करेगे, तो मैं इस बात को खत्म करता हू। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि इन्होंने कागजों में ही बिजली बढ़ाई है। इन्होंने कुछ कट अनडिकलेयर्ड भी लगा रखा है क्योकि बगैर

सूचना के भी कई जगह। पर 3– 4 घण्टे तक बिजली नही आती। मेरा अनुरोध है कि ऐसे अन डिकलेयर्ड कट्स न लगाए। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जानी चाहिए ताकि बच्चे पढ सकें और लोग अपना अपना काम कर सकें। यह सरकार कहती है कि हरियाणा एक वैल्फेयर स्टेट है। मैं बताना चाहता हू कि तामिलनाडू एक वैल्फेयर स्टेट है। वहा पर किसानों से टयूबवैल चलाने के बिजली के पैसे नही लिए जाते। चाहे वह एक घटा टयूबवैल चलाए या 6 घन्टे चलायें। इसी प्रकार से आन्ध्र प्रदेश एक वैल्फेयर स्टेट है, जहां बिजली की कौस्ट 1. 36 रुपये आने पर भी किसानों से सरकार केवल 15 पैसें ले रही है। तो फिर इस तरह से हरियाणा वैल्फेयर स्टेट कहा हुई? ये कहते है कि हरियाणा दो नम्बर की स्टेट हैं। यदि ये इसी प्रकार से चलते रहे तो हरियाणा 10 नम्बर पर आ जायेगा। मै मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि पानीपत थर्मल प्लांट की उबा यूनिट का उद्घाटन हमने किया था और छठी यूनिट का शिला– न्यास भी किया था। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे समय में कोई काम नही हुआ? यमुनानगर के प्लांट का सारा हिसाव–किताब हमने तैयार किया। हमने 1990 में इस प्रोजैक्ट को तैयार करके एन० टी ० पी ० सी ० को दिया। वे काम न करे तो हम क्या करे?

13.00 बजे

श्री उपाध्यक्षः जिले सिह जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और बिजली मन्त्री जी ने इनको एप्रिशियेट भी किया है। (विध्न) आप अब कन्क्रलूड कीजिए।

चौधरी जिले सिंह जाखडः उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के कनैक्शन के लिए एक सैल्फ फाईनैस स्कीम है। मेरे हल्के के कई लोगों ने सैल्फ फाईनैसं स्कीम के तहत पैसे जमा करवा रखे है। परन्तु उनको कनैक्शन नही दिए गए हैं। सरकार ने पैसा तो ले लिया लेकिन उसका फायदा किसान को नही हुआ और उसे कनैक्शन नही मिला 1 एक केस श्री राम कुमार पुत्र श्री सुरजीत कुमार, नया गांव, का है। उसने 16– 12–91 को 2500 रुपये भरवाये थे क्योंकि उसने केवल कनैक्शन लेना था। उससे पैसा जमा करवा लिया गया लेकिन 18– 12– 1991 को जे० ई० ने उसके कह दिया कि आप इलिजिबल नही है क्योंकि यह टयूबवैल आपके भाई के सांझे खाते में है जबकि

वह प्रिमसिज अलग है और वह अलग है। उसको कनैक्शन देने में अगर कोई हिच थी तो उससे पैसा क्यों भरवाया गया। अगर पैसा भरवाया गया है तो उसको कनैक्शन दिया जाना चाहिए था। करीब पांच साल उसे पैसा जमा करवाए हुए हो गए हैं और उसने फिटिंग भी करवा रखी है लेकिन उसको कनैक्शन आज तक नही मिला। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मार्च के दिनों में किसानों के कनैक्शन काटे जा रहे हैं। मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि सढौरा में भी कनैक्शन काटे जा रहे है। अगर आज मार्च के महीने में किसान के कनैक्शन काटे जाएंगे तो वे बिल आगे कहां

से जमा करवाएंगे। मुख्य मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे समय मे किसानों के कनैक्शन्ज न काटे जाए अगर किसी का कोई बकाया शै, तो दो महीने बाद आ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, सारी की सारी. एक्सप्रैस बसें खरीदी गई हैं। 363 में से एक भी साधा रण बस नही खरीदी गई। इन्होंने खुद माना है कि सारे फलीट में एक बस की कमी हुई है। जो 363 बसें खरीदी गए हैं, वे सारी की सारी एक्सप्रैस खरीदी गई हैं जो कि रोड्ज पर खाली चलती हैं किसी बस में 30 सवारियां होती है और किसी मे 20 सवारियां होती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि सौदा मंहगा हो गया है इसलिए किराया इन्क्रीज कर दिया। इन बसों का 25 परसैंट किराया ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राईवेट ट्रासपोर्टरो को जो परमिट सरकार ने दिए हैं, वे सारे के सारे रो रहे है क्योंकि जो रूट्स इनको मिले हैं, वे वायेबल नही है और सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दिया है लेकिन उनको लम्बे रुट्स नही दिए। ण्क तरफ परमिट्म लेने वाले रो रहे है और दूसरी तरफ सवारियां परेशान है। सरकार ने छोटे–छोटे रुट्स पर से अपनी बसे हटा ली हैं और जब कोई तगड़ी बराह शादी होती है, तो परमिट वाली बसो को बुक कर लेते है और रुट्स पर बसें न मिलने के कारण सवारियां परेशान होती हैं और 10–20 किलोमीटर का सफर पैदल करे या कोई और आल्टरनेटिव ढूंढे। इस– लिए सरकार से मेरा यह सुझाव है कि सरकार ने जो प्राईवेट परमिट्स दिए हैं, उनके रुटस बढ़ा दिए जाएं या उनको ऐसे रूट्स दिए जाएं जहां उन की

डिमांड है ताकि सवारियों को भी परेशानी न हो और प्राईवेट ट्रांसपोर्टर्ज भी घाटे में न चले।

उपाध्यक्ष महोदय, जे ० आर० योजना के तहत 1993–94 में 34.63 लाख मैन डेज थे और 1994– 95 मे 33.29 लाख मैन डेज हैं। 15.35 लाख मैन डेज में से भी 9 महीने में आधे से भी कम मैन डेज कवर हुए है और बाकी के 3 महीनों में बाकी के मैन डेज ये लोग कैसे बना लेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, जौहड़ खोदने के लिए टैरक्टर्ज चलते हैं। पब्लिक हैल्थ में भी डिग्गी खोदने के लिए टैक्टर्ज का प्रयोग किया जा रहा है और कागजों में मैन डेज दिखा दिए जाते हैं इसलिए सरकार असत्य रिपोर्ट न दे और मजदूरो का जो काम है, वह मजदूरों से ही करवाएं और जौहड मजदूरों से ही खुदवाए जाने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में कई जौहड ऐसे खुदवाए गए हैं, जिनकी जरूरत नही हैं क्योंकि सरकार को पता नहीं कि जौहड किस लिए होते है। उपाध्यक्ष महोदय, जौहड इसलिए होते है ताकि बरसात का पौंग इनमें इकट्ठा हो जाए और 2– 4 महीने पशु पानी पी लें लेकिन सरकार पैसा खाते के लिए जौहड पर जौड्ड खुदवा रही है। एक–एक जगह पर ट्रैक्टरो से 5– 5 जौहड खुदवा दिए हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि मैन डेज कागजों पर हैं। असल में नहीं है। इसलिए मैन–डेज को सही इस्तेमाल किया जाए साथ ही इसे बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक इकनोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा में लो कास्ट सैनिटेशन स्कीम का जिक्र है पता नही यह कौन सी

स्कीम है? इसमें 0.50 करोड़ रुपया रूरल सैनिटेशन के लिए दिया गया है। यह पैसा कहां खर्च किया गया है। हमें तो कहीं नजर नहीं आया। गांवों की सैनिटेशन के लिए वहुत थोड़ा पैसा सरकार ने रखा है। सड्कों पर कुरडियां पड़ी रहती हैं। महिलाओं, माताओं–बहनों को बाहर जाने के लिए बहुत तंगी है। वे बेचारी बार–बार उठती हैं। बार–बार बैठती हैं। सरकार को उनके लिए कोई अरेन्जमैन्ट करना चाहिए। इस बारे में मेरा सुझाव है कि 2–2, 4– 4 एकड़ जमीन गांव के आस–पास छोड़ दी जाए और उसकी चारदिवारी करवा दें। वहां पर कम्यूनिटी लैट्रिन्ज कामयाब नहीं है क्योंकि शहरों में जहां वाटर सप्लाई है और सफाई वाले भी रहते हैं ये लैट्रिन्ज वहां पर भी वायेबल नही हैं तो फिर गांवों में तो इस किस्म की व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में जहां नकल रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने कुछ नही किया। जो बिल्डिंग लोग आपने आप बनाते हैं, उन स्कूलों को भी अपग्रेड नहीं करते। गुप्ता जी, मैने पिछले बजट पर अपने भाषण में कहा था कि मेरे हल्के में गरोहड गांव में एक ऐसी बढ़िया बिल्डिंग है, जो शायद हरियाणा में रिकार्ड है कि ऐसी बढ़िया बिल्डिंग कही नहीं है। यह बिल्डिंग लोगों ने अपने पैसे से 25 लाख रुपये का चन्दा लगा कर बनाई कुए जिसमें एक हाल और 24 कमरे है। उपाध्यक्ष महोदय,

इस स्कूल को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इसको लड़कियो के लिए 10 जमा 2 के स्कूल में अपग्रेड कर दें ताकि इलाके की लड़कियां ही इसमें पढ़ लें। शहरों मे तो गुप्ता जी, सरकार पहले खुद स्कूल की बिल्डिंग बनाती है और वे अपग्रेड भी हो जाते हैं लेकिन इस के लिए बिल्डिंग होने के बावजूद इसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः जिले सिंह जी, आप वाइंड–अप कीजिए।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः उपाध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहता हूं कि इन्होंने 1994– 95 में 3 गांवों में 110 लीटर प्रति व्यक्ति और 1995– 96 मे 170 लीटर गांव में' पानी देने का सुझाव है। इसमें भिवानी, रोहतक और रिवाड़ी आते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्राईवेट कनैक्शन भी दिए हैं। मैं भी एक मैम्बर हूं और मैंने भी एप्लाई किया हुआ है लेकिन मुझे कनैक्शन नही दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी ये कनैक्शन दें वहां वाटर वकर्स की कपैसिटी भी बढ़ाए। उपाध्यक्ष महोदय, टेल पर पानी नही हैं और नलके सूखे पड़े हुए है। वहां पर वाटर सप्लाई की बहुत ही भारी कमी है। कागजों पर तो लोग बहुत ही अच्छा पानी पी रहे हैं लेकिन असल में वहां पर पानी नही है। मेरी इनसे गुजारिश है कि ये टेल पर पानी पहुंचाएं और केपैसिटी भी बढ़ाए। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूगा। उपाध्यक्ष महोदय, झज्जर तहसील रोहतक मे है। यहां पर सड़कें नाम माल की हैं और जो हैं भी, वह ठीक नहीं हैं। उनमें 6 फुट गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और पिछले तीन सालों से वहां पर सड़को का कोई

भी काम नही हुआ है। दूसरे यहां पर एक सैनिक स्कूल के लिए भजन लाल जी ने एक पत्थर लगाया था। उसका भी कुछ नहीं हुआ है।

चौधरी धर्मबीर गाबाः उपाध्यक्ष महोदय, हमने इन्हें पांच लाख रुपया दिया है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः उपाध्यक्ष महोदय, हमें नही पता कि वह कौन ले गया है और इन्होंने किसको दिया है? एक सड़क साल्हावास से खानपुर तक है। जब हम दादूपुर से विलोटा के तरफ आते हैं, तो पता चलता है कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट आ गया है। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि जहां पर सड्कों की जरूरत है, वहां पर सड़कें बनवाएं और जो टूटी पड़ी हैं, उनकी रिपेयर करवाएं।

श्री उपाध्यक्षः जिले सिंह जी, अब आप बैठ जाएं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ओल्ड एज पैन्शन, विडोज पैन्शन और हैंडीकैप्ड पैन्शन के बारे मे पूछना चाहता हूं कि जब से यानि कि जिस तारीख को कोई हैन्डीकैप्ड हुआ एं या कोई विधवा हुई है, उसको उसी तारीख से पैन्शन दी जाएगी या नही? उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी की बात है। गवर्नर साहब को करनाल के अन्दर आना था। वहां पर फैसला किया गया कि गवर्नर साहब और मुख्य मंडी के अलावा किसी की गाडी अन्दर नही जाएगी। वहां पर मंत्रियों की और एम० एल० एज० की गाड़ियां बाहर खड़ा रही। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों का प्रोटोकोल में 14वां नम्बर, एम० एल० ए ० का 22वां नम्बर और

चीफ सैक्रेटरी का 24वां नम्बर होता है। जव चीफ सैक्रेटरी की गाड़ी आई तो वह सीधी अन्दर चली गई। तो वहां पर एक ए० एस० पी ० ने कहा कि सर, गांडी उधर ले जाएं। डी ० सी ० ने कहा कि इनको आने दो और जब पूछा गया कि किम ने गाड़ी को रोका था तो बताया गया कि ''This Stupid Fellow'' अगर इस तरह ब्युरोक्रैट्म द्रारा कर्मचारियों, अधिकारियों और आई० पी ० एस० की बेइज्जती की जाती है तो यह बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी जगदीश नेहरा: आन ए प्यायट आफ आर्डर। सर, जो यह वात कही गयी 'है इसका तो कोई आधार नहीं है। जो आदमी इस हाउस में न हो और वह यहां पर अपनी बात को स्पष्ट न कर सकता हो तो ऐसे आदमियों के 'खिलाफ ऐलीगेशन नहीं लगाना चाहिए। इनकी यह बात अच्छी नहीं शै।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, कित्ती का नाम नही लिया है मैंने तो चीफ सैक्रेटरी की पोस्ट के मारे में कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजमत खां।

श्री अजमत खां (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें तो बजट के बारे में कहना चाहूगा। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि पता नही क्यों आपकी निगाहें उस साईड

में ही ज्यादा रहती है। हमारी साईड में तो आपकी निगाहें आती ही नहीं। हमारी तरफ भी आपकी निगाहें आनी चाहिए। आप रिकार्ड उठाकर देख लें कि कितनी कम बार तो हमें टाईम मिलता है? कितनी बार उस साईड के लोगों को टाईम मिलता है और हमारी तरफ से भी बोलने वाले को कितना समय बोलने के लिए मिलता है, यह आप देख लें। अगर हमारी तरफ आपकी निगाह नही जा सकती, तो आप हमारी सीट ही इधर से बदलवा दीजिए और ऐसी जगह हमें सीट दे दें जहां पर आपकी निगाहें चली जाएं।

श्री उपाध्यक्षः अजमत खा जी, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब आपका बोलने का वक्त आता है तभी आप हाऊस से खिसक जाते हैं।

श्री अजमत खांः सर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि कई बार ऐसा हो जाता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले चार साल हो गए आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। मैंने अपने जो सवालात दिए थे, या तो वे डिस अलाउ हो गए हैं या फिर वे लास्ट में आए जिसकी वजह से मुझे अपने सवालात पूछने का समय ही नहीं मिला। सर, मुझे इस सब का अफसोस होता है। मैं यपने इलाके की कई बातें यहां पर लेकर आता हूं। लेकिन मुझे उन बातों को सदन के पटल पर रखने की इजाजत नहीं दी जाती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्साफ हर आदमी को मिलना चाहिए। मेरा आपसे एक अनुरोध है। मेरी आवाज इन्साफ की आवाज है और मेरी मांग है कि मैं अपने जो

भी सवालात यहां पर उठाना चाहता हूं उनके लिए मुझे समय नही दिया जाता जोकि दिया जाना जाहिए। जो एक एम० एन० ए० बनकर आता है, अगर उसको साल मे एक या आधा घण्टा ही बोलने के लिए मिलेगा तो वह कैसे इतने समय में अपनी बात बोल सकता है? एक एम० एल० ए ० के कितने प्रिविलेज होने हैं, कितना उस पर पैसा खर्चा होता है। अग्र वह सब हिसाब लगाया जाए तो एक एम० एल० ए ० की एक दिन की तनख्वाह चालीस हजार रुपये जाकर बैठती है। एक एम० एल० ए ० को अपने इलाके की बातों को कहने का तो वक्त मिलना ही चाहिए। अपनी बातों को कहने का तो उसका हक है। उसका प्रिविलेज है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज कर रहा हू कि--

''अपने भी मुझसे खफा, बेगाने भी नाखुश,
मैं जहरे हलाहल को, कभी कह न सका कन्द''

सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हू कि हाउस के अन्दर बेजा बातों के लिए बहुत समय बर्बाद होता है। आप हमारे हकों के कस्टोडियन है। इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसलिए आपको यह सब देखना चाहिए। यहां पुर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन कभी भी काम की बातें यहां पर नहीं होती हैं। आपका हाउस की मर्यादा को मेनटेन करने का फर्ज बनता है। कौन सा ऐसा वक्त रहा है और कौन सा ऐसा आदमी है, जो दूध का धुला है और किस आदमी के समय में ज्यादती नही हुई है? ज्यादती तो बाऔकात हालात सै होती हैं, बाऔकात जानबूझकर होती हैं लेकिन कोई भी वक्त ऐसा नहीं रहा है, जिसमें ये ज्यादती न हुई

हों। अगर उन ज्यादतियों को सरकार बेनकाब करे, तो अच्छी बात हैं। लेकिन अगर उनको छिपाने की बात हो, तो वह गलत बात है। लैकिन ज्यादती तो हमेशा छिपायी ही गयी है। सर, हर दौर में ये ज्यादती। हुई है। इसलिए मैं अपोजीशन के लोडर्ज सै भी और अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसी बातों पर समय बर्बाद न करें।

सर, अब मैं अपने इलाके की बातें कहना चाहता हूं क्योंकि कही बाद में ऐसा न हो जाए कि आपकी घंटी बज जाए। मैं पहले एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चर के लिए पानी की जरूरत है और पानी या तो जमीन से आएगा या फिर नहरों से आएगा। बदकिस्मती से हमारा इलाका, फरीदाबाद, महेन्द्र– गढ़ और रिवाड़ी, जिधर से नहरे आती हैं, के लास्ट में जाकर पड़ता है। लेकिन अब उनके लिए पानी का इन्तजाम कैसे हो? बरसात के दिनों में हमारे यहां यमुना रिवर में काफी पानी होता है। यह पानी गुड़गांव कैनाल से हमारे एरिये में पहुंचाया जा सकता है। 1978 में जो ड्रेनैज सिस्टम आउट लेट के लिए बनाया गया था, उसके बाद वह आज तक काम नहीं आया है। वहां ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है। मेरा आपसे अनुरोध शै कि बरसात के दिनों में हुमारे इलाके की ड्रेन्ज को भर दिया जाए जो कि गुड़गांव कैनाल से भरी जा सकती है। इस पर केवल ज्यादा से वादा 10 लाख रुपये की लागत आएगी। ड्रैनों के बीच में जगह–जगह पर बांध लगा दिए जाने चाहिए। इन बाधों के लग जापे से वह पानी रूक जाएगा और जो पानी उन्ही ड्रैनों के जरिए

यमुना में जाकर गिरता है, वह पानी हमारे इलाकों में रहेगा जिससे फसलों की सिचाई हो सकेगी और पानी का वाटर लेवल भी ऊपर रहेगा तथा मेवात के इलाके का 80 प्रतिशत रकबा काश्त भी हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मेरी अर्ज है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये की लागत आएगी इसलिये इसे कर दिया जाए। 1980 में मलाई फीडर के नाम से एक फीडर बनाई गई थी। आज वहां के अफसरान जाकर देखें कि वहां कितना काम हुआ है? किसी ने देखने की जरूरत महसूस नही की। कितना पैसा उस पर लगा है? उसके बावजूद एक बून्द पानी भी आज तक उससे नही आया। क्यों वह पैसा बेकार लगाया गया और क्यों लोगो की जमीन ऐक्वायर की गई? आज उस जमीन पर लोगो ने नाजायज कब्जे कर लिए। वाटर स्टोरेज के लिए जो जमीन खोदी गई थी, लोगों ने उस पर मिट्टी डालकर उन्हें जोहड़ों में तबदील कर लिया 1 कोई अफसर आज देखने के लिए नहीं जाता कि क्यों और किस परपज के लिए यह बनाई गई थी। ड्रैनें जो है, उनको भी लोगों ने जोहड़ो में शामिल कर लिया। उनकी सफाई तक नही होती। मलाई ड्रेन को लोगों ने खोदकर जोहडों में शामिल कर लिया और मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से एक बार किसी चीज को बनाकर फेंक देना और उस पर पैसा वेस्ट करना जिस परपज के लिए वह बनाई गई है, उस परपज का पूरा न होना, क्या यह ठीक है? मेरी आपसे अर्ज है कि मेवात के इलाके के लिए सबसे बेहतर सिस्टम यह है कि बरसात में ड्रेनज

को भर दिया जाए, जगह जगह बांध लगा दिए जाए। इससे इतना पानी उसमें हो जाएगा कि पानी ऊपर आएगा और वह मीठा पानी होगा और ऐसा होने से ऐग्रीकल्चर की उपज भी बढ़ेगी। खाद, बीज सब सरकार देती है। इसमें कोई दो राय नही है लेकिन अफसरान डिले करते हैं। जब जरूरत होती है, उस वक्त बीज नही मिलता, जब जरूरत होती है, खाद नही मिलता। वही खाद दस दिन के बाद आता है। वही बीज एक महीने के बाद आता है और कभी तो उस बीज को खाद के साथ जबरदस्ती देते हैं, क्योंकि बीज लेट आया और फिर किसान को जबरदस्ती देने की बात शुरू हुई। जो भीं काम करने पैं, होते तो वे हैं, लेकिन अगर टाईम पर हों, तो अच्छा रहता है। एग्रीकल्चर जो हरियाणा की है, वह हरियाणा की ही नही बल्कि देश की रीढ़ की हड्डी है। हरियाणा ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। जितनी हम सोचते हैं, उससे कही ज्यादा पैदावार हो जाती है और यह सब सरकार की कोशिशों की बदौलत है। सरकार अच्छे बीज, खाद और पानी की सहूलियते देकर किसान को प्रोत्साहन देती है। लेकिन अफसरान की लापरवाही से सरकार की बदनामी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क के साथ–साथ सफेदे के पेड लगे हुए हैं। अगर किसान उन पेड़ों को काटता है, तो सजा होती है, मुकदमे बनते हैं। अगर नही काटता तो उसके 10 एकड़ रकबे में फसल नही होती। जिन किसानों के खेत सड़क के किनारे हैं, उन्हे बहुत नुक्सान होता है सरकार या तो इन किसानों को मुआवजा दे या यह पेड कटवाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक उटावड माइनर है। यह 1972 मे बनी है। आज तक उसका रैवेन्यू देख ले कि कितना आया है। लास्ट टेल पर पानी कभी नही जाता। जो हमारा एरिया पड़ता है, वहां हमारे जाति–भाई आते हैं और पुलिस के जरिए पानी ले जाते हैं। इससे हमारी बदनामी होती है। नहर 33 किलोमीटर तक बनी है। उसके लिए अफसरान ने कहा है कि इस से 33 कि० मी ० नहर नही चल सकती। 68 बुर्जी तक हम यहा से दूसरी लाईन निकाल सकते हैं वह स्कीम यहां आई पड़ी है। यह स्कीम डेढ़ करोड़ रुपये की है। उससे हम इस परेशानी सै बच सकते है। यह लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम है। उसका बैंक नीचे है। पीछे से पानी आता है जब बिजली गई तो उसका पानी उल्टा लौट जाता है। टेल ऊंचा है और हैड नीचा है। अगर उसके हैड को ऊंचा करना है, तो उसका बैक ऊंचा करना पड़ेगा जिससे बिजली जाने की वजह से पानी वापस नही लौटे। मेरे हल्के में एक–दों गाव को छोड्कर, बाकी गांवों मे पानी नही पहुंचता। उटाबड माईनर के बारे मे मेरी आपसे अर्ज है कि इसके लिए मैं 1988 से कोशिश कर रहा हू। इस बार 80 बुर्जी तक पानी पहुंचा है। इस पानी को रैगुलर पहुंचाया जाए जिससे पीने के पानी का मसला हल हो और खेती के लिए भी पानी मिले।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब एग्रो कल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के मुताल्लिक बात कहना चाहता हूं। पलवल में एक मार्किट कमेटी है और हथीन मे सब–यार्ड है। सिर्फ हथीन एक ऐसी जगह है, जहा पर मार्किट कमेटी नही है। हम हर साल 12–16 लाख रुपये

का रैवेन्यू सरकार को देते है जबकि सिर्फ दो महीने सीजन चलता है। मार्किट कमेटी के लिये प्लाट्स भी अलाट हो गये है लेकिन वहां पर लोग कंस्ट्रक्शन नही कर रहे। वे प्लाट्स या तो कैसिल किए जाएं या वहा पर कंस्ट्रक्शन करवाई जाए। दूसरी बात यह है कि उस मंडी को सारा साल चालू रखवाया जाए ताकि आमदनी बढ़े और यह बात तभी होगी जब हथीन को सब–यार्ड की बजाये पूरी मार्किट कमेटी का दर्जा दिया जाएगा। यह काम बहुत ही जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि हथीन के अन्दर एक बस–स्टैण्ड भी होना चाहिये। इस के लिये जननि एक्वायर हो चुकी है और पैसे भी दे दिये गये हैं। सिर्फ चार दीवारी बननी है। इस ओर सरकार ध्यान दे। अफसरों ने यह कह दिया कि साहब, हमने कुछ रूट्स प्राईवेट लोगो को दे दिये है। केवल पांच रूटों पर पांच बसें ही दी हैं। लेकिन साथ–साथ सरकारी बसे भी चलेंगी। वहां पर हमारा सैन्टर है। तहसील है और अगर खुदा ने चाहा कि कभी पलवल जिला बन गया तो हमारा हथीन भी सब–डिवी–जन होगा। इसलिये वहां पर बस–अड्डा बनना बहुत जरूरी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां पर एक हस्पताल है और वहां पर छोटी–छोटी डिसपैसरिया छोटे–छोटे गांव में होनी बहुत जरूरी है जी० यू० डी ० और जी ० ए ० डी ०। जी ० यू ० डी ० डिसपैसरी तो बराये नाम ही है। जी ० ए ० डी ० है। सौध में हमे एक भी जी ० यू ० डी ० और जी ० ए० डी ० डिसपैसरी नही मिली है। 17 हजार की

आबादी वाला गांव है और वहां से एक डिसपैसरी को उठा लिया गया है। वह शायद इसलिये किया गया कि होडल में एक सी ० एच० सी ० बन गई और वहा सै वह कोई 3–4 किलोमीटर के फासले पर है। बड़े गांव मे जी ० यू ० डी ० तो जरूर ही खोली जाए और साथ–साथ डंगरों के हस्पताल भी हर पटवार हल्के मे बनाए जाए। यह सही है कि भजन लाल सरकार आने के बाद मेवात ऐरिया मे बहुत डिवैल्पमैंट के काम हुए हैं जिससे मेवात ऐरिया को काफी फायदा हुआ है। जहां पहले कोई काम नही हो सकते थे, कहां पर डिवैल्पमैंट के काम हुए। स्क्ल बने, सड़कें बनी। पानी के बहुत काम हुए और दूसरे डिवैल्पमैंट के काम भी हुए। लेकिन एक बात गल्त हो गई कि मेवात बोर्ड का जो दफतर एं, वह गुड़गाव मे ही रहने दिया गया। यह ठीक नही है। गुड़गांव में दफतर रहने से अफसरो को फायदा हो सकता है, उनको टैलीफोन का फायदा हो सकता है। उनको टी ० ए०/डी ० ए ० का फायदा हो सकता है लेकिन आम आदमी की जरुरत के बारे मे उन अफसरों को कोई ध्यान नही है। आम लोगो की गुड़गांव में दफतर होने सै जरूरतें पूरी नही हो सकती। इसलिये यह दफतर नूह में ही रखा जाए, तो बेहतर होगा। उन अफसरों को चाहिये कि वे आम लोगों को जरूरतों को नजदीक मे देखे और यह तभी हो सकता है, जब यह दफतर गुड़गांव में न होकर नूंह में होगा। दूसरा हुमारे इलाके के कोई मुलाजिम उस दफतर में नही है। सारे बाहर के हैं। हर काम को गुड़गांव मे जाकर करवाना, यह अच्छा नही होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी एक यह गुजारिश है कि जो पैसा डिवैल्पमैंट के कामों पर लगाया जाए, उस पैसे की हमें भी जानकारीं होनी चाहिये। उस पैसे के बारे मे अफसर हमे भी बताए कि हम फला डिवैल्पमैंट के कामो के लिये यह–यह पैसा खर्च कर रहे है। इससे ऐसा होगा कि हमें मेवात बोर्ड के काम से वाकफियत रहेगी कि यह–यह काम बोर्ड ने करवाए है और यह–यह काम स्टेट के बजट से हुआ डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजुकेशन पर दो–एक बाते करना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, एजुकेशन किसी भी इलाके, किसी भी कौम, किसी मुल्क के लिये काफी बुनियादी हैसियत रखती है। जिस कौम को आगे जाना होता है वह एजुकेशन लेती है और जिस कौम को पिछड़ना होता हैं, उससे एजुकेशन छीन ली जाती है। प्राईवेट स्कूल्ज मेवात के इलाके मे हर जगह पर है। इस एजुकेशन के बारे में, सरकार नैं बहुत कुछ किया है। इस बात को मैं क्या कहूं? सरकारी आकड़े कहते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ ऐसी प्रोबलम्ज हैं, जिनका हल किये बगैर मेवात का आदमी एजुकेशन नही पा सकेगा। अगर एक इलाके को, एक कौम को एजुकेशन से वंचित रखा गया, तो वह कौम, वह इलाका दुनियां की दौड़ से पीछे रह जाएगा और आने वाली नसलें, जिनके पास कमाने के साधन नही होगे, पढ़े लिखे नही होगे, जमीनें नहीं होंगी, वे भटक जाएंगी। ऐसे लोगों को सम्भालना हमारे लिये मुश्किल हो जाएगा। वे लोग समाज के अन्दर रहकर जुल्म करेंगे। बुराईया करेंगे। गन्दे रास्ते पर चलेंगे, डकैती करेंगे और इस तरह से वे लोग समाज के ऊपर

एक तरह से कलंक सा बन कर रह जाएंगे और ऐसे लोग समाज के वातावरण को दूषित करते रहेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि हर नौजवान को एजुकेशन दी जाए। अब एजुकेशन के बाद बात आती है नौकरियों की। नौकरियां तो तब मिलेंगी, जब हर आदमी एजुकेटिड होगा। इसी तरह से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिये 10+ 2 के स्कूलों की भी जरूरत है। मेरे इलाके मे केवल एक ही स्कूल जे० बी. ० टी. ० का है। एक 10+2 का स्कूल 10– 15 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन हमारे अपने दोस्तो के यहां शहरों में प्राइवेट स्कुल हैं, जिनमे उनके बच्चे पढ्ने के लिए आते है। देहात के बच्चे 15–15 किलोमीटर से साईकल पर, बस पर लटक कर या ट्रैक्टरों पर आते है और उनका आने–जाने में बहुत टाईम खराब हो जाता है। कई बार उनके एक्सी डैंट्स भी हो जाते हैं। आप एजुकेशन को देहात मे लाएं। आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल देहातों में खोलें। इससे उन लड़कों का भला होगा। ऐसा करने से गरीब आदमी ऊपर उठ सकेंगे। हमारे यहां दस–जमा–दो के स्कूल मेवात के कस्बों के अलावा बड़े गांवों मे नही हैं। फिरोजपुर झिरका, नूह औरे तावडु के कस्बों मे तो दस जमा दो के स्कूल हैं, लेकिन देहातों मैं नही है। हमारे यहां 62 हाई स्कूलो में से 49 हाई स्कूलों में हैड मास्टर भी नही हैं और सब्जैक्ट टीचर भी नही है। सिर्फ 13 स्कूलों में हैड मास्टर हे और वे स्कूल भी शहरों मै हैं। तो आप ही बताए कि हैड मास्टर और सब्जैक्ट टीचर के बिना काम कैसे चलेगा? इस वजह से जिस बच्चे का साल खराब हो गया, वह कहां जाएगा? आपके बच्चे तो शहरों मे

पढ़ते हैं और उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। असल पता तो तब चले, जब शहर के बच्चों के मुकाबिले में देहाती बच्चे निकल कर आएं। यह तभी सभव होगा जब देहातों में जगह–जगह स्कूल खोले जाएंगे। किसी वक्त में शहरो और देहातों में एक जैसो पढ़ाई थी, लेकिन आज देहात से पढ़ाई निकल गई। इस वजह से आज शहरों के बच्चों की ही ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है और उन्हीं को अच्छी नौकरियां मिलती है। देहात से शिक्षा को निकालने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा यहां पर बिजली के बारे में भी बात की जाती है। यह कहना कि हमारे यहां बिजली नही है, यह गलत बात है। मैं कहता हूं कि पहले के मुकाबिले में बिजली का उत्पादन बढ़ा है तथा इसे और बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले चार–पांच सालों मे बिजली की पैदावार और बढ़ेगी। फिजूल में शोर मचा कर हाउस का समय बर्बाद करना, कोई अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को सच्चाई कहनी चाहिए। (घण्टी) डिप्टी स्पीकर साहब, थोड़ा समय और दें। मैं आपके हुकम को मानूगा। मैं अर्ज कर रहा था कि जो बिजली के बारे में कहा जाता है, वह सिर्फ सियासी प्रौपेगन्डे के लिए कहा जाता है और अपना फायदा उठाने के लिए कहा जाता है। अगर बिजली कहीं एक दिन में खरीदी जाती या कोयले की तरह से रेल में लाई जाती तो मसला हल हो सकता था। लेकिन बिजली तो पैदा की जाएगी, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए पावर के लिय जो सरकार ने काम किया है, वह सराहनीय है। मैं

समझता हूं कि इस बारे में जो कुछ हो रहा है, वह ठीक ही हो रहा है और मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। एक बात यहां पर विकास की आती है। ये मेरे भाई हैं और मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। इन्होंने लोगों को राजी करने के लिए पैन्शन दे दी और कर्जा माफ किया गया। कर्जा माफ करने के बारे में इन्होंने बहुत पहले शोर मचा दिया इसलिए लोगों ने कर्जा वापिस करने से इन्कार कर दिया। उस वजह से उस कर्जे का ब्याज बढ गया। पैन्शन के लिए सब ने हाथ फैलाए। आज यह आदत सी बन गई है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, वह 100 रुपए लेने के लिए हाथ फैलाता है। इसमें एक बात जरूर है कि कुछ जैनुईन लोग इससे वंचित रह गए हैं। पता नहीं, किस वजह है रह गए हैं? इसके अलावा हम एक बात को मानते हैं कि डिवैल्पमैंट के जो काम हैं, उसको कोई तजुर्बेकार आदमी ही कर सकता है। आप देखें कि हरियाणा में कितने डिवैल्पमैंट के काम हुए है। हर गांव मे पक्की गलियां हैं। स्कूलों के कमरे बने हुए हैं। हर गांव को पक्की सड्कों से जोड़ा गया है। यानी समा प्रकार की सुविधाएं लोगो को दो गई हैं। ये डिवैल्पमैंट के काम तमो होते है, जब कोई पैसा इकट्ठा करने वाला हो और उस पैसे का ठीक इस्तेमाल करना जानता हो। आदमी को पैसा लेने का भी और उसको खर्च करने का भो तरी का आना चाहिए। हमारे नेता ने पैसा इकट्ठा करने के बारे में भी सीखा और उसको खर्च करने के बारे में भी सीखा। यही कारण है कि प्रान्त में जगह–जगह डिवैल्पमैंट के काम हो रहे है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय केवल 4 मिनट के लिये बढ़ा लिया जाए।

आवाजें: जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: हाउस का समय 4 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अजमत खां: स्पीकर साहब, अब मैं आगरा कैनाल के बारे में कहना चाहूंगा। हुमारे फरीदाबाद जिले का आगरा कैनाल के साथ जिन्दगी और मौत का सवाल है। उस कैनाल का कंट्रोल यू ० पी ० सरकार के पास है। उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे भी हैं। हमारे आदमी ही, वह नाजायज कब्जे कर रहे है। हमने ही उनका रैवेन्यू नहीं दिया है। यह बात सही है लेकिन वह रैवेन्यू इसलिए हम से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वे हमे पानी नही देते हैं। मैं कहता हू कि सरकार इस मसले को हाई लैवल पर बहुत तेजी के साथ उठाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सी ० एम० साहब से अर्थ करूंगा कि जिस तरह से आपने जमुना नदी के पानी का फैसला करवा दिया तथा और भी बहुत से फैसले करवाए हैं, उसी तरह से आप यह मसला भी हल करवाएं। क्या आगरा कैनाल का फैसला नही हो सकता? आप उसका फैसला करवा करके उसका कंट्रोल अपने हाथ मे ले लें। हमें यू० पी ० वाले पूरा पानी नही देते है। आप उस कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। हमारे लिए यह काफी होगा। इसी से हमारी

जिन्दगी बन जाएगी। आप यू समझें कि आगरा कैनाल हमारे इलाके के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है। अगर आपने उसका कोई हल नहीं करवाया और इस मसले को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो पता नही यह मसला कब तक यू ही लटका रहेगा ? हमें बार–बार यह कहा आता है कि इस मसले को हल कर रहे है। हमे तो डिसिप्लिन का डर लगता है, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। अगर हम इन–डिसिप्लिन्ड हो गए, तो हम अपने हिस्से का पानी उनसे जरूर ले लेंगे। लेकिन हम चाहते है कि आप उस पानी को ले लें। पानी हमारी हद में से जाता है। हमारे सामने से जा रहा है। हमारे श्वेत तरस रहे है। हमारे बच्चे तरस रहे हैं। मेरी आपसे अर्ज है कि अगर आप पानी नही ले पाए, तो हो सकता है हम अपने हिस्से का पूरा पानी लेने पर मजबूर हो जाए'। इसलिए मेरी अर्ज है कि आप इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट पेश किया गया है, यह बहुत अच्छा है। भाई जिस आदमी को जिससे कुछ सेना ही नही, देना ही देना है उसे अच्छा ही कहा जाता है। लोगों से लिया कुछ नहीं, उनको दिया ही दिया है। उन पर कोई बोझ नही लादा है, इसलिए यह बजट बहुत शानदार है। डिप्टी स्पीकर साहब, डिवैल्पमैट के कामों के लिए जो पैसा रखा गया है, उसके लिए मैं सरकार और वित्त मनी को बधाई देता हूं कि जो पैसा डिवैल्पमैंट के कामों के लिए रखा गया है, वह ठीक है। किसी देश प्रदेश के लिए डिवैल्पमैंट भी बुनियादी बात है। आखिर मे मैं अपने हल्के

की सड्कों के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के मे एक–एक दो–दो किलोमीटर की सड़कें बननी रह गई हैं, उनको बनाया जाए। वे सड़कें इसलिए रह गई क्योंकि जिस वक्त वे बनाई गईं, उस समय 1974 मे फलड का जमाना था। इसलिए 1974 में 15–15 और 20–20 किलोमीटर का फर्क पड़ा। एक सड़क है, स्यापणकी से बिरोहपुर राजपूत। यह दो किलोमीटर का टुकड़ा बनना है इसके न बनने से लोगों को 25 किलोमीटर पा चक्कर काट कर आना–जाना पड़ता है। इसी तरह से सिहा से मरोली गांव की सड़क दो किलोमीटर बननी है। उसके न बनने से लोगों को 27 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना जाना पड़ता है। मेरे हल्के में एक गुमरेड़ा गांव है। वह आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। आज तक उस गांव की पक्की सड़क नहीं बनी है जबकि सरकर की यह पालिसी है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। मेरे हल्के में गुमरेड़ा गांव और टोंगा गांव ऐसे गांव हैं, जो सड़क से नही जोड़े गए हें। इसी तरह से रिणावा खुर्द से पोट तक की सड़क है। आरीदेव से नाटोला की सड़क है। था इका से निनाणा तक की सड़क है। लोहाणा से सोहरी तक की सड़क है। इन गांवों की सड्कों को बनाया जाए। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिन सड्कों की मुरम्मत करवाई है और जिन सड्कों को बनवाया है, वह बहुत अच्छी हैं। सड्कों की बहुत अच्छी मुरम्मत करवाई है। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के की मैंने जो छोटी–छोटी सड्कों के बारे में कहा है, उनको जरूर बनवाएं। ये सारी सड़कें मार्किट कमेटी को

जाती हैं। यदि मार्किट कमेटी उनको बनाना मान ले तो वे सारी सड़कें बन सकती हैं। जो तरक्की का दरवाजा खुला हुआ है, वह हमेशा खुला रहेगा। यह बंद नही होगा। उन सड्कों को बनाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, ताकि लोगों को सहूलियत हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अजमत खां जो, जब आपने अपनी स्पीच शुरू की, तो बीच में आपने एक बात कहो कि आप द्वारा दिए हुए सवाल लगते नहा हैं, या लगते हैं तो बहुत पीछे लगते हैं। किसका सवाल लगा, किसका नही लगा, आगे लग गया या पीछे लग गया। उसका एक सैट प्रोसैस है, सैट प्रोसीजर है। इसमें किसी की कोई कोशिश नहीं कि किसी सदस्य का सवाल पीछे लगे और न ही ऐसी कोशिश की कोई किसी की नीयत है।

श्री अजमत खां: डिप्टी स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि अगर मैं गलती पर हूं तो मैं अपनी गलती मानता हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आप कम से कम पिछले चार साल का रिकार्ड निकाल कर देख लें, मेरी कहां और क्या गलती हो गई?

Mr. Deputy Speaker : Now the House stands adjourned till 2.00 p m. on Monday the 20th March. 1995.

***13.34 hrs.**

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Monday the 20th March, 1995)